फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 216 प्रभात जयपुर, बुधवार 11 मार्च, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

Chocolate Syrup Soda And Other Curatives

Pharmacists once used chocolate syrup to mask the bitter flavour of their remedies, and make a little money on the side

The Mare - An Evil Spirit!

Before Gold

What is particularly striking is Klimt's attention to the sitter's gaze. The girl does not confront the viewer directly; her eyes drift slightly aside...

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में तख्ता पलट का पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का

ईरान में अमेरिका ने तख्ता पलट की दूसरी बार कार्यवाही की है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने अमेरिकी शक्ति के बारे में एक असहज सवाल फिर से उठा दिया है: क्या बाहर से थोपे गए शासन परिवर्तन कभी स्थायी स्थिरता पैदा कर पाते हैं? एक सदी से भी अधिक समय से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन सरकारों को गिराने के लिए बार-बार सैन्य बल या गुप्त अभियानों का इस्तेमाल किया है, जो उसे शत्रुतापूर्ण या असुविधाजनक लगती हैं। इसके परिणाम एक चेतावनी देने वाली कहानी बताते हैं, हालांकि कुछ हस्तक्षेपों ने अस्थायी व्यवस्था बनाई, लेकिन कई ने अस्थिरता, संघर्ष और भू-राजनीतिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जो उन शासनकालों से कहीं अधिक समय तक चली, जिन्हें हटाया गया था।

- पहली बार 1953 में हस्तक्षेप किया था, जब ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जो अमेरिका को पसंद नहीं आया था। तब अमेरिका ने मोसादेघ का तख्ता पलट कर शाह रज़ा पहलावी के नेतृत्व में राजतंत्र स्थापित किया। जनता के अमेरिकी विरोध, शाह की तानाशाही के कारण 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान इस्लामिक गणराज्य बन गया।
- इस्लामिक गणराज्य ईरान हमेशा से अमेरिका विरोधी था। लम्बे समय तक धमकी देने के बाद अन्ततोगत्वा अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया।
- इस तरह के हस्तक्षेप की शुरुआत अमेरिका ने 1893 में हवाई में की और वहां की क्वीन लिली को सत्ता से अपदस्थ कर अपनी मनपसंद सरकार बनाई तथा 1959 में हवाई को अमेरिका का 50 वां राज्य घोषित कर दिया।
- इसी प्रकार अमेरिका ने कई देशों, ग्वाटेमाला, क्यूबा, चिली, डोमनिशियन रिपब्लिक, ग्रेनेडा, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया में सैन्य कार्यवाही कर तख्ता पलट करवाए। कहीं तो ये तख्ता पलट जनता को और उस देश को रास आए पर अधिकांश देशों में जनता की मुश्किलें ही बढ़ीं।

सबसे प्रारंभिक उदाहरण 1893 का है, जब हवाई में अमेरिकी व्यापार हितों ने अमेरिकी कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के साथ क्वीन लिली योकलानी की सरकार को उखाड़ फेंका। राजतंत्र को एक अस्थायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसने अंततः 1898 में हवाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिला लिया। लंबे समय में, यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया और 1959 में इसे 50वां अमेरिकी राज्य स्वीकार कर लिया गया, हालांकि इसकी सरकार उखाड़े जाने को ऐतिहासिक रूप से विवादित माना जाता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पदीय कर्तव्य में कार्यवाही की हो, तो बिन मंजूरी मुकदमा नहीं करें

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों के तहत कोई कार्रवाई की है तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले में

- हाईकोर्ट ने जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश रद्द किया।

याचिकाकर्ता की ओर से लिए प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर ने यह आदेश जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी राजीव दत्ता की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता विजय शर्मा ने मार्च, 2002 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि सुबह लगभग पांच दर्जन लोग उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या अमेरिका के हथियार भंडार खाली होने लगे हैं?

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार हमले के पहले दो दिन में ही अमेरिका 5.6 बिलियन डॉलर के हथियार ईरान पर सैन्य कार्यवाही में खर्च कर चुका था

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। क्या ईरान युद्ध तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका के हथियारों के भंडार खत्म कर रहा है? वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में सैन्य अभियान शुरू होने के मात्र पहले 48 घंटों में ही अमेरिका लगभग 5.6 अरब डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है। यह अनुमान उस रिपोर्ट पर आधारित हैं, जो अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत की गई थी। ये अनुमान अमेरिकी सरकार के इस दावे से काफी अलग हैं कि ईरान मिशन से अमेरिका की "सैन्य तैयारियों में तेजी से कमी नहीं आ रही है।"

- वॉशिंगटन पोस्ट का यह दावा अमेरिका की कांग्रेस में प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर आधारित है। यह रिपोर्ट सरकार के दावों से मेल नहीं खाती। ट्रंप सरकार का दावा है कि ईरान मिशन से अमेरिका के हथियारों का जखीरा कम नहीं होगा।
- हाल ही में अमेरिका ने ईरान में 5000 लक्ष्यों पर बमबारी की, 50 जहाज नष्ट किए। ईरान के कई सरकारी कार्यालय व प्रतिष्ठानों पर भी हमले किए गए। इसमें अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरण व हथियार तैनात इस्तेमाल किए हैं।
- संभावना है कि वाइट हाउस इस सप्ताह पूरक रक्षा बजट की मांग कर सकता है जो काफी बड़ा होगा।
- इसी के साथ यह संभावना भी है कि अमेरिका व इज़रायल अब लेज़र निर्देशित बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हाल के दिनों में अमेरिका ने ईरान में 5000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है और 50 से अधिक जहाजों को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा ईरान की सरकार के मुख्यालय, खुफिया ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका ने कई तरह की सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया है, जिनमें बी-1 बमवर्षक, बी-2 स्टेल्थ बमवर्षक और बी-52 बमवर्षक शामिल हैं। इसके अलावा, लूकस ड्रोन, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम और थाड एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जैसे सिस्टम भी इस्तेमाल किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार, इस अभियान में शामिल लड़ाकू विमानों में एफ-15, एफ-16, एफ-18, एफ-22 और एफ-35 स्टेल्थ फाइटर शामिल हैं। इनके साथ ए-10 अटैक जेट और ईए-18जी इलेक्ट्रॉनिक अटैक विमान भी तैनात किए गए हैं। ई-2डी एडवांस्ड हॉकआई विमान और हवाई संचार रिले प्लेटफॉर्म भी तैनात किए गए हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने स्पीकर बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया

स्पीकर बिड़ला पर खुला पक्षपात करने का आरोप तो है ही साथ ही उन पर कांग्रेस सदस्यों को लेकर झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया गया है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 मार्च। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष-समर्थित एक प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है, जिसमें अध्यक्ष ओम बिड़ला को पद से हटाने की मांग की गई है।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के भी सदन की कार्यवाही में प्रमुख मुद्दा बनने की संभावना है। विपक्ष ईरान के मुद्दे पर भारत की स्थिति, और भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर अमेरिका द्वारा दी गई छूट सहित, कई विषयों पर सरकार की आलोचना कर सकता है।

एक और मुद्दा, जो सदन में उठ सकता है, वह है चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। खबरों के

- बजट सत्र के दूसरे भाग के एजेंडा में हालांकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा ही एक मात्र कार्यक्रम है, लेकिन ईरान युद्ध और उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, बंगाल में एसआईआर जैसे मुद्दे भी सदन में उठाए जाएंगे।

अनुसार, इस प्रक्रिया के अन्तर्गत लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस मामले को लेकर संसद में तीखी बहस होने की संभावना है।

कई विपक्षी नेताओं ने ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उनका आरोप है कि अध्यक्ष ने सदन में स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ गलत दावे किए, जब उन्होंने लोकसभा में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का उल्लेख किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का जवाब देने के लिए सदन में उपस्थित न हों।

नोटिस दिए जाने के बाद, ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस मामले पर फैसला होने के बाद ही वे सदन में आएंगे।

अविश्वास प्रस्ताव के अलावा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र राज्यपाल की शपथ ली

मुंबई, 10 मार्च। महाराष्ट्र के नवनियुक्त राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल पद की शपथ ली। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने लोकभवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें पद और

- वे महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल हैं।

गोपनीयता की शपथ दिलाई।

लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। वे महाराष्ट्र के 22 वें राज्यपाल बने हैं। लोकभवन में शपथ विधि कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत से हुई तथा समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति में बराबर का हक मिले'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका एक ही तरीका है यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुझाव दिया कि संपत्ति के अधिकारों में मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता लागू की जाए।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हालांकि सावधानी बरतते हुए कहा कि अदालत जल्दबाज़ी कर मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहती। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शरीयत के प्रावधानों को हटाने से मुस्लिम महिलाओं को 1925 के भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत अधिकार मिल सकेंगे।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है और इस पर अंतिम निर्णय संसद और सरकार को ही लेना होगा। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, जो मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं देते।

इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा

- सुप्रीम कोर्ट ने यह बात एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए कही। मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर इस रिट याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को उन प्रावधानों को चुनौती दी गई, जो महिलाओं को पुरुषों के समान संपत्ति का हक नहीं देते हैं।
- चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने माना कि शरीयत को हटा दिया तो कानूनी शून्य उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार का कोई अन्य कानून नहीं है।
- कोर्ट ने कहा, इस समस्या का समाधान यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही हो सकता है। पर इसका क्रियान्वयन संसद का विशेषाधिकार है।

न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति बागची ने एक पुराने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ को संविधान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। याचिकाकर्ता कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, जो चाहती हैं कि कानून में उन्हें पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिले।

पीठ का मानना था कि अगर शरीयत को हटा दिया जाता है, तो कानूनी खालीपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार के लिए कोई दूसरा कानून मौजूद नहीं है।

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि उत्तराधिकार का कानून एक नागरिक अधिकार है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं माना जा सकता। उन्होंने तीन तलाक मामले में अदालत के उस फैसले का उदाहरण दिया, जिसमें इसे असंवैधानिक घोषित किया गया था।

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। जब पीठ ने पूछा कि शरीयत के तहत उत्तराधिकार के प्रावधान को खत्म करने के बाद वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था क्या हो सकती है, तो प्रशांत भूषण ने याचिका में संशोधन करने पर सहमति जताई। इसके बाद अदालत ने आगे की सुनवाई स्थगित कर दी।

राज्यपाल बागडे आईसीयू में भर्ती

जयपुर, 10 मार्च । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे को आज एसएमएस हॉस्पिटल के मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया है। राज्यपाल आज अपनी रूटीन जांच करवाने दोपहर करीब 1 बजे एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे थे। यहां अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनको भर्ती कर लिया।

एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल ब्लड समेत

- रुटीन जांच के लिए एसएमएस अस्पताल गये। वहाँ घबराहट के बाद बुखार आ गया, जिसके बाद उन्हें मेडिकल आईसीयू में भर्ती किया गया।

अन्य रूटीन इंवेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। यहां जांच के दौरान घबराहट होने के बाद उनको बुखार आ गया, जिसके बाद उनको मेडिकल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंद हो सकते हैं कई होटलों और रैस्त्रां के किचन

अगर एलपीजी गैस की आपूर्ति जल्दी ही व्यवस्थित नहीं हुई तो

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 मार्च। देश में शहरी रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक, हॉस्पिटैलिटी सैक्टर अब एक अप्रत्याशित संकट का सामना कर रहा है। एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण रेस्तरां और होटलों का रोज़मर्रा का कामकाज प्रभावित होने लगा है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों में रेस्तरां मालिकों का कहना है कि स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही है। कई जगहों पर व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति या तो देर से हो रही है या कई दिनों तक उपलब्ध ही नहीं हो रही है।

उद्योग संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर यह समस्या जारी रही, तो इससे पूरे हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम पर असर पड़ सकता है, छोटे मोहल्लों के खाने के ठिकानों से लेकर बड़े रेस्तरां तक। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया और अन्य उद्योग संगठनों का कहना है कि यह क्षेत्र खाना पकाने वाली गैस के बिना काम ही नहीं कर सकता। कई अन्य उद्योगों के विपरीत, जो आपूर्ति में रुकावट के दौरान भी काम जारी रख सकते हैं, रेस्तरां लगभग पूरी तरह एलपीजी पर ही निर्भर रहते हैं। गैस के बिना रसोई बंद हो जाती है, सेवा रुक जाती है और कारोबार को हर घंटे रैवेन्यू का नुकसान होता है।

रेस्तरां संगठनों के शुरुआती अनुमान के अनुसार, बड़े शहरों में 10 से 20 प्रतिशत प्रतिष्ठान पहले ही इस समस्या से प्रभावित हो चुके हैं। कुछ को अपने काम के घंटे घटाने पड़े हैं, कुछ ने मेनू में कमी कर दी है, जबकि कुछ को अस्थायी रूप से सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। छोटे भोजनालय, जो बहुत कम मुनाफे पर चलते हैं, उनके लिए कुछ दिनों का भी काम बंद होना भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि जल्द ही आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो

- ईरान संकट ने देश के पैट्रोलियम व एलपीजी सैक्टर में भारी कमी पैदा कर दी है, जिससे सबसे भारी संकट हॉस्पिटैलिटी सैक्टर के समक्ष उत्पन्न हो गया है।
- भारी मंदी से उबर कर धीरे -धीरे रफ्तार पकड़ रहा होटल उद्योग एक बार फिर मंदी की ओर अग्रसर हो सकता है। इस उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि हालात बिगड़ें इससे पहले हस्तक्षेप करे। सरकार हॉस्पिटैलिटी सैक्टर के लिए कॉमर्शियल एलपीजी की न्यूनतम आपूर्ति सुनिश्चित करे तभी इस उद्योग को बचाया जा सकता है।
- हॉस्पिटैलिटी सैक्टर ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे रखा है, अगर यह सैक्टर प्रभावित हुआ तो बेरोजगारी में भी भारी वृद्धि हो सकती है। साथ ही देश की जीडीपी भी प्रभावित हो सकती है।

कुछ ही दिनों में बड़े पैमाने पर रेस्तरां बंद होने की नौबत आ सकती है।

इस कमी का तत्काल कारण भारत की सीमाओं से काफी दूर दिखाई देता है। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को प्रभावित करने लगा है, जिसमें खाड़ी देशों से आने वाली एलपीजी की आपूर्ति भी शामिल है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आयात करता है, और इसका अधिकतर हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट से होकर आता है। इस समुद्री मार्ग में किसी भी तरह की रुकावट या सिक्यूरिटी रिस्क बढ़ने से टैंकरों की आवाजाही धीमी हो सकती है, माल ढुलाई और बीमा लागत बढ़ सकती है और भारत जैसे आयात करने वाले देशों में एलपीजी की उपलब्धता कम हो सकती है।

सप्लाई में रुकावट की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने कथित तौर पर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य घरों में गैस की कमी को रोकना है, लेकिन इसका एक अनपेक्षित परिणाम यह हुआ है कि रेस्तरां, होटल और केटरिंग इकाइयों जैसे व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ गया है। चूंकि रेस्तरां बड़े व्यावसायिक सिलेंडरों पर ही निर्भर रहते हैं और रोज बड़ी संख्या में उनका उपयोग करते हैं, इसलिए सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट से काम रुक सकता है।

इसका असर केवल रेस्तरां मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, रसोइये, वेटर, डिलीवरी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और सप्लायर, जिनमें से कई लोग रोज़ की मजदूरी या कम मासिक आय पर निर्भर होते हैं। यदि बड़ी संख्या में रेस्तरां बंद होते हैं, चाहे अस्थायी रूप से ही क्यों न हों, तो इससे शहरों में हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

इस संकट का एक व्यापक आर्थिक पहलू भी है। हॉस्पिटैलिटी इण्डस्ट्री अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे गंभीर झटके से उबर पायी है। कई प्रतिष्ठान अब भी उस समय लिए गए कर्ज चुका रहे हैं और साथ ही बढ़ते किराए, खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों और बढ़ते श्रम खर्च का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

जयपुर, 10 मार्च। विधानसभा का बजट सत्र 24 दिन तक चलने के बाद, विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

सत्र के अंतिम दिन नगरपालिका संशोधन बिल पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे बजट सत्र की

- स्पीकर देवनानी ने कहा कि बजट सत्र में कुल 24 दिन विधानसभा की कार्यवाही चली।

समीक्षा प्रस्तुत की। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि बजट सत्र के दौरान कुल 24 दिन तक विधानसभा की कार्यवाही संचालित हुई, जिसमें विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर भी बहस हुई। सत्र की समाप्ति पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अध्यक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की।

विचार बिन्दु

जिसमे दया नहीं उसमे कोई सद्‌गुण नहीं। –हज़रत मोहम्मद

राजनीति में सार्वजनिक और निजी नैतिकता के सवाल

देश में राजनेताओं और प्रशासन तंत्र के अधिकारियों में नैतिक गिरावट आज के समय की सबसे गंभीर चिंता बन चुकी है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नेता और प्रशासक कितने ईमानदार, जिम्मेदार और नैतिक मूल्यों का पालन करने वाले हैं। जब राजनीति और प्रशासन में नैतिकता कमजोर होने लगती है, तब उसका सीधा असर समाज, शासन और जनता के विश्वास पर पड़ता है, जिसे हम आज स्पष्ट देख रहे हैं। इससे जनता भी अनैतिकता के बहाव में बहने लगती है। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम मानना अब इतिहास के पन्नों में चला गया है। वह ज़माना दंतकथा जैसा लगने लगा है जब नेता और प्रशासनिक अधिकारी देश और समाज के हित के लिए अपने निजी स्वार्थों का त्याग कर देते थे। स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दौर में कई ऐसे नेता और प्रशासनिक अधिकारी हुए जिन्होंने नैतिकता, ईमानदारी और त्याग को अपने काम का मूल आधार माना। लेकिन समय के साथ-साथ राजनीति और प्रशासनिक तंत्र का स्वरूप बदलता चला गया और इसमें सत्ता, धन और व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति बढ़ती गई। इस पर अलग-अलग राय हो सकती है कि राजनेताओं ने प्रशासन को भ्रष्ट किया या प्रशासनिक अहलकारों ने राजनेताओं को खराब किया। अब तो राजनीति में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य जनसेवा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करना और उससे मिलने वाले लाभ उठाना बन गया है। चुनावों में भारी मात्रा में धन खर्च इसीलिए किया जाता है; जाति, धर्म और क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने के उद्यम होते हैं। इस प्रकार की राजनीति में नैतिक मूल्यों की उपेक्षा होती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक धन खर्च करके सत्ता में आता है, तो वह सत्ता में आने के बाद उस धन को वापस पाने या और अधिक लाभ कमाने की कोशिश करेगा ही। प्रशासनिक तंत्र में भी नैतिकता की गिरावट सबको दिख रही है। प्रशासन का मुख्य काम कानून की पालना करवाना और समस्त जनता कोसमान रूप से निष्पक्ष सेवाएं देना होता है। लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर या व्यक्तिगत लाभ के लिए अधिकारियों का कर्तव्यों से समझौता करना आम हो चला है। नैतिकता में आई गिरावट के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख है राजनीति का व्यवसायीकरण। नए डिजिटल प्रचार के युग में बाजार की घुसपैठ जीवन के हर क्षेत्र में हो गई है। राजनीति अब सेवा नहीं रह गई है, बल्कि लोगों के लिए करियर और कमाई का साधन बन गई है। दूसरा कारण है चुनावी व्यवस्था में धन, बाहुबल और कट्टर वैचारिकी का बढ़ता प्रभाव। तीसरा कारण है वृहद समाज में नैतिक मूल्यों का कमजोर होना और सत्ता प्राप्त करने की अंधी दौड़। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतंत्र की कमी भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार योग्य और ईमानदार लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, जबकि प्रभावशाली या धनवान प्राथमिकता पा जाते हैं। इससे राजनीति में अच्छे और नैतिक लोगों की भागीदारी कम होती चली गई है। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता की गिरावट का सबसे बड़ा नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। और जब भ्रष्टाचार बढ़ता है और समाज में असमानता और असंतोष बढ़ने लगता है और लोगों का अपने नेताओं और अधिकारियों पर भरोसा टूटता है, तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

सार्वजनिक नैतिकता,या कहें कि नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के नैतिक स्तर में गिरावट काफी हद तक सरकारी काम के बड़े पैमाने पर फैलाव और सत्ता के केन्द्रीयकरण की वजह से भी है। इस व्यवस्था में हर स्तर के फैसले मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारियों की मर्ज़ी से होते हैं। इससे सरकार में बैठे लोगों को अपनी ताकत के इस्तेमाल में मनमानी करने का अवसर मिल जाता है। ऐसी व्यवस्था ने राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों का तो मूल्य बढ़ा दिया है, मगर निजी और सार्वजनिक नैतिकताओं के मानदंडों को संकुचित कर दिया है। ऐसे माहौल में राजनेताओं के लिये नारे लगाना और बड़े दावे करना सामान्य हो गया है। कोई नेता हर साल लाखों नई नौकरियों का वादा कर देता है, हालांकि उसे पता है उसके पास उस संख्या के एक-चौथाई लोगों को भी काम देने का कोई तरीका नहीं है। नेताओं ने यह भी जान लिया है कि वे जो वादे वे चुनावों में जनता से करते हैं जनता उनसे उनका कभी हिसाब नहीं मांगेगी। जनता के हाथ में अपने वोट के अलावा कोई ताकत नहीं है। चुनावों में भी उनकी पसंद बहुत सीमित होती है। सारे फैसले राजनैतिक दल करते हैं। बुद्धिजीवी भी इस बात पर रोशनी डालने में नाकाम हैं कि आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ऐसी क्यों होती चली गई है? प्रशासन कें राजनीतिकरण के तर्क को समझने में बहुत ज़्यादा समय लग गया है। उदारवादी मूल्यों के लिए समर्पित पुराने नेता आज़ादी की लड़ाई की देन थे, जबकि उनके बाद आने वाले लोग सत्ता की लड़ाई में लगे हुए रहे, जो आज चरम पर है। वे सभी जो मज़लूमों के हितों की मुखर आवाज़ें उठाने के लिये भुजाएं उठाते थे वे भी सत्ता के लालच में बिगड़ते चले गए और लोकतान्त्रिक व्यवस्था मजबूत होने के बजाय आजादी के पहले की परंपरागत सामंती छाया में सुकून पाती रही। सवाल उठाया जा सकता है कि राजनेता जैसे हैं, वैसे क्यों हैं? यह जानने के लिए कभी गंभीरता से बुद्धिजीवियों ने विचार ही नहीं किया। इस पर भी नहीं कि राजनीतिक प्रक्रिया गंदे लोगों को कैसे या क्यों ऊपर उठा लाती है। समाज की भूमिका और उसके सामान्य सरोकारों पर कभी गंभीर चर्चा नहीं होती। समाज और उसे चलाने वाले धर्म के नेता भी वर्तमान में बिगड़ैल राजनेताओं की होड करने में लगे नज़र आते हैं। मगर सभी बुराइयों का दोष राजनेताओं पर डालदेना इस मुद्दे से बचना है। होशियार छात्र या प्रोफेसर जो घर पर कम सैलरी वाली नौकरी के बजाय विदेश में आरामदायक नौकरी पसंद करते है, भरपूर प्रैक्टिस करने वाले वकील और डॉक्टर अक्सर अपनी आय छिपाने में नहीं हिचकिचाते, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव जो पागलों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे पाने की कोशिश करते हैं, व्यापारी जो जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है और सही कनेक्शन वाला आदमी सब सेवाएं पा जाता है मगर कमजोर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं के लिए लाइन में लगा रह जाता है। यह भी कैसी नैतिकता है। समाज के सभी हैसियतदार लोग क्या विधानमंडलों में बैठे अपने प्रतिनिधियों जितने ही नैतिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं? सच तो यह है कि राजनेता उसी भ्रष्ट सामाजिक माहौल में बढ़ते हैं जिसमें दूसरे समूह फलते-फूलते हैं। बस सबकी चाहतें अलग-अलग होती हैं। लोकतान्त्रिक राजनीति की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी है, प्रचलित रुझानों को फॉलो करना, मौजूदा बकवास को दोहराना, लोकप्रियता और पब्लिसिटी के लालच में पड़ना है। यह भुला दिया जाता है कि नारे लगाने वाली आवाज़ें कितनी भी ज़्यादा और ज़ोरदार क्यों न हों बकवास बकवास ही रहती है। इसलिए, अगर आजकल के मीडिया बकवास से भरे हों, अगर राजनेता आखिरी मिनट में राजनीतिक वफादारी बदल लेते हों और अगर नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के फायदे के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताये जाते हो, तब आन आदमी निराश होकर अपने हाथ खड़े न करे तो क्या करे। वर्तमान में बदले की भावना वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति है। किसी राजनेता से इससे बचने की उम्मीद किसी को नहीं रही है। राजनेता ज़्यादातर सिर्फ़ असहमत होने पर ही सहमत होते हैं।

> **जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनाने के प्रयास जरूरी है।**

चालाक नेता जनता की राय को अपने फ़ायदे के हिसाब से मैनिपुलेट करना साध चुके हैं। गंभीर मुद्दों को मीडिया के जरिये आसान लगते हुए बना दिया जाना भी इसी मैनिपुलेशन का हिस्सा है। प्राइवेट नैतिकता में एक बड़े झूठ और आधे सच में बहुत फ़र्क होता है। मगर सार्वजनिक नैतिकता में दोनों के बीच की दूरी अक्सर गायब रहती है। सिर्फ़ वही लोग बड़े झूठ का सहारा नहीं लेते जो पहले से ही ऊंचे राजनीतिक पद पर हैं, जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, वे भी ऐसा ही करते हैं। मीडिया देश में अफ़रा-तफ़री का माहौल का आभास देता हुआ सॉफ्ट ऑप्शन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। सब राजनेता जान गए हैं कि हार्ड ऑप्शन वोट खींचने वाले नहीं होते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है उसी प्रकार नैतिकता की इस समस्या का समाधान भी संभव है। सबसे पहले समाज को बदलना पड़ेगा। उसे पुराने सामंती चोले से बाहर निकालना होगा। ऐसे चुनावी सुधारों करने होंगे जिससे राजनीति में धन और अपराध का प्रभाव कम किया जा सके। प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ानी होगी। सूचना का अधिकार, डिजिटल प्रशासन और स्वतंत्र जांच संस्थाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ-साथ समाज में नैतिक शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। जब नागरिक जागरूक होंगे और बेईमान नेताओं को चुनौती देंगे, तभी राजनीति की दिशा बदल सकेगी। राजनीति और प्रशासन में नैतिकता किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है और यदि नैतिकता कमजोर पड़ती है तो शासन व्यवस्था भी कमजोर हो जाती है। इसे ठीक से समझने वाले विवेकशील नागरिक बनाने के प्रयास जरूरी है। आवश्यक है कि नेता, प्रशासक और नागरिक सभी मिलकर ईमानदारी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को मजबूत करें, ताकि एक स्वस्थ और सशक्त लोकतंत्र का निर्माण हो सके।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

भारत-अमरीका ट्रेड डील : सार्वभौम देश के राष्ट्रीय हित

रामनिवास बैरवा

यूरोपियन यूनियन के साथ हुए व्यवसायिक समझौते के बाद संयुक्त राज्य अमरीका से अपरिपक्व अन्तरिम व्यापारिक समझौते का सरकारी स्तर और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा इस तरह से प्रचार किया गया जैसे अमरीका को जीत लिया हो। व्यापारी और पैसे के हिसाब-किताब में पक्का अमरीका अन्तिम समझौते को किस रूप में सामने लायेगा। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि उस अन्तिम समझौते में भारत अमरीका की शर्तों को मानकर भारत के राष्ट्रीय हितों की हिफाजत कर पायेगा या नहीं। कही फजीहत नहीं हो जाये? इसे आगे देखना बाकी है।

2019 में प्रकाशित मेरी पुस्तक "अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का साम्राज्य" में मैंनें यह उल्लेख किय था कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर और 'स्टर्लिंग एरिया' के माध्यम से भारत की सम्पति को ब्रिटेन में ले जाया गया था और भारत के व्यापारिक लाभ को लंदन के बैंकों में जमा करवाया गया था। आज संयुक्त राज्य अमरीका अपनी मुद्रा डॉलर के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग अपनी औपनिवेशिक व्यवस्था बना चुका है। बहुप्रचारित वर्तमान व्यापार समझौता उसी का एक रूप है- जिसमें कृषि की बात को लेकर भारत सरकार के दो बड़े मंत्री, इस समझौते के शिल्पकार वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर अनभिज्ञता बता चुके हैं कि क्या शर्तें है।

इस प्रकार की अनभिज्ञता कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1935 में ही भारतीय राजनेताओं की अविश्वसनीयता को रेखांकित कर चुकी थी जो आज भी भारत की सार्वभौमिकता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर सवाल खड़े करती है। इसका कारण भी रहा है- 1947 के पहले पूरे आन्दोलन में सिर्फ दो ही व्यक्ति भगत सिंह और डॉ. भीमराव अम्बेडकर ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा रखी थी। इनके अलावा कोई भी ऐसा राजनेता नहीं था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा पेश की हो।

यही कारण है कि 1947 के बाद के वर्षों में न तो इंगलैंड और न ही अमरीका ने भारत में आर्थिक निवेश किया था और ना ही औद्योगिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया। यूरोपीय देश और जापान युद्ध में तबाही से उबर कर अपने-अपने पुनर्निमाण में लगे थे। वहीं दूसरी तरफ गल्फ, मध्य पूर्व के लगभग सभी इस्लामिक देशों ने कभी भी भारत पर विश्वास नहीं किया। केवल कूटनीतिक और रणनीतिक कारणों से उन्होंने भारत का समर्थन किया है निवेश कभी नहीं किया। ऐसे में शीत युद्ध की बाध्यताओं के चलते सोवियत संघ ने आर्थिक और तकनीकी मदद देकर भारत में भारी उद्योगों की नींव रखी थी। इस प्रकार के सरकारी उद्योगों और उद्योगों के सरकारीकरण को राष्ट्रीयकरण बताकर समाजवाद का नाम दिया गया। 1991 के बाद, सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद खुली प्रतियोगिता के नाम पर बिना औद्योगिकरण के विदेशी वित्तीय पूंजी के आयात/निवेश को विकास का मापदंड बता दिया गया। इससे शेयर बाजार में पूंजी लगाना और मुद्रा स्फीति तथा महंगाई बढ़ने पर पूंजी को वापस निकाल लेना बड़े पूंजीवादी साम्राज्यवाद देशों का नया पूंजी निर्माण तथा वित्तीय साम्राज्य के विस्तार का आधार बन गया। बिना औद्योगिक विकास के चीन जैसे देश का मुकाबला करना भारत जैसे देश में अविश्वसनीय राजनेताओं के अधीन सम्भव नहीं है। अत: अमरीका ने अपनी चिरपरिचित नीति के तहत नेताओं को कई तरह के लालच देकर अपने पक्ष में कहना और खुली अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता के दरवाजे बंद करके अपनी ही शर्तों पर व्यापार करने के लिए बाध्य करना अमरीकी पूंजीवाद की साधारण रणनीति है।

वर्तमान ट्रेड समझौते के अनुसार, अगले पांच वर्षों में अमरीका के साथ व्यापार को 500 बिलियन डॉलन यानि कि 50 हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर ले जाना है जो कि आज केवल पांच हजार करोड़ डॉलर के स्तर पर है। जाहिर है इतना अधिक व्यापार सामान्य वस्तुओं के व्यापार से सम्भव नहीं है। इसमें तीन क्षेत्रों के व्यापार में अमरीकी एकाधिकार का तत्व छिपा है, और भारत को पूर्णत: अमरीका के आर्थिक उपनिवेश में बदलने की रणनीति है। इसके तहत, सैन्य साजो-सामान पूरी तरह से खरीदा जायेगा, रूस से खरीद पर प्रतिबंध लगाये जायेंगे। रूस और ईरान से खरीदे जाने वाले पेट्रोलियम के बदले अमरीकी कम्पनियों के माध्यम से वेनेजुएला का पेट्रोलियम लेने की बाध्यता का खुलेआम ऐलान कर ही दिया गया है।

बाकी बचा कृषि क्षेत्र। 2021-22 में सरकार द्वारा बनाये गये तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के अपमान का बदला लेने का रास्ता वाया अमरीका अपनाया गया है। कभी लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीका के पी.एल. (पब्लिक लॉ) 480 के तहत गेंहू लेना बंद करके भारत में हरित क्रान्ति और स्वेत (दूध) क्रांति के परिणामस्वरूप आज भारत खाद्यान तथा डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर है। इन्हीं दो क्षेत्रों पर साइलेंट आक्रमण की योजना कथित अमरीकी ट्रेड डील में छिपी है।

उल्लेखनीय है कि 2 अप्रेल, 2025 से पहले भारतीय सामानों पर अमरीकी टैरिफ एम.एन.एफ. दर 3 प्रतिशत थी। इससे अमरीका के साथ-साथ भारत का व्यापार बचत में था-यानि कि सरप्लस था। इस पर ट्रम्प ने अपनी संदिग्ध अपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के मालों पर 50 प्रतिशत की दर का डर दिखाकर बाद में 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया। अब कथित ट्रेड डील में इसे 18 प्रतिशत किया गया है। साथ ही उक्त ट्रेड डील के प्रस्ताव के साथ ट्रम्प ने एक इक्जीक्यूटिव आदेश निकाल दिया है, जिसके अनुसार, भारत को जो महत्वपूर्ण कदम उठाने है, वे है- भारत रूस से सीधे या इनडायरेक्टली पेट्रोलियम खरीदना बंद करेगा (भारत यह तेल रूपये में खरीदता हैं), भारत अमरीका से उर्जा संसाधन तथा रक्षा सहयोग के लिए पाबंद होगा। छिपे तौर पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 50 प्रतिशत ही रहेगा, ऑटो-कॉम्पोनेंटस पर यह टैरिफ 25 प्रतिशत ही रहेगा। खेती के उत्पादन अमरीकी सामान, जैसे लाल ज्वार, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट्स पर रियायतें भारत बहुत दिया भतें पहले ही घोषित कर चुका है। अब, कपास तथा डेयरी उत्पादों के आयात से भारत के कपास उत्पादन और डेयरी उत्पादों की आत्मनिर्भरता प्रभावित होगी। बीच-बीच में यह भी खबरें आई थी कि अमरीका डेयरी उत्पादन उन गायों से प्राप्त होता है जिन्हें गायों के एनीमल फीड में मांस मिलाकर दिया जाता है, जिससे ज्यादा दूध का दोहन हो सके।

वास्तव में अगले पांच वर्षों में भारत 500 बिलियन डॉलर के व्यापार के लिए क्या-क्या खरीद लेगा और उनका उपयोग कहां करेगा? यह प्रश्न आत्मनिर्भर भारत, विश्वगुरू बनने में, तथा 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में कितनी सहायक होगी, यह भविष्य ही बतायेगा।

उक्त कथित अंतरिम समझौते को लेकर अखबारों में छपी भारतीय प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार थी- "मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करना अच्छा लगा। भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत की टैरिफ की घटी दरों से मैं प्रसन्न हूँ। भारत की 140 करोड़ जनता की तरफ से इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प को बहुत-बहुत धन्यवाद। दुनिया की शान्ति, स्थायित्व और समानता के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प का नेतृत्व महत्पूर्ण है। इनके द्वारा शान्ति के लिए प्रयासों का भारत पूरी तरह से समर्थन करता है।" पिछले 11 दिनों से अमरीका और इज्राइल ने मिलकर ईरान पर हमला जारी रखे हुए है। ट्रम्प के कथित विश्व शान्ति के प्रयास में यह युद्ध भी एक है। भारत की पेट्रोलियम की आवश्कताओं को देखते हुए अमरीका ने भारत को 30 दिनों के लिए रूस से पेट्रोलियम आयात करने की छूट दी है और रूस ने कथित ट्रेड डील के पहले के दामो पर पेट्रोलियम ना देकर आज के बाजार भाव से बेचने की बात कही है। यह पहली झलक है भारत के सार्वभौम हितों की रक्षा की!

लेकिन अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ वार के अलावा कई अन्य वित्तीय आदेशों को रद्द कर दिया है। परिणामस्वरूप टैरिफ 10 प्रतिशत रह जायेगा। उधर ट्रम्प अपनी पराजय की झेंप मिटाने के रास्ते खोजने में लगा है, इधर भारत की सरकार ने उक्त ट्रेड डील को अन्तिम रूप देने के लिए जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की 21 फरवरी, 2025 के होने वाली अमरीका यात्रा को ईरान पर किए गए हमले के कसरण बदली हुई परिस्थितियों के दबाव में टाल दिया है।

जहां भारत की सार्वभौमिकता और संविधान की रक्षा एक ही व्यक्ति की इच्छा-अनिच्छा पर टिकी रहती है, वहीं अमरीका की संवैधानिक व्यवस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वहां की न्यायपालिका, वहां के सशक्त राष्ट्रपति और उसकी कार्यकारिणी से स्वतन्त्र है और वहां का सर्वेसर्वा राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवहेलना नहीं कर सकता है और न ही ऐसा कोई कानून बना सकता है जिससे वहां के सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों पर अंकुश लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कानून बनाने में सीनेट की सशक्त भूमिका है जो राष्ट्रपति के हरेक नाच को नियन्त्रित करती है। लेकिन ट्रम्प ने 24 फरवरी, 2026 को अपने दो घंटे के भाषण में भारत से सोलर उपकरणों के निर्यात पर 126 प्रतिशत का टैरिफ लगाकर अपनी अधिकारिता का बखान करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर किसी देश ने अमरीका के साथ किये गये टैरिफ डील पर फिर से बात करने की कोशिश की तो और भी बुरा हो सकता है। भारत के अमरीका परस्त नेताओं, मंत्रियों के पास क्या जवाब होगा सिवाय इसके कि भारत को वेनेजुएला के रास्ते ले जाया जाये।

लेकिन भारत में, कहने को तो न्यायपालिका और संसद स्वाधिकारी, स्वतन्त्र हैं, परन्तु कार्यकारिणी प्रमुख की रीतियों, नीतियों, अन्तर्राष्ट्रीय संवाद समझौतों के बारे में कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकती; उनका अनुमोदन करने को अपने अधिकार में लेने के संसद के पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसी दशा में भारत की सार्वभौमिकता, आर्थिक-औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा अमरीका के साथ होने जा रही ट्रेड डील से क्या सुरक्षित और संरक्षित हो पायेगी?

वैसे, 2029 में ट्रम्प भी राष्ट्रपति नहीं होगा और भारत भी आम चुनावों के दौर से गुजरेगा।

-राम निवास बैरवा,
पूर्व क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में तालाबंदी कर देनी चाहिए ?

प्रो. अशोक कुमार

आज भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ उसकी उपयोगिता और अस्तित्व दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। देश के कोने-कोने में कुकुरमुत्तों की तरह उगे महाविद्यालय और दशकों पुराने विश्वविद्यालय आज डिग्री बाँटने वाले केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं। कक्षाओं में पसरा सन्नाटा, परीक्षाओं के समय वन वीक सीरीज और 24 ऑवर सीरीज के लिए उमड़ती भीड़, और संस्थानों का गहराता आर्थिक संकट-ये सब एक ऐसी दुर्गंध की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। ऐसे में यह तीखा सवाल उठना लाजिमी है: क्या उन संस्थानों को बंद कर देना चाहिए जो न ज्ञान दे पा रहे हैं और न ही रोजगार?

मर्ज की गहराई:-भारत की उच्च शिक्षा का सबसे त्रासद पहलू कक्षाओं की रिक्तता है। छात्र प्रवेश तो लेते हैं, लेकिन उनका कॉलेज से वास्ता केवल परीक्षा फॉर्म भरने या डिग्री लेने तक सीमित रह गया है। इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। छात्र को यह भली-भांति ज्ञात है कि जो पाठ्यक्रम उसे पढ़ाया जा रहा है, वह दशकों पुराना है और बाजार की जरूरतों से उसका कोई सरोकार नहीं है। जब कक्षा में मिलने वाला ज्ञान उसे रोजगार की गारंटी नहीं देता, तो वह अपनी ऊर्जा और समय शॉर्टकट यानी कुंजी या सीरीज संस्कृति में लगाता है।

यह सीरीज संस्कृति शिक्षा के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा खिलवाड़ है। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होना चाहिए था, वहां मात्र 100-200 पन्नों की रटी-रटाई सामग्री ने बौद्धिक विकास का गला घोंट दिया है। परीक्षा प्रणाली की विफलता ही है कि एक छात्र साल भर गायब रहकर भी मात्र 24 घंटे पढ़कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है। ऐसे में शिक्षा केवल एक कागजी रस्म बनकर रह गई है।

आर्थिक बदहाली और नियुक्तियों का अकाल

संस्थानों के बंद होने की वकालत करने वालों का एक बड़ा तर्क उनकी आर्थिक स्थिति है। सरकारी कॉलेजों में बजट की भारी कमी है, तो निजी संस्थान केवल मुनाफे के मॉडल पर चल रहे हैं। बुनियादी ढांचे के नाम पर टूटी हुई बेंचें, पुरानी प्रयोगशालाएं और धूल फांकती लाइब्रेरी रह गई हैं। सबसे भयावह स्थिति नियुक्तियों की है। दशकों से कई राज्यों में प्रोफेसरों की स्थायी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। अतिथि विद्वान या एडहॉक या संबल योजना व्यवस्था के भरोसे चल रही शिक्षा व्यवस्था से गुणवत्ता की उम्मीद करना बेमानी है। शिक्षक को पेंशन की गारंटी नहीं! जब शिक्षक का अपना भविष्य अनिश्चित हो, तो वह छात्रों के भविष्य की नींव कैसे मजबूत करेगा?

रिक्त पदों और धन के अभाव ने विश्वविद्यालयों को शोध के बजाय केवल परीक्षा आयोजित करने वाली मशीन बना दिया है। यही कारण है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों की सूची में भारतीय संस्थान अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते दिखते हैं।

क्या तालाबंदी ही एकमात्र विकल्प है?

तर्क दिया जाता है कि यदि कोई फैक्ट्री उत्पाद नहीं दे रही और घाटे में चल रही है, तो उसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या शिक्षा पर भी यही मार्केट लॉजिक लागू किया जा सकता है? कतई नहीं।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बंद करना किसी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक त्रासदी का आमंत्रण होगा। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:-

शिक्षा का लोकतंत्रीकरण: भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ आर्थिक असमानता चरम पर है, सरकारी कॉलेज ही गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए उच्च शिक्षा का एकमात्र द्वार हैं। इन्हें बंद करने का अर्थ होगा शिक्षा को केवल अमीर की जागीर बना देना।

सामाजिक चेतना के केंद्र: विश्वविद्यालय केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, वे समाज को नेतृत्व देते हैं। युवाओं के भीतर वैचारिक मंथन और तर्क करने की क्षमता वहीं विकसित होती है। संस्थान बंद होने से देश में बौद्धिक शून्यता पैदा हो जाएगी।

डेमोग्राफिक डिविडेंड का संकट: भारत के पास युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है। यदि हम संस्थानों को सुधारने के बजाय बंद करेंगे, तो यह जनसांख्यिकीय लाभांश देश के लिए जनसांख्यिकीय आपदा में बदल जाएगा। बिना कौशल और शिक्षा के भटकते युवा अराजकता की ओर बढ़ सकते हैं।

समाधान: बंद करना नहीं, री-इंजीनियरिंग अनिवार्य

हमें संस्थानों के ताले लगाने के बजाय व्यवस्था के इंजन को बदलने की जरूरत है। इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कुछ कड़े और क्रांतिकारी कदम उठाने होंगे:-

पाठ्यक्रम का मार्केट-लिंक होना: हर डिग्री के साथ एक वोकेशनल स्किल अनिवार्य होनी चाहिए। यदि कोई छात्र साहित्य पढ़ रहा है, तो उसे कंटेंट राइटिंग या अनुवाद का कौशल सिखाया जाए। यदि कोई विज्ञान पढ़ रहा है, तो उसे स्थानीय उद्योगों के साथ इंटर्नशिप करना अनिवार्य हो।

परीक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव: जब तक प्रश्नपत्र रटने वाले होंगे, सीरीज बिकती रहेगी। परीक्षाओं को ओपन बुक बनाया जाए, प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन हो और कक्षा में उपस्थिति को केवल कागजों पर नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों से सुनिश्चित कर उसे क्रेडिट स्कोर से जोड़ा जाए।

नियमित नियुक्तियाँ और जवाबदेही: सरकार को शिक्षा पर जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना ही होगा। रिक्त पदों को तुरंत भरा जाए, लेकिन साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही भी तय हो। शिक्षकों का स्टूडेंट फीडबैक और रिसर्च आउटपुट उनकी पदोन्नति का आधार होना चाहिए।

उद्योग-अकादमिक तालमेल : महाविद्यालयों को अपने क्षेत्र के उद्योगों के साथ जुड़ना होगा। उद्योग अपनी जरूरत बताएं और कॉलेज उस अनुसार प्रशिक्षण दें। इससे आर्थिक संकट भी दूर होगा और छात्रों को प्लेसमेंट भी मिलेगा।

निष्कर्ष-उच्च शिक्षा में व्याप्त वर्तमान संकट व्यवस्था की विफलता है, शिक्षा के महत्व की नहीं। छात्र का कक्षा में न आना कॉलेज की असफलता है कि वह छात्र को कुछ नया नहीं सिखा पा रहा। वन वीक सीरीज का फलना-फूलना हमारी परीक्षा प्रणाली पर एक तमाचा है। संस्थानों को बंद करना पलायनवाद है, सुधारवाद नहीं।

हमें कॉलेजों को डिग्री छापने वाली प्रेस के बजाय स्किल और विजन देने वाले पावरहाउस में बदलना होगा। यदि हम आज इन संस्थानों को सुधारने के लिए निवेश नहीं करेंगे, तो कल हमें जेलों और बेरोजगारी भत्तों पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। शिक्षा बोझ नहीं, बल्कि भविष्य का निवेश है। ज़रूरत है कि हम इमारतों पर नहीं, शिक्षा की आत्मा-यानी शोध, नवाचार और गुणवत्ता-पर ध्यान केंद्रित करें।

–प्रो. अशोक कुमार,
विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 11 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:00 तक, वज्र योग प्रातः 9:12 तक, बालव करण दिन 3:07 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 10:00 से धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग रात्रि 10:00 से सूर्योदय तक है। आज गुरू मार्गी प्रातः 9:00 से होगा। आज शीतला माता पूजन बास्योडा है। आज कालाष्टमी, ऋषभ देव जयन्ती, वर्षीतप आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:41 तक, शुभ 11:09 से 12:37 तक, चर 3:33 से 5:01 तक, लाभ 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:45, सूर्यास्त 6:29

मेष

अपनी कार्य योजना सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

वृष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन

स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होने लगेगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

कर्क

परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आज आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। आज खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

सिंह

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

कन्या

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक

व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं से संबंधित परेशानी हो सकती है।

मकर

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

कुंभ

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आज धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

स्पीकर देवनानी द्वारा संसदीय संस्कृति में किये गए नवाचारों से लोकतंत्र में आमजन की आस्था बढी : मुख्यमंत्री

संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत है और विपक्ष के सुझावों पर विचार किये जाना भी आवश्यक है। राजस्थान विधानसभा अधिक दिनों तक और नियमों व परम्पराओं से चल रही है। हम सभी का भी एक ही ध्येय होता है कि राजस्थान की जनता का भला किस प्रकार से किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा विधान सभा में किये गये नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि विगत दो सालों में पुस्तकें लिखकर उन्होंने संसदीय परम्पराओं के प्रति लोगों की रूचि बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की जो परम्परा रही है वह बहुत ही ऐतिहासिक और संसदीय मूल्यों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजस्थान विधान सभा में किये गये नवाचारों पर आधारित पुस्तक ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि'' के नवीन संस्करण कृति के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्पीकर देवनानी की दोनों पुस्तकों का अनावरण कर विमोचन किया और उत्कृष्ट लेखन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह समारोह लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय संस्कृति की सतत यात्रा का उत्सव है। लोकतांत्रिक संस्थाएं तब ही सशक्त बनती है जब वे परम्पराओं और नवाचारों के बीच संतुलन स्थापित करते हुए जन भागीदारी, पादर्शिता को केंद्र में रखकर कार्य करती है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा लिखित पुस्तक ''संसदीय संस्कृति का उत्कर्ष नवाचारों के दो वर्ष और सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि'' के नवीन संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर स्पीकर देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग भी मौजूद थे।

वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा का अमृत महोत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जायेगा। विधानसभा में संसदीय व्यवस्था को मजबूती देने और संसदीय संस्कृति को उत्कर्ष बनाने के लिए अनेक नवाचार किये गये है। राजस्थान विधानसभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय को 50 हजार से अधिक लोगों ने देख लिया है। यह लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था का परिचायक है।

- 50 हजार से अधिक लोगों ने देखा विधान सभा का संग्रहालय : देवनानी

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में सेन्ट्रल हॉल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 14 करोड रूपये की राशि भी बजट में पारित कर दी है। देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए भी राज्य सरकार द्वारा बजट में राशि का प्रावधान किये जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा के नवाचारों में बजट की कोई कमी नहीं रखने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है।

देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधान सभा में संविधान गैलेरी, वन्दे मातरम की 150वीं जयन्ती पर वन्दे मातरम दीर्घा और कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण कर नवाचार किये गये है। अब आने वाले समय में विधान सभा में कोई भी प्रश्नों के जवाब लम्बित नहीं रहेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि जनहित के मुद्दों को हल करने के लिए विधायकों द्वारा लगाये गये प्रश्नों के जवाब 100 प्रतिशत मंगवाये जाए।

देवनानी ने कहा कि विधान सभा सदन का आसन महत्वपूर्ण होता है। आसन पर बैठने के बाद वे अनुशासन और नियमों के प्रति कठोर हो जाते है। सदन से किसी सदस्य को अनुशासनहीनता के मामले में जब सदन से बाहर कर दिया जाता है तो उनकी स्थिति उस मां की तरह भी हो जाती है, जिसका बच्चा जब तक भोजन नहीं कर लेता है तब तक वह दु:खी रहती है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधान सभा का सत्र शानदार रहा है। विधान सभा में ऐतिहासिक कार्य हुए है। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है। स्पीकर का संरक्षण ही प्रतिपक्ष को मजबूती प्रदान करता है।

जूली ने कहा कि स्पीकर देवनानी की सेन्ट्रल हॉल निर्माण की सोच सराहनीय है। यहां पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य बैठकर चर्चा कर सकेंगे और उन सभी में आपसी समन्वय की भावना भी प्रबल हो सकेगी।

संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि स्पीकर देवनानी ने दो वर्षों में विधान सभा में अनेक नवाचार किये है। विधान सभा संग्रहालय को देखने आने वालों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि विधान सभा से आमजन का जुडाव बढ रहा है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आभार जापित किया। समारोह में मंत्रीमण्डल के सदस्य, विधायक, जनप्रतिनिधि, कुलगुरु, शिक्षाविद सहित गणमान्य लोग मौजूद थे।

दो से ज्यादा बच्चों वाले बन सकेंगे मेयर-पार्षद

कुष्ठ रोग पीड़ित भी लड़ सकेंगे निकाय चुनाव

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान में दो से ज्यादा बच्चों वाले नेता अब पार्षद, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, सभापति बन सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को बहस के बाद राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को पारित कर दिया। सरकार ने एक्ट की धारा 18(2) में संशोधन किया है। दो बच्चों की बाध्यता साथ ही कुष्ठ रोग पीड़ितों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाई गई है। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होते ही यह कानून बन जाएगा। अगले निकाय चुनाव में दो से ज्याादा बच्चों वाले नेता चुनाव लड़ सकेंगे।

नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस का जवाब देते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नगर निकायों में हम ''एक राज्य, एक चुनाव'' करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, एक साथ चुनाव करवाने की स्थिति में हैं। शर्त एक ही है कि ओबीसी को अगर राजनीतिक आरक्षण देना है तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करना पडेगा।

अगर आप विपक्ष के लोग मांग करते हैं और लिखकर देते हैं कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे।

नगरपालिका संशोधन बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओ में दो से ज्यादा बच्चों वालों को लाभ नहीं मिलता। अब निकाय और पंचायतीराज चुनावों में आपने दो बच्चों की बाध्यता हटा दी है तो क्या अब केंद्र-राज्य की योजनाओं में भी इस बाध्यता को हटाएंगे? दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं, जहां तीसरा बच्चा होने पर लाभ से वंचित कर दिया जाता है। उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

कल पंचायतीराज मंत्री कह रहे थे कि सब जागरूकता आ गई, दो बच्चों की बाध्यता की जरूरत नहीं है। जब यह सब हो गया तो फिर योजनाओं से भी बाध्यता हटाइए। डोटासरा ने कहा कि चुनाव के लिए आप नगरपालिका एक्ट में संशोधन कर दो बच्चों की बाध्यता हटा रहे हो, लेकिन चुनाव नहीं करवा रहे हो? यूडीएच मंत्री ने कई बार चुनाव करवाने की समय सीमा के बयान दे दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ओबीसी आयोग से जानबूझकर रिपोर्ट नहीं ले रहे हो। ओबीसी आयोग को पंगु बना दिया। राज्य निर्वाचन आयोग को भी कठपुतली बना दिया। सीएमओ में बुलाकर हाजिरी लेते हैं और बताते हो ऐसा करना है।

डोटासरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव करवाने का फैसला दिया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव करवाने की नीयत नहीं है। अब आप चुनाव टालने के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का बहाना बना रहे हैं कि आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा। उधर, आयोग को मना कर रखा है कि रिपोर्ट नहीं देनी है। आयोग कह रहा है कि सरकार डेटा नहीं दे पा रही है। सरकार डेटा नहीं दे पा रही है तो यह उसकी विफलता है।

- यूडीएच मंत्री बोले ''निकायों में हम 'एक राज्य-एक चुनाव' करवाने की हालत में हैं, सिर्फ ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है।''
- अगर आप विपक्ष मांग लिखकर देता है कि बिना ओबीसी आरक्षण दिए निकाय चुनाव करवा लिए जाएं, तो हम कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर देंगे : झाबर सिंह खर्रा
- कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सदन में पूछा कि ''क्या केंद्र-राज्य की योजनाओं से भी दो बच्चों की बाध्यता हटाएंगे?''

'60 दिन में मुकदमा तय नहीं होने के आधार पर स्वत: जमानत का अधिकार नहीं'

न्यायिक अधिकारी तय अवधि में निस्तारण का प्रयास करें : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत जमानत का स्वत: लाभ इस आधार पर नहीं मिल सकता कि गैर जमानती मामले में साक्ष्य दर्ज करने के प्रथम दिन से साठ दिन में प्रकरण तय नहीं हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश अजीत कुमार शुक्ला की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रदेश के सभी न्यायिक अधिकारियों को कहा है कि वह ऐसे मामलों को तय अवधि में तय करने का प्रयास करें।

जमानत याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ श्याम नगर थाना पुलिस में साल 2024 में एफआईआर दर्ज हुई थी और वह गत 25 मई से न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका में कहा गया कि गत 18 अगस्त को निचली अदालत उसके खिलाफ आरोप तय कर चुकी है। इसके बावजूद किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए गए, जबकि बीएनएसएस की धारा 480 की उपधारा 6 के तहत यदि गैर जमानती मामले में आरोप तय होने के 60 दिन में सुनवाई पूरी नहीं होती तो आरोपी को जमानत का लाभ दिया जा सकता है।

इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील एमएस शेखावत ने कहा कि उसने पीडित को प्रॉफिट ट्रेडिंग प्लान का लालच देकर उससे करीब 82 लाख रुपए की ठगी की है। वहीं उसके खिलाफ अन्य मामले में लंबित है। धारा 480 की उपधारा 6 को अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता और अदालत परिस्थितियों को देखते हुए जमानत पर निर्णय कर सकती है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

46.30 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला गिरफ्तार

जयपुर। अशोक नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोलर प्रोजेक्ट की आड़ में फर्जी बैंक गारंटी लगाकर 46 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से फर्जी बैंक गारंटी तैयार कर सरकारी संस्था से बड़ी रकम हड़प ली थी। डीसीपी (दक्षिण) उपायुक्त राजर्षि राज ने बताया कि मुख्य आरोपी महेश भाई (50) गुजरात के अहमदाबाद का निवासी है और फिलहाल इंदौर में रह रहा था।

फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसएमएस अस्पताल जैसे मल्टी-स्पेशिलिटी अस्पतालों के वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर जारी नकली मेडिकल प्रमाण पत्र जारी होने पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के नाम पर नकली प्रमाण पत्र बनाने और इन्हें जारी करने से रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि ऐसे चिकित्सा प्रमाण पत्रों को ऑन लाइन पोर्टल के जरिए जारी करने के संबंध में लंबित फाइल पर 45 दिन में फैसला करें। अदालत ने कहा कि इसके अनुमोदन के लिए विभाग के संबंधित अधिकारियों से परामर्श कर अंतिम रूप दें। वहीं अदालत ने मामले में बनाए एसओपी के ड्राफ्ट की कॉपी भी अदालत में पेश करने को कहा है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश शकुंतला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने अदालत को बताया कि ऐसे प्रमाण पत्रों की जालसाजी और दुरुपयोग को रोकने के लिए एसओपी का ड्राफ्ट तैयार कर उसे अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। इस पर अदालत ने इसे अंतिम रूप देने के लिए 45 दिन का समय दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनुराग कलावटिया ने बताया कि प्रकरण एनबीसी के पास स्थित करीब छह बीघा जमीन से जुडा हुआ है। जिसके स्वामित्व को लेकर याचिकाकर्ता के पक्ष में आदेश हुए थे। वहीं कानूनी कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता की बीमारी को लेकर याचिकाकर्ता ने एसएमएस की चिकित्सक भावना शर्मा की ओर से जारी इलाज कराने के प्रमाण पत्र को अदालत में पेश किया। वहीं अदालत ने मामले में एसएमएस प्रशासन को भावना शर्मा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा। इस पर भावना शर्मा ने इस प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए अपने खिलाफ हुए आदेश को रद्द करने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मौत भी हो चुकी है।

स्मारकों- संग्रहालयों में 18 मार्च को मिलेगा नि:शुल्क प्रवेश

जयपुर। राजस्थान सरकार के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने अपने अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए 18 मार्च, नि:शुल्क प्रवेश की घोषणा की है। निदेशक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग डॉ. पंकज धीरेन्द्र ने बताया कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधीन सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में 7 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश नि:शुल्क है एवं लेटर पैड हस्ताक्षर युक्त पत्र के साथ आने वाले शिक्षण संस्थाओं को भी पूरे सप्ताह स्मारकों और संग्रहालयों में नि:शुल्क भ्रमण करवाया जाता है।

राजस्थान कृषि उपज मंडी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन

मंडियों और यार्डों का तेजी से होगा विकास, भूमि अर्जन प्रक्रिया होगी पारदर्शी और सुव्यवस्थित : मुख्यमंत्री

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है। इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मण्डी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।

इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलें जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को नि:शुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यार्डों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड रूपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अटरू (बारां), बारां, रामगंजमण्डी (कोटा), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), दूदू (जयपुर), सरदारशहर (चूरू) एवं सूरजपोल, (अनाज) जयपुर सहित अन्य मण्डियों में यार्ड निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों से व्यापारियों एवं किसानों के लिए मण्डी प्रांगणों में मूलभूत सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

'छात्रावासों में चौकीदार-रसोइयें संवेदक से जॉब बेसिस पर लेते हैं'

जयपुर (कासं)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में विद्यार्थियों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संवेदक द्वारा जॉब बेसिस पर रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएं ली जाती हैं। मंत्री गहलोत ने स्पष्ट किया कि विधानसभा में दिए गए उत्तर में विभाग के स्वीकृत पदों की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी। विभाग के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई अंशकालीन कर्मचारी नियुक्त नहीं है। हालांकि, छात्रावासों में भोजन व्यवस्था को प्रभावित न होने देने के लिए स्थानीय स्तर पर मानदेय अथवा समय-आधारित व्यवस्था के माध्यम से संवेदक द्वारा रसोइयों और चौकीदारों की सेवाएं ली जाती हैं, जो प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। गहलोत ने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में रसोइयां एवं चौकीदारों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध अंशकालीन रसोइयां या चौकीदार कार्य नहीं कर रहे है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग के राजकीय छात्रावासों में वित्त विभाग की सहमति उपरांत रसोईयां व चौकीदार का कार्य आरटीपीपी एक्ट के मुताबिक जॉब बेसिस पर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों।

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने हैल्पलाइन पर सुनी समस्याएं

लाखेरी के पंकज सुमन की शिकायत पर बूंदी कलक्टर को मौके पर दिए निस्तारण के निर्देश

जयपुर। राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन (181) आमजन की समस्याओं का अंतिम पडाव साबित हो रही है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उनके विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की जानकारी ली तथा परिवादियों से सीधे संवाद कर मौके पर ही संबंधित अधिकारीयों को प्रकरणों के निस्तारण कर कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए।

- 10261 प्रकरणों का निस्तारण, औसतन 27 दिनों में हो रहा समस्याओं का समाधान

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनन्द कुमार ने मंगलवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के परिवादियों से संवाद के दौरान बूंदी जिले के लाखेरी के पंकज सुमन द्वारा बताया गया कि मेन रोड पर लगे पीपल के पेड मे से गुजर रही बिजली लाइन आमजन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने मौके पर ही बूंदी कलक्टर अक्षय गोदारा को फोन कर मंगलावार शाम से पहले परिवादी की समस्या के समाधान कर की गई कारवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सीकर के महेश कुमार खुडानिया ने समस्या के समयबद्ध समाधान हो जाने पर राज्य सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। जयपुर के श्री विष्णु द्वारा दर्ज केमिकल फेक्ट्री से प्रदूषण की शिकायत पर आनंद कुमार ने संबंधित अधिकारी को औचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल समस्याओं का अंतिम पडाव होना चाहिए। इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित कुल 10957 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 10261 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरणों के निस्तारण की औसत अवधि 27 दिन है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हैल्पलाइन पर स्वयं उपस्थित रहकर परिवादियों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे है।

अमरूदों का बाग व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व समारोह पर रोक बरकरार

जयपुर (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर में अमरूदों का बाग, अंबेडकर सर्किल व जनपथ क्षेत्र में रैली, मेले व बडे समारोहों के आयोजनों पर रोक बरकरार रखते हुए इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इलाकों में सार्वजनिक कार्यक्रमों और ट्रैफिक के नियमन से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश फिलहाल प्रभावी रहेंगे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह संबंधित क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रित करने या जरूरी प्रतिबंध के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत आठ सप्ताह में नया वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश प्रशासक रिटायर जस्टिस सुदर्शन कुमार मिश्रा व अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया। इन याचिकाओं में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

प्रशासक व एसएमएस इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में राज्य सरकार ने एक परिपत्र निकालकर इन जगहों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे और वह मौजूदा व्यवस्था को बहाल रखना चाहते हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व नए कानूनी प्रावधानों के अनुसार वैधानिक आदेश जारी कर सकती है। गौरतलब है कि 5 सितम्बर 2018 को अमरूदों का बाग, जनपथ में एक बड़ी सभा के कारण भारी ट्रैफिक जाम हो गया था। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए रैली, सभा, सम्मेलन और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

'दिलावर-डोटासरा की जोड़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आ सकती है'

जयपुर (विसं)। महाराणा प्रताप खेल यूनिवर्सिटी बिल पर बहस का जवाब देते हुए खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर चुटकी ली।

मंत्री राज्यवर्धन ने कहा कि आजकल एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए बहुत से एक्सपर्ट लगते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बेहतर परफॉर्मेंस के लिए खिलाड़ी को टिप्स देते हैं। उसे पता होता है कि क्या चीज करनी है, जिससे शानदार प्रदर्शन करे। जैसे उदाहरण के तौर पर दूसरे क्षेत्र के विधायक को देखकर विधायक में उत्तेजना जाती है यह साइकोलॉजी होती है, यह सारी की सारी चीजें जुड़ती है, तब जाकर खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर पाता है।

- खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह ने सदन में दोनों नेताओं पर चुटकी ली

जैसे डोटासराजी और मदन दिलावरजी की जो जोड़ी है, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आ सकती है, यह उदाहरण ठीक है न। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी कहा कि दोनों को साथ में खाना खिला दीजिए।

उदयपुर : जंगल की आग में घिरे मध्य प्रदेश के पर्यटक की अस्पताल में मौत

बताया गया है कि पर्यटक माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने गया था

- **हादसे के बाद पर्यटक माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो मौके पर युवक बेहोशी की हालत में मिला**

उदयपुर, (कासं)। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी झील पर बाहुबली हिल क्षेत्र में भीषण जंगल की आग में फंसे पर्यटक को सोमवार रात को रेस्क्यू किया गया था। मंगलवार सुबह उसकी एमबी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले माखन सिंह (33) के रूप में हुई है। बाहुबली हिल क्षेत्र का 3 हेक्टेयर घना जंगल अग से जलकर राख हो गया है।

बताया गया कि माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाडी पर घूमने चला गया। जंगल में आग में फंस गया। माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर्मियों के अनुसार युवक धुएं के बीच झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला। उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहां मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसकी मौत हो गई। माखन सिंह रतलाम जिले की जावरा तहसील के ऊपरवाडा गांव का रहने वाला था।

गांव के सरपंच कमलेश पाटीदार ने बताया कि माखन घर से घूमने के लिए ही बोलकर निकला था। वह हार्वेस्टर शोरूम में मैनेजर था। उसके तीन बच्चे हैं।

एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन ने बताया कि प्रारंभिक रूप से मौत का कारण आग के धुएं से दम घुटना माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फायर ब्रिगेड अधिकारी बी.एल. चौधरी ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैल गई थी जिसके कारण पूरी पहाडी काले धुएं से ढ क गई थी।

दमकल की टीमों ने देर रात तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि एहतियात के तौर पर रातभर फायर ब्रिगेड की टीमें जंगल क्षेत्र के आसपास तैनात रही।

जानकारी के अनुसार बाहुबली हिल्स बड़ी लेक के पास स्थित जंगल एरिया है। इस पहाड़ी पर टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए आते हैं। बीते कुछ समय में ये पूरा एरिया प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी पॉपुलर हुआ है। फॉरेस्ट अधिकारियों के अनुसार यहां के जंगल में कई दुर्लभ वनस्पति भी मिलती हैं। आग के कारण इन्हें भी नुकसान पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि इस सीजन में पहाड़ियों पर अब तक करीब पांच जगह आग लगी है। 15 दिन पहले नीमचमाता स्थित पहाड़ी पर आग लगी थी। सप्ताहभर पहले ऋषभदेव की पहाड़ी पर आग लगी थी। तीन दिन पहले चित्रकूट नगर और दो दिन पहले बड़ी गांव स्थित पांडवा की पहाड़ी पर आग लगी थी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कई स्थानों पर आगजनी की घटना घटित हो रही है ऐसी आपात स्थिति में बिना संसाधन के आग में प्रवेश नहीं करें। आग लगने की सूचना तुरंत शहर प्रशासन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, पर देवें जिससे आग को काबू में किया जा सके। आग जलने से वातावरण में चारों तरफ दम घुट गैस कार्बन डाइ ऑक्साइड बनती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है एवं जानमाल की नुकसान होने की संभावना रहती है।

जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक घायल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में शताब्दी सर्कल के पास बदमाशों ने एक युवक पर गोलियां चला दी। वारदात में युवक के कंधे में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए एम्स अस्पताल ले जाया गया है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायल युवक की पहचान रामड़ावास निवासी अनिल साहू के रूप में हुई है, जो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के समय अनिल साहू के साथ उसका भाई मुन्ना उर्फ देवसा भी मौजूद था। हमलावर कौन थे और उन्होंने दिनदहाड़े इस वारदात को किस वजह से अंजाम दिया, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि, पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते ही यह घटनाक्रम हुआ हो सकता है। इसी आशंका के आधार पर पुलिस एक संदिग्ध स्कॉर्पियो की तलाश में जुटी है। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वारदात की सूचना मिलते ही कुड़ी थानाधिकारी तेजकरण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी करवा दी है। हमलावरों को पकड़ने के लिए कुड़ी के अलावा विवेक विहार, लूणी, झंवर और बोरानाडा थाना इलाकों में भी सभी एसएचओ अपनी-अपनी टीमों के साथ अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर बदमाशों की तलाश कर रही है।

बाइक चोरी

सादुलपुर, (निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित बोर्ड परीक्षा संग्रहण केंद्र के बाहर से एक शिक्षक की बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि गांव रामपुरा निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक है।.नौ मार्च को बोर्ड परीक्षा के चलते वे सुबह अपनी बाइक स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी कर अंदर परीक्षक कक्ष में बोर्ड की कॉपियों की जांच करने चले गए। शाम करीब चार बजे जब वह घर जाने के लिए बाहर आए तो उनकी बाइक मौके से गायब मिली।

राजस्थान सरकार
कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
क्रमांक-ए.जी.एच./लेखा (क्रय)/2026/7224 दिनांक-26.02.2026
ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 26/2025-26)
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.) सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर के रक्तकोष विभाग में काम आने वाले टेस्ट किट्स रिजेन्ट्स व कन्ज्यूमेबल के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा (दोहरी बिड पद्धति) में इच्छुक बोलीदाता दिनांक 7.3.2026 से 16.3.2026 सायं 05.00 बजे तक निविदा डाउनलोड/अपलोड कर सकते है। बोली आमंत्रण सूचना की महत्वपूर्ण शर्ते व पूर्ण विवरण "http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा http://sppp.rajasthan.gov.in" पर देखी जा सकती है। ई-बोली की अनुमानित लागत 100 लाख है।
UBN NO. MCB2526GLRC00334
चिकित्सा अधीक्षक
प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एच.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
DIPR/C/4833/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त बांसवाडा
सिन्टेक्स मिल के पास, दाहोद रोड-327001
दूरभाष- 02962-294907, ई-मेल-secircle.ban.phed@rajasthan.gov.in
निविदा सूचना संख्या 27/2025-26
जन स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बांसवाडा के अधीन विभिन्न पेयजल योजनाओं क कार्य हेतु आफलाईन बिडस इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 27/2025-26 दिनांक 28.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिडस से सम्बन्धित समस्त जानकारी www.sppp.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।
NIB CODE- PHE2526A7016
NIT NO. 27/2025-26
UBN NO. PHE2526WSRC15133
(जालेन्द्र कुमार चारण)
अधीक्षण अभियंता
जन स्वा.अभि.विभाग
वृत बॉसवाडा
DIPR/C/4852/2026

ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की

पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिला की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पीड़िता के पति ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी पत्नी ने 28 नवंबर 2025 को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिवार से मिली जानकारी के आधार पर अब मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले में बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी पत्नी बीमार होने पर एक प्राईवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में कार्यरत आरोपी संदीप उसकी पत्नी को दवाई देता था, जिससे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि संदीप कुमार ने बाद में उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद संदीप कुमार के साथ रोहताश और वीरेंद्र भी इस मामले में शामिल हो गए। तीनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पत्नी से पैसों की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि पिछले करीब छह महीने से तीनों उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

दर्ज मामले में बताया कि उसकी पत्नी ने दुकान की आमदनी से नगद व खाते के माध्यम से आरोपियों को पैसे दिए। यहां तक कि उसने अपने सोने के गहने बेचकर भी करीब 7 से 8 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए, लेकिन इसके बाद भी वे लगातार और पैसों की मांग करते रहे। इससे उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। बताया गया कि 28 नवंबर 2025 को आरोपियों ने फोन कर दो दिन में दो लाख रुपये देने की मांग की और नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसी से भयभीत होकर उसकी पत्नी ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया कि जांच के दौरान मोबाइल की जांच करने पर यह जानकारी मिलने पर परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अनियंत्रित ट्रेलर खाई में गिरा

उदयपुर, (कासं)। मंगलवार को उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे-27 पर पत्थर के पाउडर से भरा ट्रेलर 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना स्थल से गुजर रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग खाई के अंदर उतरे। केबिन में ट्रेलर ड्राइवर और खलासी को फंसा देखकर पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत से दोनों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार पत्थर के पाउडर से भरा ट्रेलर सुबह करीब दस बजे उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर खोखरिया नाल सुरंग के पास गहरी खाई में गिर गया। मौके से गुजर रहे वाहन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। टीम ने खाई में उतरकर केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। दोनों घायल झालावाड जिले के भवानीमंडी निवासी आत्माराम पुत्र प्रभुलाल और राजेश पुत्र भागचंद को एंबुलेंस के जरिए गोगुंदा हॉस्पिटल ले जाया गया।

नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

नोखा, (निसं)। थाने में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में नोखा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले दो साल से एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इस दौरान दवाइयों के प्रचार-प्रसार का काम करने वाला एक युवक अक्सर अस्पताल में आता-जाता था। उसने पहचान बढ़ाई और उसे बीकानेर के किसी बड़े अस्पताल में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी ले लिए। पीड़िता ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को आरोपी उसे अपने साथ बीकानेर ले गया। वहां एक होटल में इंटरव्यू होने का बहाना बनाकर उसे नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और मोबाइल से अश्लील फोटो-वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने इन फोटो-वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे कई बार अपने साथ बीकानेर ले जाकर दुष्कर्म किया।

रिपोर्ट में बताया कि 12 जनवरी 2026 को आरोपी उसे फिर नशीला पदार्थ पिलाकर जयपुर ले गया। वहां उसने धमकी देकर कुछ कागजातों पर जबरन साइन भी करवा लिए और खुद को उसका पति बताने लगा। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसे एक बंद कमरे में रखकर मारपीट, गाली-गलौच करता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता ने बताया कि 7 मार्च को वह किसी तरह युवक के घर से निकलकर अपने पिता के घर पहुंची। उसने अपने पिता और भाई को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नोखा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
क्रमांक-6754-6773 दिनांक-27.02.2026
निविदा सूचना संख्या- 176-187/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विभिन्न कार्यो हेतु नियमानुसार उपर्युक्त श्रेणी में इस विभाग में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से दिनांक 12.03.2026 तक को सायं 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते है। वेबसाईट पर तकनीकी बिड दिनांक 13.03.2026 को इस कार्यालय में प्रात 11.00 बजे खोली जाएगी राजस्थान सरकार वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ईप्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ई निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही चालान से बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fee) बिड सिक्योरिटी (EMD) एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाना आवश्यक है।
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.dipronline.org पर देखे जा सकते है।
NIT no. 176 - UBN - PHE2526WSRC15092, NIT no. 177 - UBN - PHE2526WSRC15094,
NIT no. 177 - UBN - PHE2526WSRC15095, NIT no. 178 - UBN - PHE2526WSRC15096,
NIT no. 179 - UBN - PHE2526WSRC15099, NIT no. 180 - UBN - PHE2526WSRC150100,
NIT no. 181 - UBN - PHE2526WSRC150101, NIT no. 182 - UBN - PHE2526WSRC150102,
NIT no. 183 - UBN - PHE2526WSRC150103, NIT no. 184 - UBN - PHE2526WSRC150106,
NIT no. 185 - UBN - PHE2526WSRC150107, NIT no. 186 - UBN - PHE2526WSRC150108,
NIT no. 187 - UBN - PHE2526WSRC150109
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
टेलीफोन नं. 0141-2221802
DIPR/C/4801/2026

खेत में अज्ञात युवक का शव मिला

- **युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है**

सादुलपुर, (निसं)। सिद्धमुख थाने के गांव चैनपुरा छोटा की रोही में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धर्मवीर लाठर के खेत में पड़े शव को लेकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को उस समय मिली, जब खेतों में लोग चने की फसल की कटाई कर रहे थे। शव मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सिद्धमुख थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि शव को राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं संभवतः युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। हांलाकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिद्धमुख थाना पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं मृतक के बारे में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी साझा की जा रही है ताकि मृतक की शिनाख्त हो सके। इस घटना ने स्थानीय लोगों को हैरानी में डाल दिया है। पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि मौत के असली कारणों का पता लगाया जा सके।

थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि मृतक का कद 5.7 फीट, बदन दुबला पतला, रंग सांवला, उम्र करीबन 40-45 वर्ष, सिर पर हल्के बाल है, हल्की काली व सफेद दाढी मुंछे, सफेद रंग की शर्ट, स्लेटी रंग की इनर व काले रंग की पैंट पहने हुए हैं, नंगे पैरों से है।

युवक ने आत्महत्या की

निवाई, (निसं)। शिवाजी कॉलोनी की गली नंबर 14 में एक 17 वर्षीय युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस के एएसआई कमलेश गूर्जर व भारती मीणा मय जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को फंदे से उतारकर राजकीय उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

एएसआई कमलेश गुर्जर ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे दीपक वर्मा पुत्र कान्हा रैगर निवासी गली नंबर 14 वार्ड नंबर 32 शिवाजी कॉलोनी ने फंदे से झूलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक अपने बुजुर्ग दिव्यांग चाचा के साथ रहता था। उसकी मां मजदूरी कर जीवन-यापन करती है। करीब तीन वर्ष पूर्व मृतक के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी।क

विवाहिता की मौत, आरोपी पति दहेज हत्या में गिरफ्तार

विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी

जोधपुर, (कासं)। शहर के भदवासिया स्थित 80 फीट रोड पर रहने वाली एक विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या में केस दर्ज कराया था। प्रकरण में पुलिस ने अब आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया।

थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि जयमल नगर, 80 फीट रोड भदवासिया निवासी कमल किशोर जोशी ने गत 26 फरवरी को रिपोर्ट दी थी। इसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री 30 वर्षीय तर्पिता की शादी वर्ष 2022 अप्रेल में विद्यानगर, आरटीओ के पास बीजेएस निवासी धर्मेंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ की गई थी। शादी के समय 20 तोला सोना और एक किलो चांदी के आइटम के साथ घरेलू सामान दिया गया था, मगर ससुराल पक्ष के लोग जिनमें सास सुमन देवी, जेठ महेंद्र, जेठानी नीतू, काकी ससुर लक्ष्मणराम एवं खुद पति धर्मेंद्र उसे दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। चार साल शादी के बीच में दो तीन बार उसकी बेटी तर्पिता को कम दहेज के लिए मारपीट कर घर बदर भी कर दिया गया। बाद में समाज के लोगों द्वारा समझाइश कर उसे ससुराल भिजवाया गया। बेटा जन्म के बाद उसे दहेज मे कार की मांग रखी गई थी। कार नहीं दिलाए जाने पर उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में उसकी बेटी तर्पिता को किराए के मकान में रखा गया जहां पर पति धर्मेंद्र उससे मारपीट करता और दहेज के प्रताड़ित करता था। इस साल 24 जनवरी को उसकी बेटी तर्पिता ने एक बेटी को जन्म दिया था।

मामले में जांच कर रहे एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद मृतका के पति आरटीओ के पीछे विद्या नगर पावटा, सी रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B)((After Policy-2026-27)EX/L/2026-06481-9018219/748
दिनांक-10.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4(1)वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	16.03.2026	प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्व प्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://SSO.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलमी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक में बढाकर बोली लगानी होगी।
4 बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5 कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6 ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नहीं होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाने के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7 प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8 सफल बोलीदाता को धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तो, जो विभागी वेबसाईट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
9 निर्धारित समय में वांछित राशियॉ यथा-धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10 वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तो पर अनुज्ञा पत्र नीवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11 बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूव्र विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश प्रक्रिया एवं शर्तो का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12 मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध मं विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13 ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुार रहेंगे।
आबकारी आयुक्त, राज.
DIPR/C/5187/2026

8500 लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अन्तर्राज्यीय ठग बिहार से गिरफ्तार

आरोपी इतना शतिर था कि फर्जी आधार कार्ड से नाम बदलकर वारदात को अंजाम देता था

- **आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम राशि घोषित की गई थी**
- **आरोपी ने कोटा ही नहीं, बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया था**

कोटा, (निसं)। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में 8500 से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस टीम ने ठगी के मास्टरमाइंड आरोपी कुमार शानू को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी इतना शतिर था कि फर्जी आधार कार्ड से अपना नाम बदलकर ठगी की वारदात को अंजाम देता था।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 15 नवम्बर 2025 को पीड़ित कुलदीप शर्मा व अन्य ने अनंतपुरा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा कि दीपक सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अनंतपुरा क्षेत्र में ओएसि एन्टरप्राइजेज कंपनी खोलकर 8500 लोगों को घर बैठे रोजगार देने के नाम पर ठगी करते हुए 2500 रूपये सुरक्षा राशि के नाम से जमा की और करीब दो करोड़ रूपये की राशि हड़पकर रातों-रात दफ्तर को बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि मामले को गंभरीता से लेते हुए शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया। मामले की जांच पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में की गई। शहर एसपी ने बताया कि ठगी के आरोपी ने ठगी के दौरान पहचान छिपाने के लिये फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग किया था, जिससे उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिये चुनौती बन गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज द्वारा 50 हजार के इनाम राशि घोषित की गई। गठित टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर दबिश भी दी।

शहर एसपी ने बताया कि आरोपी तक पहुंचने में टीम के सदस्य कांस्टेबल फरसाराम की अहम भूमिका रही। कांस्टेबल ने डिजिटल फुटप्रिंस और तकनीकी डेटा का गहन विशलेषण करते हुए ठगी के आरोपी की पहचान बिहार के खगड़िया निवासी कुमार शानू के रूप में की। मामले में अनुसंधान के दौरान सामने आया कि आरोपी ने कोटा ही नही बल्कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी अलग-अलग तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है। शहर एसपी ने बताया कि कांस्टेबल फरसाराम द्वारा दिये गये तकनीकी इनपुट के आधार पर अनंतपुरा थानाधिकारी रमेश कविया के नेतृत्व में पुलिस टीम को बिहार रवाना किया गया और टीम ने कई दिनों तक अपनी पहचान छिपाकर आरोपी की निगरानी की एवं डिजिटल सर्विलांस के जरिये पुख्ता हुआ कि ठगी का मास्टरमाइंड कुमार शानू एक होटल में छिपा हुआ है, इस पर टीम ने होटल में दबिश देकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपी के पास से 1,88,500 रूपये नकद, ठगी मे प्रयुक्त कार सहित कई फर्जी आधार कार्ड, ई-श्रमकार्ड बरामद किये। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड लेकर कोटा लाया गया। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी हैं।

शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि आरोपी कुमार शानू शातिर और पेशेवर ठग है। अनंतपुरा क्षेत्र के सुभाष नगर में ओएसि एन्टरप्राइजेज नाम से फर्जी कंपनी खोली और अखबारों में घर बैठे रोजगार के लुभावने विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं व महिलाओं को निशाना बनाता था, आरोपी फर्जी आधार कार्ड पर अपनी पहचान जाहिर करता था। आरोपी ने पुस्तकें तैयार करने का काम देने के बदले 2500 रूपये सुरक्षा राशि के नाम पर जमा करवाता, आरोपी ने ठगी की वारदात को जल्दी करने के लिये चैन मार्केटिंग का सहारा लिया और नये सदस्य जोड़ने पर 500 रूपये कमीशन का लालच दिया। आरोपी ने कुछ ही महीनों में करीब 8500 युवा व महिलाओं से करीब दो करोड़ की राशि हड़प ली और रातों-रात दफ्तर बंद कर फरार हो गया। शहर एसपी ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पूर्व में कई राज्यों में कहीं मोतियों की माला बनाने का काम देकर तो कहीं स्वेटर बुनने तो कहीं कुछ ओर काम देकर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी ने दरभंगा बिहार, रांची झारखंड, सारनपुर उत्तरप्रदेश, इन्दौर मध्यप्रदेश, बीकानेर राजस्थान में भी ठगी की वारदातें की है।

जुआ खेलते चार जनों को पकड़ा

टोंक, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने सोमवार देर रात को ताश पत्ती पर जुआ खेलते चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्यवाही में डीएसटी ने कोतवाली क्षैत्र के बछेरों के घेर में छापा मारकर 1 लाख 68 हजार रुपए नगद और तीन मोटरसाइकिल जब्त की हैं। डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि डीएसटी ने जुआं खेलते चार आरोपियों गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.68 लाख रुपए की जुआ राशि बरामद की है तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई तीन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-जालोर
Tel: 02973-222272 E-mail: ee.jal.phed@rajasthan.gov.in., xen_jal@yahoo.com
क्रमांक-वृत/जालोर/निविदा/ /2025-26/ दिनांक-
बिड आमंत्रण सूचना (NIB) संख्या 100/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु लोक निर्माण और वित्तीय नियम के पार्ट-4 नियम 334 (ए) (iii) के तहत रू. 150.00 लाख तक की निविदाओं हेतु केवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत एवं इससे अधिक लागत की निविदाओं हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में पंजीकृत निविदादाताओं हेतु नियमानुसार छूट के साथ एवं केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकृत विभागों/संगठनो, केन्द्रिय लोक निर्माण विभाग, रेल, डाक, दूर संचार विभागों में उपयुक्त समकक्ष श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से पूर्ण धरोहर राशि के साथ ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा निम्न ऑनलाईन बिड आमंत्रित की जाती है-

बिड संख्या	NIB NO. PHE2526A6946	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	बिड शुल्क (रूपये)	ई-प्रक्रिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
100/2025-26	UBN NO. PHE2526WSRC15194	35.00	70000	1000	1000	6 माह
ऑनलाइन बिड उपलबध होने की तिथि			05.03.2026			
ऑनलाईन बिड डाउनलोड/अपलोड करने की अन्तिम तिथि			19.03.2026 को 6.00 पी.एम.			
ऑनलाईनबिड खोलने की तिथि			20.03.2026 को 02.00 ए.एम.			

बिड से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट www.dipronline.org sppp.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
(राजकुमार कटारा)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
खण्ड-जालोर
DIPR/C/4923/2026

प्रदेश में गैस की कीमतें बढ़ाने पर कांग्रेस ने किया सदन में हंगामा और वॉकआउट

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला तो सदन से वॉकआउट किया

-विधानसभा संवाददाता-

जयपुर । विधानसभा में ईरान और यूएस-इजराइल युद्ध के बाद गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी और कॉमर्शियल सिलेंडरों की राशनिंग के मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया। सरकार के इस मुद्दे पर जवाब नहीं देने के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया।

शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने संकट के समय गैस की कीमतें बढ़ाकर जनता पर डबल बोझ डाला है। सरकार को सब्सिडी देकर जनता को राहत देनी चाहिए, सरकार ने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की तरफ से सदन में गैस की कीमतें बढ़ाने से उपजे हालात पर जवाब दिलाने की मांग की। जूली ने कहा कि सरकार को बढ़ी हुई गैस सिलेंडर की कीमतों और कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं देने से उपजे हालात पर सदन में बयान देना चाहिए। सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम सदन से वॉकआउट कर रहे हैं।

- **दरअसल शून्यकाल में कांग्रेस विधायक अमित चाचाण ने यह मामला उठाते हुए कहा कि सरकार ने संकट के समय गैस की कीमतें बढ़ाकर जनता पर डबल बोझ डाला है। सरकार को सब्सिडी देकर जनता को राहत देनी चाहिए।**

प्रश्नकाल में गोदारा व जूली में नोकझोंक

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान बढ़ी हुई गैस कीमतों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के बीच बहस हो गई। जूली ने पूछा कि कल ही रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कॉमर्शियल सिलेंडरों पर अघोषित रोक लगा दी है। क्या सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देकर जनता को राहत देगी? खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष विद्वान हैं। आपको पता होगा कि गैस की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं।

गैस की किल्लत नहीं होने देंगे : खाद्य मंत्री

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब सदन में पूछा कि, आप जनता को सब्सिडी देकर राहत देंगे क्या? इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि हम आमजन को गैस की किल्लत नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। इस पर जूली ने कहा कि, गैंस सिलेंडरों कीमतें बढ़ गईं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जब हमने 500 में सिलेंडर दिया था, तब 800 रुपए का सिलेंडर था। अब जब 600 रुपए सिलेंडर का रेट है तो आप सस्ता नहीं दे सकते क्या?

कांग्रेस करेगी 12-13 मार्च को प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन

जयपुर । कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने केंद्र की सरकार पर विदेश नीति में विफल रहने और देश में महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इजरायल, ईराक ओर अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान देश के हितों को सुरक्षित रखने में केंद्र सरकार असफल रही है, जिसके कारण देश में ईंधन संकट की स्थिति पैदा हो गई है।

डोटासरा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आमजन पर महंगाई का बोझ डालते हुए घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और समारोहों में उपयोग होने वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शादी-विवाह और सामाजिक समारोहों का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होना आमजन के लिए गंभीर समस्या बन गया है। डोटासरा ने इसे केंद्र सरकार का घातक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी असर पड रहा है। डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार को गत वर्ष की तुलना में 7.10 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला

प्रदेश के विकास में राजस्व की भूमिका अहम, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्ययोजनाएं बनाएं : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण के संबंध में बैठक ली।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष समान अवधि में राज्य सरकार को 7.10 प्रतिशत की राजस्व अर्जन में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति, खनन ब्लॉक्स की नियमित नीलामी, पारदर्शी कर व्यवस्था सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि अधिकारी राजस्व आय में वृद्धि के लिए कार्ययोजना बना कर कार्य करें। साथ ही, सभी विभागों की राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समिति का भी गठन किया जाए जो नियमित तौर पर विभागवार प्रगति का आंकलन करे। शर्मा ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आमजन को राहत मिली है और इस क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स में प्रदेश देशभर में अग्रणी है तथा इससे करदाताओं को भी लाभ मिला है।

शर्मा ने कर चोरी और पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए सुदृढ निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही,

- **मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने और पारदर्शी व्यवस्था के लिए सुदढ़ निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए**

कर संबंधी सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया। अधिकारियों ने बताया कि इस सिस्टम के उपयोग करने से करदाताओं को अधिक सुगमता हुई है। राज्य में जीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से परिवहन विभाग द्वारा भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.51 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन हुआ है। साथ ही, ग्रीन टैक्स से आय भी दोगुनी हो गई है। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाए।

साथ ही, व्हीकल स्क्रैपिंग का भी व्यवस्थित निष्पादन किया जाए। बैठक में बताया गया कि पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा डीएलसी दरों में किए गए सुधारों से इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में स्टांप ड्यूटी से अर्जित राजस्व समान अवधि में 16.34 प्रतिशत बढ़ा है। खनन पट्टों की नीलामी से राजस्व अर्जन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग द्वारा अवैध खनन पर पूर्ण रोकथाम के उपाय किए जाएं तथा इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल करने और आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में किए गए नीतिगत सुधारों से इस वर्ष आबकारी से राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष से लगभग 7.52 प्रतिशत अधिक रहा है। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गन्ने की फसल की आड़ में अफीम की खेती का खुलासा

जयपुर । राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई करते हुए राशमी थाना क्षेत्र में गन्ने की फसल की आड में की जा रही अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने खेत से 5317 अफीम के पौधे और 780 ग्राम शुद्ध अफीम का दूध जब्त कर खेत मालिक को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर राशमी थाना पुलिस ने गांव भालोटा की खेडी में खेत पर दबिश दी। खेत में गेहूं, चना और गन्ने की फसल के बीच अवैध अफीम की खेती की जा रही थी। पुलिस टीम ने मौके से कुल 5317 अफीम के पौधे (वजन 431 किलो 460 ग्राम) और अफीम डोडों से निकाला गया 780 ग्राम अफीम का दूध जब्त किया। साथ ही अफीम चिराई और लुवाई में उपयोग होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए। मामले में खेत मालिक शोभा लाल जाट (45) निवासी भालोटा की खेड़ी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में जांच शुरू की।

गर्मी में बिजली का समुचित प्रबंध करें : ऊर्जा मंत्री

जयपुर (कासं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को आगामी गर्मी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गर्मी की तीव्रता अधिक रहने के आसार हैं। ऐसे में विद्युत मांग में संभावित बढ़ोतरी का आंकलन करते हुए अधिकारी बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। नागर मंगलवार को विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों के अधिकारियों के साथ आगामी गर्मियों में विद्युत मांग एवं उपलब्धता की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विद्युत गृहों के कॉमन पूल से बिजली का आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में भारत सरकार ने गर्मी के सीजन में 750 मेगावाट तक का कोटा आवंटित किया था, जिससे आपूर्ति प्रबंधन में मदद मिली थी। ऊर्जा मंत्री ने लघु अवधि आधार पर एक्सचेंज से बिजली खरीद के लिए भी निविदा प्रक्रिया अभी से सम्पादित करने के निर्देश दिए।

- **ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय विद्युत गृहों के कॉमन पूल से बिजली का आवंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं।**

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने मंगलवार को विद्युत भवन में अधिकाारियों की बैठक लेकर आगामी गर्मियों में विद्युत मांग एवं उपलब्धता को लेकर समीक्षा की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा अजिताभ शर्मा ने निर्देश दिए कि उत्पादन निगम द्वारा थर्मल यूनिटों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए जिससे कि यूनिटों के अनावश्यक ट्रिप होने की सम्भावनाओं को कम किया जा सके। साथ ही अधिकतम उत्पादन हासिल किया जा सके। उन्होंने उत्पादन निगम को बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली के कार्य की प्रगति में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

राजस्थान ऊर्जा विकास एण्ड आईटी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा ने आगामी अप्रैल माह से सितम्बर माह तक ऊर्जा की औसत मांग, उपलब्धता, मांग में बढ़ोतरी आदि को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि अप्रैल और मई माह में लघु अवधि आधार पर एक्सचेंज से बिजली खरीद के लिए निविदा जारी कर दी गई हैं। बैठक में जोधपुर डिस्कॉम की ओर से कुछ सब-स्टेशनों पर ऊर्जा भण्डारण प्रणाली के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक में जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल, ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव सौरभ स्वामी, उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी सहित तीनों विद्युत वितरण निगमों एवं प्रसारण निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के.पी वर्मा वीडियो कान्फ्रेन्स से जुड़े।

नागालैंड की युवती को जयपुर में ट्रक ने रौंदा, मौत

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । बजाज नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में नागालैंड की एक युवती की मौत हो गई। टैक्सी बाइक से गिरने के बाद पीछे से आ रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने उसे कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

सड़क दुर्घटना थाना (पूर्व) के हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान नागालैंड निवासी लिगा जिमो (22) के रूप में हुई है। वह पिछले करीब दो साल से जयपुर के मालवीय नगर क्षेत्र में किराए पर रह रही थी और एक पार्लर में काम करती थी।

जो सोमवार रात वह सिंधी कैंप से टैक्सी बाइक लेकर अपने घर मालवीय नगर लौट रही थी। इसी दौरान गोपालपुरा बाईपास पर पुलिया पर चढ़ते समय बाइक चालक ने अचानक नीचे की ओर मोड लिया। इससे संतुलन बिगड़ने पर युवती बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई।

इसी दौरान पीछे से आ रहे एचपी गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका-मुआयना कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

सार-समाचार

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा

जयपुर । फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से मंगलवार को आईटीसी राजपूताना जयपुर में इनसाइडर टेल्स - भारतीय मुद्रा के बदलते स्वरूप विषयक एक खास सत्र का आयोजन किया गया। सत्र ने फ्लो सदस्यों को भारतीय मुद्रा की रोचक यात्रा को समझने का अनूठा अवसर मिला। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन डॉ. रिम्मी शेखावत (2025-26) ने कहा कि ऐसे सत्र से सदस्यों को देश के महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों को विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से समझने का मौका मिलता है। साथ ही सीखने के नए आयाम मिलते हैं। सत्र के मुख्य वक्ता काज़ा सुधाकर रहे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण के पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने भारतीय मुद्रा प्रणाली के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण अनुभव साझा किए। उन्होंने भारतीय मुद्रा के विकास, नए नोटों के डिज़ाइन और मुद्रण की प्रक्रिया तथा 2016 की नोटबंदी से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदमों पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में फ्लो सदस्यों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। सत्र सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और रोचक रहा।

अज्ञात मृतक के परिजनों की तलाश

जयपुर (कासं)। विधायकपुरी थाना पुलिस अज्ञात मृतक के परिजनों की तलाश में जुटी है। पुलिस ने बताया कि 10 मार्च को दोपहर 2:50 बजे एम.आई.रोड पर महिन्द्रा शोरूम के नजदीक एक अज्ञात युवक अचेत स्थिति में पड़ा मिला, उसे उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव मुर्दाघर में रखवाकर उसके परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष है।

डॉ. अर्चना मेहता का सम्मान

जयपुर (कासं)। सामाजिक संस्था इकोफ्यूजन और एटर्नल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न वर्गों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पॉली हाउसेस और कृषि कार्य में उत्कृष्टता के लिए डॉ. अर्चना मेहता को ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉ. रोही दहिया ने सम्मानित किया। एटरनल हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। डॉ. अर्चना मेहता जो पी.एच.डी. हैं और गृहणी हैं तथा साथ ही जयपुर फुट की निर्मीता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति की कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रवेश कर पॉलिहाउस कृषि प्रणाली में अल्पसमय में अच्छी सफलता प्राप्त की। समारोह में राजस्थान की आम कर संयुक्त आयुक्त लेखा शर्मा भी उपस्थित थी।

रो. सुनील दत्त गोयल बने सलाहकार

जयपुर । एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया ने सामाजिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रोटेरियन सुनील दत्त गोयल को क्लब का सलाहकार नियुक्त किया है। क्लब के अध्यक्ष अमिताभ अग्निहोत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय गिरि एवं महासचिव डॉ. सुनील कौशिक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सुनील दत्त गोयल के लंबे अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और सामाजिक सरोकारों को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन से एडिटर्स क्लब ऑफ इंडिया की गतिविधियों को नई दिशा और गति मिलेगी। संगठन सचिव नरेश वशिष्ठ एवं एडवाइजरी विंग के चेयरपर्सन अनुराग वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एडिटर्स क्लब ऑफ़ इंडिया द्वारा गठित यह एडवाइजरी विंग केवल एक औपचारिक संरचना नहीं, बल्कि पत्रकारिता के भविष्य को दिशा देने वाला एक सशक्त विचार मंच है। ज्ञात रहे कि सुनील दत्त गोयल वर्तमान में इंपीरियल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

'जनसुझावों से बनेंगे गांव और वार्डों के मास्टर प्लान'

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान - 2047 के लक्ष्य के क्रम में राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन मास्टर प्लान्स में भविष्य की आवश्यकताएं और महिला, युवा, गरीब, किसान सहित सभी आयु वर्ग के सुझाव शामिल किए जाएंगे ताकि यह जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन सके। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान की बजट घोषणा के क्रम में प्रस्तावित अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम एवं दीर्घ अवधि की श्रेणियों में विभाजित करते हुए तैयार करें ताकि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप उनकी जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मास्टर प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुनियोजित विकास करना है जिससे ग्रामीणों का पलायन रूके और शहरों पर भार ना पड़े। उन्होंने साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण से मास्टर प्लान्स में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सडक, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं बनाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि विकास के साथ-साथ विरासत के मूल मंत्र को केन्द्र में रखे।

नौकरी का झांसा देकर ठगने वाला गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर उत्तर की ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिछले एक साल से फरार चल रहे एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिवालय में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) करन शर्मा ने बताया कि ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अरुण शर्मा उर्फ आलू (32) निवासी कागदीवाड़ा (ब्रह्मपुरी) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 17 फरवरी 2025 को सुभाष कुमार नामक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था। थानाधिकारी हेमन्त जनागल ने बताया कि आरोपित अरुण शर्मा ने उसे सचिवालय में एलडीसी के पद पर सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दिया था। इसके बदले आरोपी ने उससे 3.20 लाख रुपये ऐंठ लिए और विश्वास जीतने के लिए उसे एक फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिया।

ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया। जिसके बाद से ही आरोपी अपनी पहचान छिपाकर फरार चल रहा था।

जिस पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीरज पाठक व सहायक पुलिस आयुक्त (आमेर) सुरेन्द्र सिंह राणावत के सुपरविजन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना पर आरोपी को दबोचा। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए ठगी करता था।

वह कभी खुद को ड्रग इंस्पेक्टर तो कभी पुलिस अधिकारी बता कर लोगों पर रौब झाड़ता था। वह बड़े अधिकारियों से अपनी साठगांठ होने का दावा कर युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देता था।

साथ ही शातिर ठग अरुण शर्मा उर्फ आलू के खिलाफ पूर्व में भी जयपुर के ब्रह्मपुरी, गलता गेट और नाहरगढ़ थानों में ठगी के कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य वारदातों और फर्जी दस्तावेजों के निर्माण के संबंध में जानकारी मिल सके।

'जयपुर को गड्ढा, गंदगी और प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य'

प्रदेश के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के.के.गुप्ता ने जयपुर नगर निगम में ली अफसरों की मैराथन बैठक

जयपुर (कासं)। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नियक्त प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के.के.गुप्ता ने मंगलवार को नगर निगम जयपुर में साफ-सफाई को लेकर अफसरों की मैराथन मीटिंग ली। उन्होंने निर्देश दिए कि राजधानी जयपुर में 100 प्रतिशत कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का पृथकीकरण, प्रतिदिन समयबद्ध कचरा उठाने, जीपीएस मॉनिटरिंग तथा सॉफ्टवेयर से पेनल्टी की व्यवस्था की जाए।

गुप्ता ने कहा कि, मोहल्लों में आम नागरिकों को जोड़ते हुए व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्वच्छता गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित किया जाए। सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों की दिन में 3 बार सफाई, खाली भूखंडों की सफाई नहीं होने पर पेनल्टी और सीजर कार्रवाई, व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई, बिजली के पोलों की लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने, बेसहारा गौवंश को गौशालाओं भेजने, नालियों की हाई-प्रेशर मशीन से सफाई और बाग-बगीचों को स्वच्छ रखा जाए।

स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को अब एक जन आंदोलन बनाना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संकल्प है कि हमारा राज्य समृद्ध और विकसित बने, जिसके लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान सबसे प्राथमिक कड़ी है। मुख्यमंत्री खुद समय-समय पर प्रदेश की सभी निकायों की स्वच्छता को लेकर जानकारी ले रहे हैं। पिछले 1 माह में 17 जिलों की 90 निकायों में बैठकें की गई हैं। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि स्वच्छता के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जीरो टॉलरेंस नीति के साथ में काम होगा। मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट परिणामों के लिए कोताही-लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के.के.गुप्ता ने मंगलवार को नगर निगम जयपुर में साफ-सफाई को लेकर अफसरों की मीटिंग ली।

- **100 प्रतिशत कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का पृथकीकरण, प्रतिदिन समयबद्ध कचरा उठाने, जीपीएस मॉनिटरिंग तथा सॉफ्टवेयर से पेनल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश**

90-ए और भू-उपयोग पर खुलकर बातचीत

गुप्ता ने 90 ए को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि 90-ए करने के पश्चात जब तक निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की जाए, जब तक भूमि का पूरा डेवलपमेंट संबंधित भू मालिक द्वारा नहीं कर दिया जाए। जिसमें रोड लाइट, पानी, नाली, बगीचे तथा अगर कोई कॉलोनी नई बन रही है, उसका पानी बरसात के अंदर किसी झील या तालाब में जाने की संभावना हो तो उस जगह गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट अवश्य लगवाने के लिए पाबंद करें, अन्यथा झील तालाब प्रदूषित हो जाएंगे। आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने पश्चात ही कॉलोनाइजर को 12.5 प्रतिशत प्लॉट दिए जाएं, अन्यथा उनका आवंटन रोककर रखें।

डूंगरपुर निकाय हर वर्ष रच रहा कीर्तिमान

गुप्ता ने कहा कि जनजाति अंचल की डूंगरपुर निकाय ने स्वच्छता में सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान प्राप्त किए हैं। वर्ष 2015 में प्रदेश के सभी निकाय प्रमुखों की कार्यशाला जयपुर में आयोजित हुई थी, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि प्रदेश के सभी निकायों को खुले में शौच मुक्त बनाना है। तब मेरे द्वारा सबसे पहले डूंगरपुर को खुले में शौच मुक्त बनाने और 5 करोड रुपए प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद यहां अधिकारियों और जनता ने साथ में मिलकर स्वच्छता की लडाई लड़ी थी और आज तक भी डूंगरपुर निकाय का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पटल पर स्वच्छता में पहचाना जाता है तथा निकाय राजस्थान प्रदेश की प्रथम खुले में शौच मुक्त निकाय घोषित होने का भी गौरव रखती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रतिवर्ष डूंगरपुर निकाय किसी न किसी श्रेणी में अव्वल स्थान प्राप्त कर रहा है।

जहां सीवरेज लाइनें डल चुकी, वहां मरम्मत करें

गुप्ता ने निर्देश दिए कि शहर में जहां-जहां सीवरेज के कार्य चल रहे हैं उसमें यह आवश्यक है कि जो खुदाई कर दी गई है, जहां लाइन डाल दी गई है पहले उसकी रिपेयरिंग और मरमत का कार्य किया जाए। प्राय: यह देखने में आया है कि ठेकेदार द्वारा लाइन तो डाल दी जाती है, लेकिन रिपेयरिंग का कार्य नहीं करते, जिससे आमजन सरकार को कोसते है।

ARBiT
it happens here...

Celebrating Aspirations And The Courage To Dream

National Dream Day is observed to celebrate the power of aspirations and the courage it takes to pursue them. The day encourages individuals to reflect on their goals, rekindle forgotten ambitions, and take meaningful steps towards turning dreams into reality. It serves as a reminder that innovation, creativity, and progress often begin with a simple idea and the determination to act on it. Whether personal or professional, dreams shape purpose and direction in life. National Dream Day inspires people of all ages to believe in possibilities, overcome self-doubt, and work steadily towards building the future they envision.

राष्ट्रदूत
WEDNESDAY
11 March 2026
A-B

#GUSTAV KLIMT

Before Gold

What is particularly striking is Klimt's attention to the sitter's gaze. The girl does not confront the viewer directly; her eyes drift slightly aside...

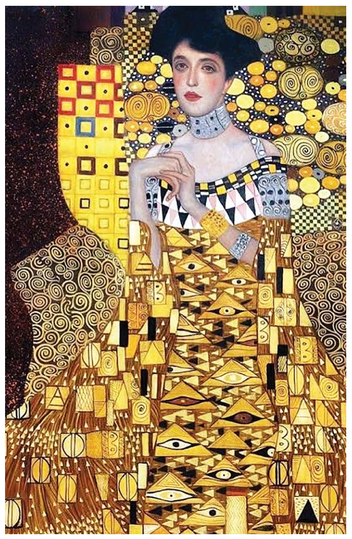

Looking closely at *Head Study of a Girl from Haná* (c.1883). When speaking about Gustav Klimt, public imagination almost automatically jumps to gold leaf, flattened ornament, and the seductive symbolism of his mature period. Yet, works such as Head Study of a Girl from Haná remind us that Klimt's artistic language was built on a foundation of exceptional academic discipline and observational sensitivity.

Painted around 1883, this modestly scaled oil on wood belongs to Klimt's early formative years, when he was still deeply embedded in the traditions of academic realism. The handling of the face is careful and restrained: the modelling is soft, the transitions between light and shadow finely calibrated, and the palette subdued. There is no decorative excess here, only a quiet insistence on presence, weight, and psychological inwardness.

What is particularly striking is Klimt's attention to the sitter's gaze. The girl does not confront the viewer directly; her eyes drift slightly aside, creating a subtle tension between intimacy and reserve. This compositional choice already hints at a trait that will later define Klimt's mature work: figures that are emotionally charged yet inwardly self-contained. Even at this early stage, Klimt seems less interested in narrative than in the mental and emotional state of the subject.

The reference to Haná, a region in Moravia known for its distinct folk culture, adds another layer. Klimt was not merely studying anatomy; he was engaging with regional identity and human type, an approach common in academic training but elevated here by his unusual empathy. The headscarf, softly merging with the background, dissolves the boundary between figure and space, foreshadowing Klimt's later fascination with unity between body and environment.

Importantly, this painting stands as firm evidence that Klimt did not abandon realism because he lacked skill. On the contrary, works like this demonstrate that his later radical stylistic shifts were a conscious rejection of academic limits, not an escape from them. The seeds of the secession, flatness, psychological intensity, and the suppression of anecdotal detail, are already quietly present.

To view Head Study of a Girl from Haná is to witness Klimt thinking through paint, testing how far a face alone can carry meaning. It is not a decorative object, but a disciplined, searching study, one that anchors his later brilliance in a deeply serious artistic beginning.

Chocolate Syrup Soda And Other Curatives

At the time, chocolate was touted for its medicinal properties and prescribed as treatment for a range of diseases, says Deanna Pucciarelli, a professor of nutrition and dietetics at Ball State University who researches the medicinal history of chocolate. It was often prescribed for people suffering from wasting disease. The extra calories assisted in weight gain, and the caffeine-like compounds helped perk patients up. "It didn't treat the actual illness, but it treated the symptoms," she explains.

#TASTY MYTHS

Verna Mohon

At first glance, nothing seems particularly odd about the December 1896 edition of *The Druggists Circular and Chemical Gazette*, a catalog of products that any self-respecting pharmacy ought to carry. But look closer! Hiding among medical necessities like McElroy's glass syringes and Hirsh Frank & Co's lab coats, you'll find some more curious finds, including Hershey's cocoa powder.

"Perfectly soluble," boasts the ad in bold, capital lettering. "Warranted absolutely pure." It reads as if it was peddling medicine, and in fact, it sort of, was.

Druggists of the day often used the dark powder to whip up a syrup sweet enough to mask the flavour of objectionable remedies, explains Stella Parks, a pastry chef with the food and cooking website *Serious Eats*. Parks happened upon these vintage advertisements while she was researching her new book, *BraveTart: Iconic American Desserts*, which features lesser-known histories of our favourite sweet treats.

The Hershey's ad intrigued her. "What in the world are these guys doing, advertising to druggists?" she recalls wondering at the time. By digging into the history and tracking down more pharmaceutical circulars and magazines, she discover the rich history of chocolate syrup, which began not with ice cream and flavoured milk, but with medicine.

Our love of chocolate goes back over 3,000 years, with traces of cacao appearing as early as 1500 B.C. in the pots of the Olmecs of Mexico. Yet, for most of its early history, it was consumed as a drink made from fermented, roasted, and ground beans. This drink was a far cry from the sweetened, milky stuff that we call hot chocolate today. It was rarely sweetened, and likely very bitter.

Still, the roughly football-sized pods that cradled the beans were held in high esteem; the Aztecs even traded cacao as currency. Chocolate didn't become popular overseas, however, until Europeans ventured into the Americas at the end of the 15th century. By the 1700s, the ground beans were avidly consumed throughout Europe and the American colonies as a sweetened, hot drink that was vaguely reminiscent to today's hot cocoa.

At the time, chocolate was touted for its medicinal properties and prescribed as treatment for a range of diseases, says Deanna Pucciarelli, a professor of nutrition and dietetics at Ball State University who researches the medicinal history of chocolate. It was often prescribed for people suffering from wasting disease. The extra calories assisted in weight gain, and the caffeine-like compounds helped perk patients up. "It didn't treat the actual illness, but it treated the symptoms," she explains.

Yet, for pharmacists, it wasn't only the supposed health benefits but also the rich, velvety flavor that held such appeal. "One thing about medicines, even going way back, is that they are really bitter," says Diane Wendt, associate curator of the division of medicine and science at Smithsonian's National Museum of American History. Many medications were originally derived from plants and fall in a class of compounds known as alkaloids, which has an acrid, mouth-puckering flavour. The first of these alkaloids, isolated by a German chemist in the early 1800s, was none other than morphine. Chocolate, it turns out, effectively covered the toe-curling taste of these foul flavours. "Few substances are so eagerly taken by children or invalids, and fewer still are better than chocolate for masking the taste of bitter or nauseous medicinal substances," according to the 1899 text, *The Pharmaceutical Era*. It's unclear exactly when pharmacists first combined cocoa powder and sugar to brew the sticky syrup. But its popularity was likely helped along by the invention of cocoa powder. In 1828, Dutch chemist Coenraad J. Van Houten patented a press that successfully removed some of chocolate's natural fats, reducing its bitter flavour and making it easier to dissolve with water. Still, the result wasn't exactly the 'same kind of smooth mellow chocolate we have now,' says Parks; to make it palatable, pharmacists would mix cocoa powder with at least eight times more sugar than chocolate.

The popularity of chocolate syrup exploded in the second half of the 19th century, coinciding with the golden age of so-called patent medicines. These are named after the 'letters of patent' the English crown awarded to inventors of supposedly curative formulas. The first English medicine patent was awarded in the late 1600s, but the name later came to refer to any over-the-counter drugs. American 'patent medicines' went by the same name, but were not typically patented under this system. Patent medicines emerged at a time when public need for treatments and cures outpaced medical knowledge. Many of these 'cures' did more harm than good. Often marketed as cure-alls, the concoctions could contain anything from pulverized fruits and veggies to alcohol and opioids. At the time, the common use of these addictive substances in remedies was legal; regulation didn't come about until the 1914 passage of the Harrison Narcotic Act.

One popular remedy featuring tincture of opium as its active ingredient was Stickney and Poor's Paregoric. This syrup was marketed as a treatment for many ills, and given to cholicky infants as young as five days old. 'Remedies' like this weren't completely ineffective. The inclusion of narcotics and alcohol in the cures did indeed give customers temporary relief from illness, and, more sinisterly, their addictive nature kept them coming back for more.

The boom of factory mass production in the 1900s brought with it the rise of easy-to-swallow medical pills. But before that, "pill making by hand is pretty labor intensive," says Wendt. "To actually make a pill of a certain dose, to mix it up and cut the pills, and roll the pills, and dry the pills, and coat the pills, that's a pretty lengthy process." That's why, during this time, medications were mostly served up in liquid or powder form, says Wendt.

Druggists would mix each liquid remedy with a base of sugary flavoured syrups, like chocolate, and take it either by the spoonful or mixed into a beverage, says Wendt. Alternatively, powders could be directly poured into your refreshment of choice. The base for these medicinal drinks could be anything from plain water to tea to a couple fingers of whiskey. But over the course of the 1800s, one particular drink was gaining popularity as a medicine masker: carbonated water.

Not unlike chocolate, soda water was initially considered a health drink in its own right. The carbonated beverage mimicked the mineral-rich waters bubbling up in natural springs that had become known for its curative and healing powers. Soda became a truly widespread phenomenon in America around the turn of the century, thanks to the pharmacist Jacob Baur, who invented the process necessary to sell tanks of pressurized carbon dioxide.

Part health drink, part delicious treat, sweetened carbonated water began spreading like wildfire in the form of soda fountains, Darcy O'Neil writes in his book *Fix the Pumps*.

Syrups became ever more popular to keep pace with the soda craze. Many of these flavours are still common today: vanilla, ginger, lemon and, of course, chocolate. By the late 1800s, hardly a pharmacist publication went without some mention of chocolate syrup, Parks writes in *BraveTart*. And hardly, a drug store went without a soda shop: Soda fountains served as a lucrative side business for druggists and pharmacists who commonly struggled to make ends meet, says Parks.

At the time, carbonated concoctions were largely still seen as cures. "Soda is an excellent medium for taking many medicines," according to the 1897 book, *The Standard Manual of Soda and Other Beverages*. "For example, the best method of administering castor oil is to draw a glass of sarsaparilla soda in the usual manner and pour in the requisite amount of oil." (Sarsaparilla, a flavour derived from the root of a tropical vine, is still used today in some root beer variants.)

One example still very much available today is Coca Cola. Originally mixed up with cocaine, the fizzy drink was touted it as a healthful stimulant to revive the brain and body.

At the turn of the century, however, chocolate syrup began to shift from treatment to treat. "It just seemed to naturally segue into all the ice cream (desserts) that pharmacists had to keep on hand just to stay afloat," says Parks.

A fortuitous mix of events helped elevate the state of chocolate to commercial confection. First, in the early 20th century, concerns over false health claims and downright dangerous cures helped lead to the passage of the 1906 Pure Food and Drug Act, which required druggists to disclose the remedy ingredients with clear and accurate labels. Similarly, a clamp down on American patent medicines may have further driven the chocolatey transition.

At the same time, other forms of chocolate were gaining traction as confections in their own right. As the industrial revolution ushered in machinery that took over the time-intensive process of turning cacao to cocoa, prices began to fall, explains Pucciarelli. "It all comes together," she says. "The price of manufacturing drops, the price of sugar drops, and then you have chocolate bars."

In 1926, Hershey's began marketing pre-mixed chocolate syrup in both single and double strength varieties for commercial businesses. The cans were shelf stable, meaning druggists (and soda jerks) didn't need to continually mix up new batches. By 1930, both Hershey's and other chocolate companies like Bosco's had begun marketing chocolate syrup for home use. The rest is sweet, sweet history. These days, despite many modern claims of health benefits, some founded and some unfounded, chocolate is considered more confection than cure. Chocolate accounts for the 'vast majority' of the $35 billion confection market in the United States, according to the National Confectioners Association.

Yet, the use of a sweet cover for medications remains isn't completely dead. You can find sweetness masking medicine in many forms, from cherry cough syrup to bubblegum-flavoured amoxicillin. It seems Mary Poppins was right! A spoonful of sugar, or in this case, chocolate, really does help the medicine go down.

rajeshsharma1049@gmail.com

An Ad of Stepping Stones to Health, Hershey's Syrup.

The Druggists' Circular and Chemical Gazette.

#NIGHTMARE

The Mare - An Evil Spirit!

The mare was believed to be a malevolent entity that haunted individuals during the night, inducing feelings of suffocation, anxiety, and dread

In Old English, the word 'mare' originally referred not to a horse but to a supernatural creature or evil spirit. The term 'mare' comes from the Old English word mære, which described an evil spirit or goblin that would sit on people's chests while they slept, causing them to experience bad dreams or nightmares. The mare was believed to be a malevolent entity that haunted individuals during the night, inducing feelings of suffocation, anxiety, and dread.

The creature was often depicted as a night-riding demon who would visit people while they slept, usually inducing feelings of paralysis, breathing difficulties, or night terrors. The presence of the mare was associated with a sensation of being crushed or smothered, which could explain the feelings of pressure many experience during intense nightmares, often resulting in a feeling of being unable to breathe or move.

In many cultures, the mare was considered a type of night hag or incubus that would torment people during sleep, usually preying upon the vulnerable or the weak. This evil spirit was often blamed for phenomena such as sleep paralysis, a condition in which individuals wake up but are temporarily unable to move, often accompanied by terrifying hallucinations or sensations of a presence in the room.

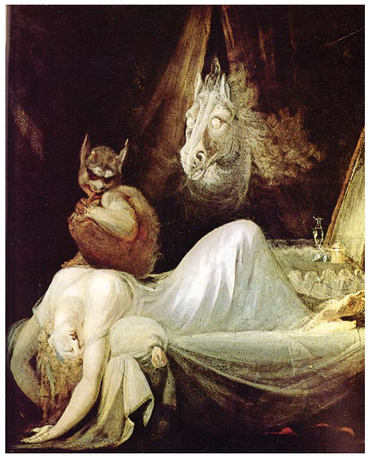

The Role of the "Night" in "Nightmare"

The word 'nightmare' itself comes from a combination of 'night' (referring to the time of sleep) and 'mare' (the spirit or goblin). In ancient times, people did not necessarily distinguish between the physical world and the supernatural one in the way that we do today, so bad dreams and nighttime experiences were often thought to be the result of malevolent forces. The term 'nightmare' thus implies that these unsettling experiences were not simply random occurrences but rather caused by some external, paranormal influence.

Interestingly, while the modern usage of the word 'nightmare' refers strictly to bad dreams, its origins were much more physical and terrifying. The mare's torment would often be tied to feelings of breathlessness, panic, or a sense of oppression on the chest. This can be linked to certain sleep disorders like sleep paralysis, where people wake up but experience an inability to move, and may even hallucinate an intruder or oppressive force pressing down on them.

Not Related to Female Horses

The confusion with the female horse is understandable, given that the word 'mare' is still used in modern English to refer to a female horse. However, the connection between the spirit and the horse is a matter of linguistic evolution, not mythology. The word 'mare' in the context of nightmares has nothing to do with horses; instead, it refers to an old belief in a supernatural entity.

THE WALL

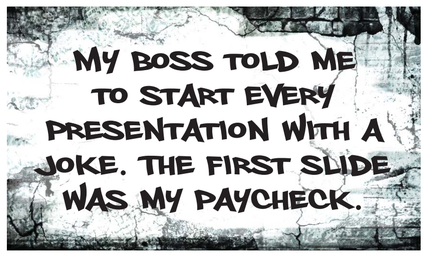

BABY BLUES

By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS

By Jerry Scott & Jim Borgman

अजमेर में दो युवकों पर हमले से आक्रोशित वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन किया

वाल्मीकि समाज के लोगों ने कलैक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की

अजमेर, (कासं)। शहर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों पर हुए हमले के विरोध में मंगलवार को समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग डाक बंगले से रैली के रूप में कलैक्ट्रेट पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना देकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि आक्रोशित लोगों ने कलैक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर लगी बैरिकेडिंग हटाकर परिसर में प्रवेश कर लिया, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ के उग्र होने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इस दौरान कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया। बाद में पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। इसके बाद समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एकत्र हो गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें शांत किया और मामले में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

अजमेर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।

वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि अनिल नरवाल ने बताया कि 8 मार्च की रात करीब 11 बजे गुलाबबाड़ी नाका मदार फाटक क्षेत्र में समाज के दो युवक रघुवीर और अर्जुन किसी काम से जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावर लाठी, सरिया, चाकू सहित अन्य हथियारों से लैस थे और उन्होंने दोनों युवकों को घेरकर मारपीट की। प्रतिनिधियों के अनुसार हमलावरों ने पीड़ित युवकों के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। आरोप यह भी लगाया गया कि हमलावरों ने डर फैलाने के लिए रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग भी की। घटना के बाद दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

परिजनों के अनुसार हमले में रघुवीर के पैर की हड्डी टूट गई है, जबकि अर्जुन को शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। दोनों का उपचार कराया जा रहा है। घटना को लेकर समाज में काफी रोष व्याप्त है। इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

- **पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया**

अजमेर में वाल्मीकि समाज के दो युवकों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कमल कोली और मंथन यादव को गिरफ्तार में लिया है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद वाल्मीकि समाज द्वारा प्रस्तावित अलवर गेट थाने के घेराव का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उदयपुर : वृद्ध का अपहरण करने वाले नौ आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के बड़गांव थाना पुलिस ने जमीन हथियाने के लिए वृद्ध का अपहरण करने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि बदमाश गिरोह बनाकर रजिस्ट्रीयां करवाते हैं, जिसके कागजात पहले से ही तैयार कर रखते हैं। बदमाशों ने रैकी कर योजना के चलते रामा का अपहरण किया, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस के सक्रिय होने पर पकड़े जाने के भय से रामा को साईफन पर छोड़ कर फरार हो गए। किशन मेघवाल निवासी बांसलिया नान्देशमा सायरा व सुरेश मेघवाल निवासी सुहावतों का गुड़ा गोगुन्दा के कहने पर आरोपियों ने रामा का अपहरण किया था। पुलिस किशन, सुरेश व साथियों की तलाश कर रही है।

- **पुलिस के सक्रिय होने पर पकड़े जाने के भय से वृद्ध को छोड़ कर फरार हो गए थे**

प्रकरण के अनुसार 8 मार्च को बंशीलाल पुत्र रामलाल गमेती निवासी हलेलाल नारायण सेवा संस्थान के पास बडगांव ने रिपोर्ट दी कि सवेरे मैं काम से गया था। मेरी मां कंकू बाई व पिता रामा घर पर थे। पिता पास में स्थित पनघट पर पानी लेने गए थे, जहां पर आई कार में सवार बदमाश मुकेश पुत्र मांगीलाल गमेती निवासी लियो का गुड़ा व नन्दु गमेती निवासी शौभागपुरा व विजय कुमार निवासी लखावली व एक अन्य व्यक्ति मेरे पिता का कार में डाल कर अपहरण कर ले गए। आरोपी मेरे पिता के नाम की जमीन हड़पने की नियत से अपहरण कर ले गए।

इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर बडगांव थानाधिकारी किताब देवी के नेतृत्व में गठित दल ने मामले में अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर रामा गमेती को दस्तयाब कर बदमाशों की तलाश कर मामले में मुकेश गमेती पुत्र मांगीलाल गमेती निवासी हाथीधर्रा बडगांव, अशोक बंजारा पुत्र भंवरलाल बंजारा निवासी ईसवाल गोगुन्दा, दीपचन्द्र पुत्र लक्ष्मीलाल गमेती निवासी खरबडिया हिरणमगरी, सुरेश पुत्र लोगर गमेती निवासी काछबा गोगुन्दा, पुष्कर गमेती पुत्र मेघाली निवासी पडियारों का गुडा सुखेर, विजय गमेती पुत्र लालूराम गमेती निवासी पावटा लखावली सुखेर, प्रकाश गमेती पुत्र तख्ता राम गमेती निवासी बीएसएनएल टावर के पास गोगुन्दा, प्रवीण पुत्र पन्नालाल मेघवाल निवासी बांदरवाड़ा गोगुन्दा हॉल आरामशीन की गली बडगांव तथा दिलीप कुमार गमेती पुत्र मोहनलाल गमेती निवासी गोडान कला नाई को गिरफ्तार इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की।

हमलावरों ने एटीएम में युवक से लूटपाट की

गंगापुर सिटी, (निसं)। अपराधियों में पुलिस के भय नहीं होने से आमजन का जीना दुश्वार हो रहा है। कुछ ऐसा ही मामला मंगलवार को देखने को मिला, जिसमें नगर परिषद गंगापुर सिटी के कर्मचारी राहुलराज पुत्र सोमराज से सोमवार शाम एटीएम से 15 हजार रुपए छीन लिए गए। यह घटना हीरालाल की मील के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर हुई।

राहुलराज ने बताया कि सोमवार को शाम को वह एटीएम से पैसे निकाल रहे थे, तभी खुशीराम पुत्र कजोड़मल, किशन पुत्र खुशीराम और बेदराम पुत्र कजोड़मल नामक 3 आरोपी उनके पास आए। आरोपियों ने राहुलराज के साथ मारपीट की और 15 हजार रुपए छीन लिए। पीड़ित के अनुसार, मारपीट के दौरान किशन ने उनकी नाक पर पंच मारा, जिससे उन्हें चोट आई और पीठ पर लात भी मारी। घटना के तुरंत बाद, पीड़ित राहुलराज ने गंगापुर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट और लूट सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

अनूपगढ़ में आवारा श्वानों ने दो साल की बच्ची पर हमला किया

अनूपगढ़, (निसं)। यहां गांव 4 ए में मंगलवार दोपहर एक आवारा कुत्ते (श्वान) ने दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। गंभीर रूप से घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है।

- **कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला, गंभीर घायल बच्ची को बीकानेर रेफर किया**
- **दो बड़ी बहनों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौट रही थी बच्ची, रास्ते में हुई घटना**

जानकारी के अनुसार, हर्षिता (2) अपनी दो बड़ी बहनों प्रीता (5) और हिमांशी (4) के साथ आंगनबाड़ी केंद्र से घर लौट रही थी। घर से लगभग 200 मीटर पहले एक आवारा कुत्ते ने हर्षिता पर अचानक हमला कर दिया। हर्षिता की दोनों बहनें भागकर घर पहुंची और परिवार को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही हर्षिता की दादी राजू देवी और गांव के युवक विनोद कुदावला मौके पर पहुंचे। उन्होंने हर्षिता को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया। हर्षिता को तुरंत अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया।

सरकारी जिला अस्पताल के डॉक्टर केशव कामरा ने बताया कि कुत्ते ने बच्ची के चेहरे को दोनों ओर से नोच लिया है, जिसके कारण उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर किया गया है।

विनोद कुदावला ने बताया कि जब वह मौके पर पहुंचे, तब तक कुत्ता हर्षिता को छोड़ चुका था। वह अपनी बाइक पर हर्षिता और उसकी दादी राजू देवी को अस्पताल ले गए।

निवाई कृषि उपज मंडी में सरसों की बम्पर आवक

निवाई, (निसं)। कृषि उपज मंडी में सरसों की आवक लगातार बढ़ रही है। खेतों से कटाई के बाद किसान सीधे मंडी में पहुंच रहे हैं, जिससे मंडी में रौनक बढ़ गई है। मंगलवार को मंडी में सरसों की रिकॉर्ड करीब 60-70 हजार बोरी की आवक दर्ज की गई।

व्यापार मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश चंवरिया व ताराचन्द बोहरा ने बताया कि आवक बढ़ने के साथ सरसों के भाव भी बढ़े हैं। सरसों अधिकतम 6351 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकी है। उन्होंने बताया कि निवाई के आसपास के गांवों सहित चाकसू, बौंली एवं पीपलू क्षेत्र से भी किसान सरसों लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। अधिकांश किसानों की फसल कटाई पूरी हो चुकी है और वह खेतों से सीधे मंडी में उपज को लेकर आ रहे हैं।

व्यापारी दीपक गुप्ता व राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में सरसों की आवक और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि मंडी में होली के त्यौहार के बाद करीब साढे तीन लाख सरसों की बोरियों की आवक हुई है। इससे मंडी में व्यापारिक गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

अजमेर रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित कार सेवा का ट्रायल शुरू

अजमेर, (कासं)। अजमेर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाली कार सेवा की शुरुआत कर दी गई है। यह सेवा विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में मदद करेगी। फिलहाल इस सेवा को ट्रायल बेस पर शुरू किया गया है और इसके सफल संचालन के बाद इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा।

- **विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार यात्रियों को राहत मिलेगी**

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मिहिर देव ने बताया कि रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को लगातार बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में अजमेर रेलवे स्टेशन पर बैटरी ऑपरेटेड कार सेवा शुरू की गई हैद्ध ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म और ट्रेन तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि यह बैटरी संचालित कार एक बार में पांच यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। यात्री इस सेवा का लाभ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित हेड टीसी ऑफिस या सहायता बूथ पर संपर्क करके ले सकते हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा, जबकि पांच वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए 30 रुपये प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। फिलहाल एक बैटरी संचालित कार का संचालन किया जा रहा है, लेकिन यात्रियों की संख्या और आवश्यकता के अनुसार भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।

पाक की ओर से ड्रोन से फेंकी गई थी हेरोइन

श्रीगंगानगर, (निसं)। भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले में करीब 32 करोड़ रुपए की हेरोइन मिली है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से 6 किलो 400 ग्राम फेंकी गई। इसे समेजा कोठी थाना पुलिस और बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र के गांव 43 पीएस की है। गांव के एक खेत में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन द्वारा 6 किलो 400 ग्राम फेंकी गई थी। मामले में बीएसएफ ने एक तस्कर को पकड़ा है।

- **पंजाब के एक तस्कर को पकड़ा, आरोपी के साथ दो अन्य तस्कर भी थे**
- **आरोपी से पुलिस, बीएसएफ और अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है**

आरोपी हेरोइन की खेप लेने बॉर्डर के पास पहुंचा था, जिसे भारतीय जवानों ने पकड़ लिया। तस्कर पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला है। आरोपी से पुलिस, बीएसएफ और अन्य एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है कि तस्कर हेरोइन को कहां ले जाने वाला था और क्या उसके अन्य साथी भी मौके पर थे। साथ ही तस्करी के पूरे नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। इस बीच रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, समेजा कोठी समेत आस-पास के थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे खेतों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच में सामने आया कि आरोपी के साथ दो अन्य तस्कर भी थे, लेकिन दोनों फरार हो गए। दोनों की तलाश की जा रही है।

गर्मी की दस्तक के साथ ही दौसा में जलापूर्ति की मांग बढ़ने लगी

दौसा, (निसं)। सूरज के तीखे तेवर एवं समय से पूर्व गर्मी के दस्तक दिये जाने के साथ ही जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। इधर तापमान 35 से 40 के पार पहुंचने के साथ ही हीटवेव की संभावनायें बढ़ गई है। वही दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर के चलते शहर में जलापूर्ति की मांग भी बढ़ने लगी है, अगर यही हालात रहे तो इस पर प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

- **गर्मी के यही हालात रहे तो इस पर प्रशासन को भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है**
- **वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है**

उल्लेखनीय है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरु कर दिये हैं, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। तापमान 35 से 40 डिग्री के बढ़ने के साथ ही दौसा जिले में हीटवेव की संभावनायें बढ़ गई है। भीषण गर्मी व सूरज के तीखे तेवर के चलते दोपहर बाद शहर के मुख्य मार्गों पर अघोषित कर्फ्यू के हालात पैदा हो गये हैं। वहीं दूसरी ओर गर्मी के तीखे तेवर ऐसे ही रहे तो इस बार गर्मी में शहर की जलापूर्ति गड़बड़ा सकती है। वर्तमान में शहर की अधिकांश आवासीय कॉलोनियों में 3 से 4 दिन में जलापूर्ति की जा रही है। जैसे ही गर्मी का असर ओर तेज होगा, वैसे की पानी की मांग बढ़ सकती है। ऐसे में हालात बेकाबू हो सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही भीषण गर्मी ने जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग के आला अधिकारियों की नींद उडा दी है। इधर राज्य सरकार द्वारा मार्च तक दौसा शहर मे ईसरदा बांध से जलापूर्ति का दावा किया गया था, ये दावा भी खोखला साबित हो गया है। बताया जाता है कि वर्तमान में 25 प्रतिशत से अधिक काम शेष है तथा शहर की कई कॉलोनियों में अभी तक पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है, लोग पाइपलाइन का भी इंतजार कर रहे हैं। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, भीषण गर्मी के चलते ग्रामीणों में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। अधिकांश किसानों ने गेहूं की फसल तक नहीं काटी है, इस गर्मी में फसल काटने के लिए मजदूर नही मिल रहे हैं।

शाम होते ही बढ़ जाती है उमस

:- दिन में सूरज की तपीस एवं सांझ ढलने के साथ ही उमस का अहसास होने लग जाता है, जिसके चलते गर्मी में लोगो के हाल बेहाल हो रहे हैं। अधिकांश लोगों ने घरों में एसी एवं पंखे चलाना शुरु कर दिया है। कुछेक दिनों में कूलर भी चालू हो जायेंगे। पंखे अभी से आग उलग रहे हैं।

मौसमी बीमारी बढ़ने की संभावना:- मार्च के प्रथम सप्ताह में गर्मी के दस्तक दिये जाने के साथ ही शहर में मौसमी बीमारी फैलने की भी संभावना बढ़गई है। चिकित्सा विभाग ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी शुरु कर दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी चिकित्सकों ने मुख्यालय पर रहने के लिए पाबंद किया है। साथ ही मौसमी बीमारी से निपटने के निर्देश दिये हैं। जिला चिकित्सालय में आउटडोर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है।

सफाईकर्मियों की हड़ताल से करौली शहर में पसरी गंदगी

करौली, (निसं)। नगर परिषद के संवेदक सफाईकर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगने से शहर का वातावरण दूषित हो रहा है, लेकिन नगर परिषद प्रशासन की ओर से अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से आमजन में नाराजगी है।

- **बताया जा रहा है कि संवेदक कर्मचारियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिला है**

बताया जा रहा है कि संवेदक कर्मचारियों को लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण वे हड़ताल पर चले गए हैं। यह स्थिति पहली बार नहीं है, बल्कि मानदेय नहीं मिलने के कारण समय-समय पर संवेदक कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। शहर में इन दिनों कैलादेवी मेले की तैयारियां चल रही हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। कोतवाली के पास कचरे के ढेर जमा होने से वहां आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे श्री मदनमोहनजी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार हिंडौन दरवाजा मार्ग पर गंदी नालियों का पानी दिनभर सड़क पर बहता रहता है, जिससे राहगीरों को काफी कठिनाई होती है। स्थानीय लोगों ने कई बार नगर परिषद और जिला प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सूत्रों के अनुसार सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण नगर परिषद प्रशासन और कुछ पार्षद प्रतिनिधि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों से सफाई करवाने का दबाव बना रहे हैं, जिससे अग्निशमन कर्मियों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।

कोर्ट ने भारत-पाक बॉर्डर पर 7.58 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री रद्द की

'नोटिफाइड एरिया में बिना परमिशन के जमीन खरीद-बेच नहीं सकते'

बीकानेर, (निसं)। भारत-पाक बॉर्डर से सटे नोटिफाइड क्षेत्र में बिना अनुमति जमीन की खरीद-फरोख्त पर बीकानेर जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बॉर्डर एरिया पूगल में 7.58 हेक्टेयर कृषि भूमि की वर्ष 2006 में हुई रजिस्ट्री को रद्द (शून्य) घोषित कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नोटिफाइड एरिया में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना जमीन खरीदना-बेचना कानून के खिलाफ है, इसलिए ऐसी रजिस्ट्री प्रभावहीन मानी जाएगी। फैसले के बाद संबंधित भूमि अब सरकारी नियंत्रण में रहेगी।

- **जांच में सामने आया कि भूमि खरीदने से पहले कलेक्टर और एसडीएम से प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि खरीदने की आवश्यक अनुमति नहीं ली थी, जबकि नोटिफाइड बॉर्डर एरिया में जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले यह अनुमति लेना जरूरी होता है**

अपर लोक अभियोजक शिवशंकर स्वामी ने बताया कि ऐसे करीब 200 मामलों को जिला न्यायालय में पेश किया गया था। इनमें से एक मामला राज्य सरकार बनाम दर्शन सिंह का था, जिसकी सुनवाई एडीजे-5 कोर्ट में हुई। 26 फरवरी 2026 को अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। जांच में सामने आया कि दर्शन सिंह ने भूमि खरीदने से पहले कलेक्टर और एसडीएम से प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि खरीदने की आवश्यक अनुमति नहीं ली थी, जबकि नोटिफाइड बॉर्डर एरिया में जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले यह अनुमति लेना जरूरी होता है।

बीकानेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े बज्जू, पूगल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला क्षेत्रों की सीमा से सटी जमीन को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफाइड एरिया घोषित किया हुआ है। मामले के अनुसार पूगल तहसील के गांव करकरी भासियान में खसरा नंबर 1275, 1314, 2663/1274 और 1278 की कुल 7.58 हेक्टेयर कृषि भूमि के सेल एग्रीमेंट को 29 मई 2006 को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस पूगल में रिकॉर्ड कराया गया था। बाद में इस जमीन के सौदे को लेकर विवाद सामने आया, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में वाद दायर किया। ऐसे क्षेत्रों में जमीन की खरीद-फरोख्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में बिना अनुमति के ही जमीन को बेच दिया गया था। इसलिए रजिस्ट्री को निरस्त करने की मांग की गई।

जिला कोर्ट बीकानेर ने राजस्थान राज्य बनाम दर्शन सिंह प्रकरण में सुनवाई करते हुए माना कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति भूमि का हस्तांतरण कानून के खिलाफ है। कोर्ट ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी समझौते का उद्देश्य कानून के खिलाफ हो, तो ऐसा समझौता स्वत: शून्य माना जाता है। कोर्ट ने 29 मई 2006 को सब रजिस्ट्रार ऑफिस पूगल में दर्ज सेल एग्रीमेंट को अवैध और शून्य घोषित करते हुए रजिस्ट्री निरस्त करने के आदेश दिए। इसके साथ ही संबंधित भूमि को सरकारी नियंत्रण में रखने का निर्देश दिया गया।

बीकानेर जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से जुड़े बज्जू, पूगल, छत्तरगढ़ और खाजूवाला क्षेत्रों की सीमा से सटी जमीन को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफाइड एरिया घोषित किया हुआ है। इन क्षेत्रों में जमीन खरीदने के लिए पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी होता है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि खरीदार की यह जिम्मेदारी थी कि वह पहले यह सुनिश्चित करता कि जमीन नोटिफाइड क्षेत्र में तो नहीं आती। खरीदार बाद में यह तर्क नहीं दे सकता कि उसे केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की जानकारी नहीं थी।

घर में लगी आग से सामान जला

सूरौठ, (निसं)। तहसील के बंजारों के नंगला में मंगलवार दोपहर को शॉर्ट सर्किट के कारण एक छप्परपोश घर में आग लगने से घर में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना के समय घर के सदस्य बच्चों की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर को दिखाने गए हुए थे, जिससे घर पर कोई मौजूद नहीं था।

पूर्व पार्षद दशरथ सिंह बंजारा ने बताया कि दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई। पास में रहने वाले एक पड़ोसी ने आग लगने की सूचना देते हुए शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और मिलकर आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि पास के दो अन्य मकान आग की चपेट में आने से बच गए। घटना के दौरान घर के अंदर रखा एक गैस सिलेंडर भी मौजूद था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई थी। आग लगने से एक पंखा, दो चारपाइयां, एक गैस चूल्हा, करीब 20 छोटे-बड़े बर्तन, दो पानी के कलश, अनाज तथा बिस्तर जलकर नष्ट हो गए। आग बुझाने में रणजीत बंजारा, मनोज, उल्फत, हरकेश, रमेश, पप्पू, अमृत, हुलासी, आकाश, राधे सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने सहयोग किया और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से पीड़ित परिवार को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है।

सीकर में 200 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त

सीकर, (निसं)। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करते हुए प्रशासन ने मंगलवार को पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्लास्टिक पर्यावरण संरक्षण अभियान और मिशन लाइफ के तहत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर एवं नगर परिषद सीकर की संयुक्त टीम ने कई दुकानों व गोदामों पर छापेमारी कर सघन जांच की। जांच के दौरान नियमों की अवहेलना करते हुए भंडारण एवं बिक्री किए जा रहे करीब 200 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद किए गए, जिन्हें मौके पर ही जब्त कर लिया गया। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर 10,500 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया।

कार्रवाई प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी सविता के मार्गदर्शन तथा जिला कलैक्टर मुकुल शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुई। अभियान में राजस्व अधिकारी प्रमोद कुमार सोनी, प्रवर्तन दल के सदस्य, सहायक कर्मचारी सुरेश निठारवाल, कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता ओजस्व कड़वासरा और सूचना सहायक कुलदीप सहित मंडल एवं नगर परिषद के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में एडमिशन 14 मार्च से शुरू होंगे

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में संचालित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों तथा राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 2026-27 के लिए एडमिशन प्रोसेस 11 मार्च से शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस संबंध में सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और विद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। इसमें 14 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकेगा, वहीं 27 मार्च को स्टूडेंट की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एक अप्रैल से सेशन शुरू हो जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए अभिभावकों को शाला दर्पण पोर्टल या क्यूआर कोड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निर्धारित सीटों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। निर्देशों के अनुसार जिन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी/बाल वाटिका संचालित हैं, वहां नर्सरी कक्षा में सभी सीटों पर नए प्रवेश दिए जाएंगे। अन्य कक्षाओं में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों के प्रमोशन के बाद बची सीटों पर प्रवेश होगा। प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन में कमी आई है। पिछले साल भी उपलब्ध सीटों से कम आवेदन मिलने के कारण अनेक स्कूलों में लॉटरी की जरूरत ही नहीं पड़ी।

संक्षिप्त

बैठक आयोजित

बौंली- बामनवास। मित्रपुरा एवं बौंली तहसील क्षेत्र के निजी विद्यालय शिक्षा परिवार की बैठक बौंली उपखंड मुख्यालय के एक निजी विद्यालय में आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता महावीर सिंह नाथावत ने की आयोजित बैठक में निजी स्कूल शिक्षा परिवार का जिला स्तरीय अधिवेशन 3 अप्रैल 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया बैठक के दौरान जिला स्तरीय वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना को एवं मुख्य वक्ता के रूप में स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा को बुलाने पर विचार विमर्श किया गया बैठक के दौरान निजी स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया, जिसमें निजी स्कूल के संचालन में आ रही आरटीई का दो वर्ष से लंबित भुगतान व कक्षा 5 बोर्ड का परीक्षा शुल्क लेना साहित विभिन्न मांगे शामिल है

कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भरतपुर । प्रशासन द्वारा शहर में कराये जा रहे सौंदर्यीकरण एवं निर्माण कार्यों की वजह से आम जनता को हो रही भीषण समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सूपा के निर्देशन में जिले के वरिष्ठ पदाधिकारीयों के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर कमर चौधरी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि निर्माण कार्यों की वजह से पूरे शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा नहीं की गई है तथा नल, बिजली, पानी एवं सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़क के आर पार खुदाई कर दी गई है जिनकी बाद में ना तो लेबलिंग की गई है ना डाबरीकरण किया गया है। जिससे वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं।

दो दिवसीय वाक्पीठ संगोष्ठी 27 को

निवाई। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिणक गुणवत्ता को सुदृढ करने के उद्देश्य से राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की जिला स्तरीय वाक्पीठ संगोष्ठी का आयोजन 27 एवं 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। वाकपीठ के सचिव रामकिशोर सैनी राहोली ने बताया कि दो दिवसीय संगोष्ठी में विभिन्न राजकीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापक सम्मलित होकर शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों, प्रभावी विद्यालय प्रबंधन, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा आधुनिक शिक्षण पद्धितयों जैसे विषयों पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि संगोष्ठी का मुख्य ध्येय सरकारी विद्यालयों में एक बेहतर और सकारात्मक शैक्षिणक वातावरण तैयार करना है।

शिवमहापुराण कथा का आयोजन

कोटपूतली। कस्बे के तालाब वाले प्राचीन श्री शिव मंदिर में 12 मार्च गुरुवार से 20 मार्च शुक्रवार तक 09 दिवसीय संगीतमय श्री शिवमहापुराण कथा का आयोजन किया जायेगा। कथा का वाचन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से पधारे श्री श्री 1008 श्री चतुर्भुज दास महाराज के शिष्य श्री शिवमहापुराण कथा के राष्ट्रीय कथा वाचक राष्ट्रीय संत स्वामी कमलदास बापू करेंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 02:15 बजे से सायं 05:15 बजे तक होगी। 12 मार्च गुरुवार को प्रात: 08:15 बजे विशाल कलश यात्रा भगवान श्री परशुराम के मंदिर से निकाली जायेगी।

दांडी मार्च कल

टोंक। दांडी मार्च कि स्मृति में 12 मार्च को शांति मार्च पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया जायेगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति टोंक के संयोजक सुनील बंसल ने बताया 12 मार्च का दांडी मार्च यात्रा निकाली जायेगी, जो बस स्टैंड से घंटाघर तक होगी।

खोया पाया

8/2 मालवीय नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र डिक्लेरेशन लेटर कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। 9414330026

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

करणी माता मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक आयोजित

अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं शहर बीना महावर ने करणी माता के मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक ली।

- मेले का 19 मार्च से 27 मार्च तक होगा आयोजन
- अतिरिक्त जिला कलक्टर ने विभागीय अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन हेतु आपसी समन्वय रखते हुए सौंपे गये दायित्वों को पूर्ण करने के निर्देश दिये

अलवर । अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम एवं शहर बीना महावर की अध्यक्षता में आज आगामी 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होने वाले बाला किला स्थित करणी माता के मेले की व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मेले के सफल आयोजन हेतु आपसी समन्वय रखते हुए सौंपे गये दायित्वों को यथासमय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि मेले में श्रृद्धालुओं के प्रवेश का समय प्रात: 6 बजे से सांय 7 बजे तक रहेगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिये कि मेले में नियमित रूप से साफ-सफाई कराने के साथ कचरे का उठाव करावे। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि मेले में आवश्यकतानुसार पेयजल की व्यवस्था करावे एवं निर्धारित जगहों पर मोबाइल टॉयलेट लगवाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि भण्डारे करने की अनुमति देते समय आयोजनकर्ता को पर्याप्त संख्या में भण्डारा स्थल पर कचरा पात्र रखने के लिए पाबन्द करें एवं कचरे का निस्तारण विधिवत रूप में करें और सुनिश्चित करावें कि कचरा वन क्षेत्र में नहीं फेंके तथा भंडारे में प्रसाद हेतु प्लास्टिक डिस्पोजल उत्पाद का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। पेड के पत्तों से बने पत्तल, दूने एवं मिट्टी के कुल्हडों का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में डी.जे. व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंधित रहेगा। इसकी पालना सुनिश्चित करावे। उन्होंने कहा कि प्रसाद की दुकानों का स्थान इस प्रकार निर्धारित करें कि श्रद्धालुओं को आने-जाने में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि मेला स्थल एवं बाला किला क्षेत्र में पॉलिथिन की थैलियां व प्लास्टिक डिस्पोजेबल उत्पाद ले जाने व उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देश दिये कि मेला स्थल पर आमजन को चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सा दलों का गठन कर आवश्यकतानुसार चिकित्सक एवं पैरा मैडिकल स्टाफ लगाएं।

उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वन नाका से मन्दिर तक के रास्ते में श्रृद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जहां आवश्यक हो वहां स्पीड ब्रेकर संकेतक आदि लगाए जाएं।

उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिए कि मेले में वृद्ध, असहाय एवं दिव्यांग लोगों को लाने व ले जाने के लिए एक अलवर वाहिनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर विकास न्यास के अधिकारियों को मेला स्थल पर रोशनी, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मंदिर तक जाने वाले रास्ते पर श्रृद्धालुओं के अल्पकालीन विश्राम हेतु छाया एवं पानी की व्यवस्था कराए।

उन्होंने कहा किउन्होंने कहा कि चार पहिया वाहनों को वन विभाग के नाके से आगे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी, किन्तु मेला व्यवस्था में लगे वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि मेला स्थल पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर वायरलैस सैट उपलब्ध कराया जायेगा।

रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम में पंजीकरण प्रारम्भ

कोटपूतली। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान फिनिशिंग स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित महाविद्यालय में रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना है। राजकीय एलबीएस पी जी महाविधालय के प्राचार्य डॉ. आर. के. सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय में दो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जा रहे हैं। यह दो कोर्स हैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर में ही राज्य सरकार द्वारा चयनित एजेंसी के विशेषज्ञों द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट स्किल्स संचार कौशल तथा कार्यानुभव आधारित ज्ञान प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर विद्यार्थियों को संबंधित एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना में केवल प्रदेशभर में 259 ने फायदा उठाया

- राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से 2024 में मुख्यमंत्री ने शुरू की प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना

किशनगढ़ बास। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के उपचार और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से 2024 मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना लेकर आए। लेकिन विडंबना रही की अभी तक इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ खैरथल तिजारा जिले का एक भी व्यक्ति नहीं उठा पाया वहीं पूरे राजस्थान में केवल 259 लोग ही उठा पाए हैं। मुख्यमंत्री की इस योजना को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव रहा है या फिर सरकार के सिस्टम में कहीं कमजोरी रहीं हैं यह सरकार व मुख्यमंत्री को देखनी होगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्बल योजना राज्य के ऐसे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण पहल है जो भारत सरकार की राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारियों से पीड़ित हैं। इस योजना का उद्देश्य गंभीर और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना और उनके परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने बताया कि राजस्थान में 259 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

इस योजना में पात्र बच्चों को उपचार के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों की देखभाल और आवश्यक खर्चों के लिए प्रति माह 5000 रुपये की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। यह योजना राज्य के ऐसे बालक, बालिकाओं के लिए है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन्हें राष्ट्रीय नीति के अनुसार दुर्लभ बीमारी से पीड़ित प्रमाणित किया गया है, वे आर्थिक सहायता के पात्र होंगे। इस योजना में माता-पिता या पालनकर्ता की आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद परिवार इसका लाभ उठा सकें।

दुर्लभ बीमारी का प्रमाणन केवल अधिकृत चिकित्सा संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर तथा जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर को अधिकृत किया गया है। इन संस्थानों के सक्षम चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद यदि किसी बच्चे में दुर्लभ बीमारी की पुष्टि होती है, तो उसे योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें उपचार के लिए सरकार द्वारा गठित दुर्लभ बीमारी निधि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के अनुदान के साथ-साथ क्राउड फंडिंग, दानदाताओं और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से प्राप्त राशि भी शामिल की जा सकेगी।

बैठक आयोजित

टोंक। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कक्ष में बैठक ली। राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 15 मार्च से होगा। समारोह के तहत जिले भर में 15 से 19 मार्च तक विकसित राजस्थान रन, राजस्थान को जाने क्विज, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, मंदिरों में आरती समेत विविध कार्यक्रम होंगे। राजस्थान को जाने क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता जिले भर के महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में आयोजित होगी। जिले में ओडीओपी मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। 16 मार्च को राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस, 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस, 18 मार्च को मंदिरों में आरती, 19 मार्च को राजस्थान दिवस के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बैठक में एडीएम रामरतन सौंकरिया, सीईओ परशुराम धानका, एडीएम बीसलपुर भूपेंन्द्र यादव, एएसपी रतनलाल भार्गव, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक, मधुसूदन, एसडीओ टोंक हुक्मीचंद रोहलानिया, एसीपी श्याम सुंदर जांगिड़ समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।

सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उमड़ा समाज

सावित्रीबाई फुले सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया।

लालसोट। देश की प्रथम महिला शिक्षिका व महान समाज सुधारक की 129वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को लालसोट के सावित्रीबाई फुले सर्किल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाजबंधुओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सावित्रीबाई फुले ने करते हुए लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर सामाजिक परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। आज उनका जीवन संघर्ष समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है।

समिति के सचिव राजेश सैनी मालवाला ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित समाजबंधुओं ने शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले सेवा समिति के अध्यक्ष किशनलाल सैनी धाकड़ा, उपाध्यक्ष हरकेश सैनी सोनंदा, कोषाध्यक्ष श्रवण कुमार माली जमात, सहसचिव गिर्राज प्रसाद सैनी डीडवाना, माली महासभा चौरासी के सभापति डॉ. रामनारायण वेध, गिर्राज प्रसाद सैनी कंछला, श्रवण सैनी धाकड़या, सावित्री सैना, मुकेश सैनी बगड़ी, पदम सैनी फड़कल्या, कांजीलाल सैनी खटवा, जयप्रकाश सैनी व हंसराज सैनी पार्षद सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक ध्वनिमत से पारित

- राजधानी जयपुर में आमेर के पास बनेगा विश्वविद्यालय

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक चर्चा और सुझावों के बीच ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के पास स्थापित किया जाएगा।
विधेयक पर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे, वहीं कुछ सदस्यों ने इस पर जनमत लेने और पुनर्विचार की मांग भी की। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए खेल मंत्री कनर्ल राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि आज खेल केवल खेल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग 10 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में खेलों की अर्थव्यवस्था करीब 520 बिलियन डॉलर यानी लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि भारत में यह करीब 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्रिकेट का है। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित होने से खेलों से जुड़े कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फिजियोथैरेपिस्ट, डेटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिकल डॉक्टर और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।

कलेक्टर ने पंच गौरव के लिए कार्ययोजना एवं प्रचार प्रसार के संबंध में निर्देश दिए

कोटपूतली । राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही आर्थिक उन्नित एवं रोजगार के अवसरों में बढोतरी कर प्रदेश के सभी जिलों के सर्वागीण विकास हेतु राज्य में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोटपूतली-बहरोड़ जिले की विरासत एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए पंच गौरव के रूप में एक जिला-एक उत्पाद में ऑटोमोबाईल पार्टस, एक जिला-एक उपज में गाजर, एक जिला-एक वनस्पति में गूगल, एक जिला-एक खेल में कुश्ती, एक जिला-एक पर्यटन स्थल में बैराठ चिहित किये गये हैं।

योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पंच गौरव कार्यक्रम के लिए प्राप्त बजट से योजना के प्रभावी क्रियान्वयन सहित आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के संबंध में चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने पंच गौरव के संरक्षण और संवर्धन व प्रचार प्रसार के लिए वन, कृषि, उद्योग, पर्यटन और खेल विभाग को ठोस कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित कर कहा की पंच गौरव के लिए विस्तृत रोडमैप बनाएं। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना में विज्ञापन, उत्सव, प्रचार स्टॉल, कार्यशाला, बुकलेट, पंपलेट पर आवश्यक व्यय की कार्य योजना तैयार हो। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से पंच गौरव योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर ओमप्रकाश सहारण, एसीईओ हरिओम मीणा, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी अखिल गुप्ता एवं विसंभर दयाल गुर्जर , संयुक्त निदेशक कृषि लीला राम जाट, जिला उद्योग अधिकारी भंवरलाल सैनी, एसीएफ तरुण प्रकाश यादव, खेल विभाग से जसवीर सिंह सहित समबन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

NAME CHANGE

My name is Dushar Jain, son of Rakesh Kumar Jain. In my school documents, CBSE Board and other school documents, it is written as DUSHAR JAIN BHILASPURIYA. Whereas in my Aadhar card, Janadhar card, birth certificate etc. documents, it is written as Dushar Jain. Now I am keeping my name as Dushar Jain, in future I should be known and recognized only by the name Dushar Jain.
Dushar Jain S/O Rakesh Kumar Jain R/O in front of Sabeel Shah's post, Tonk (Raj.)

आम सूचना दिनांक-10.03.2026

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल मोहम्मद अकबर पुत्र मौहम्मद आशिक निवासी ए-306 शिव मार्ग राजपूत टीला, भट्टावस्ती, जयपुर का पुत्र सलीम मेरे मुवक्किल के कहने में नहीं है तथा उसने अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली है एवं मेरे मुवक्किल के साथ आये दिन लड़ाई झगडा करता है तथा परेशान करता है इस कारण मेरे अभिभाष्य ने अपने पुत्र सलीम को अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है इसलिए आज से सलीम का मेर मुवक्किल की चल-अचल सम्पत्ति से कोई संबंध व हक अधिकारी नहीं रहा है। सलीम पुत्र मौहम्मद अकबर द्वारा किये गये लेन-देन संव्यवहार व कृत्यों के बारे में मेरे मुवक्किल की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अत सूचित रहे।
(नवल किशोर सिंघल) एडवोकेट, मो. 9314876234

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम (MOHAMMED SHOAIB) से बदलकर (MOHD SHOAIB) पुत्र अब्दुल वहीद निवासी 1020 चार दरवाजा गंगापाल रोड जयपुर रख लिया है भविष्य में मुझे (MOHD SHOAIB) के नाम से जाना पहचाना जावें।

मेरा नाम आरती विजय (ARTI VIJAY) है। जबकि अन्य दस्तावेजों में आरती विजय (AARTI VIJAY) दर्ज है। भविष्य में मुझे आरती विजय (AARTI VIJAY) पत्नी श्री नवीन विजय के नाम से जाना पहचाना जावें। निवासी 90 नन्दपुरी मालवीय नगर जयपुर-902017 राज.

मैंने अपना नाम परमानन्द साजानी से बदलकर परमानन्द महादेव साजानी कर लिया है। परमानन्द महादेव साजानी निवासी मकान नं. 12/224-बी, शंकर नगर निर्मल स्कूल के पीछे, आमेर रोड, जयपुर (राजस्थान) भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें।

इंतेजामिया वक्फ कमेटी दरगाह अमानीशाह जयपुर

दरगाह अमानीशाह जयपुर

क्रमांक-506/26 दिनांक-09.03.2026

टेंडर सूचना

दरगाह हजरत दाता अमानीशाह जयपुर में दिनांक 11.03.2026 से झूले के टेंडर फार्म भरे जाकर दिनांक 17.03.2026 को दोपहर 3 बजे को राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड एल के 1 ज्योति नगर जयपुर में खोले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कमेटी के दफ्तर में संपर्क करें।
सदर जमील उर्रहमान फारूकी
इंतेजामिया वक्फ कमेटी
दरगाह अमानीशाह जयपुर, मो.नं. 9887747786

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-10707 दिनांक-05.03.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास संख्या 268/03 (MIG-B), का आवंटन श्री हेमेन्द्र माथुर पुत्र स्व. श्री दुर्गा प्रसाद माथुर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1662 दिनांक 30.06.2007 के द्वारा जारी किया गया था। श्री हेमेन्द्र माथुर द्वारा श्री कालू सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह को दिनांक 26.06.2008 को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री कालू सिंह द्वारा श्री हेमेन्द्र माथुर के पक्ष में पंजीयन निष्पादन दिनांक 28.07.2008 को करवाया गया। श्री कालू सिंह द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से पंजीयन पश्चात उक्त आवास का विक्रय कर श्री आकेश जैन पुत्र श्री अजय जैन को दिनांक 31.07.2008 विक्रय पत्र उप पंजीयक (अष्टम) जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री आकेश जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 19.05.2010 को श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री छिट्टा राम शर्मा को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र उप पंजीयक अष्टम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात आवेदक श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन करने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3194 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा मण्डल रिकार्ड में इनका नाम दर्ज किया गया। श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 17.09.2021 को श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल को Exchange Deed कर उनके पक्ष में बदल पत्र उप पंजीयक द्वितीय जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमती माया देवी अग्रवाल पत्नी श्री शिव कुमार अग्रवाल का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप) व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय ADJ No. 2 साहब स्थान हिण्डौन

आरती विरुद्ध हरिओम

वाद/प्रार्थना पत्र Ti c.m.

प्रार्थना-पत्र संख्या 13 सन् 2019

नाम वन्दना टंडन पुत्री टेकचन्द पत्नि श्री अमित टंडन जाति पंजाबी पता नि. प्लाट नं. 117, फ्लेट नं. 202, चौधरी रोड्, राम नगर, पत्रकार कॉलोनी जयपर (राज.)।

उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 13 माह 03 सन् 2026 को 10.30 A.M. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता. 09 माह 03 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से-
(मुहर) सीनीयर रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन सिटी (करौली)

विवाधको के स्थरीकरण के लिए सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय ADJ No. 2 साहब स्थान हिण्डौन

आरती विरुद्ध हरिओम

वाद बावत दावा वाद सं. 13 सन् 2019

बनाम 1. वन्दना टंडन पुत्री टेकचन्द पत्नि श्री अमित टंडन जाति पंजाबी स्थान नि. प्लाट नं. 117, फ्लेट नं. 202, चौधरी रोड्, राम नगर पत्रकार कॉलोनी जयपर ने आपके विरूद्ध के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 13 माह 03 सन् 2026 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित्त साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल /सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं. तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह वाद ता. 09 माह 03 सन् 2026 का मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
आज्ञा से- सीनीयर रीडर
(मुहर) अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश सं. 2 हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1818

चूंकि प्रार्थी श्री मुकेश मित्तल 599/5 पटेल नगर वार्ड नंबर 6 गुडगांव हरियाणा 122001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास शनि धाम मंदिर संस्थान शनि धाम K N D स्कीम ग्राम कंवरपुरा कोटखावदा जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1591

चूंकि प्रार्थी श्री हरिओम दास मंदिर परिसर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज परमानन्द धाम ग्राम खोरी शाहपुरा जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज परमानन्द धाम मंदिर परिसर श्री लक्ष्मीनारायण जी महाराज परमानन्द ग्राम खोरी शाहपुरा जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 10.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14.05.2026
(मोहर अदालत) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान

हेमन्त कुमार बनाम कमल सिंह

मु.नं. 238/22/25

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी हेमन्त कुमार पुत्र श्री भगत सिंह निवासी सुखम टॉवर, भगत सिंह कॉलोनी भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान-301019 ने न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवाडी में कमल पुत्र श्री कॅवर सिंह निवासी डी-2 करणी पैलेस रोड, बजरी मंडी रोड, भुवनेश्वरी वाटिका पॉचावाला, जयपुर राजस्थान के विरूद्ध दावा वसूली बाबत सिविल वाद दायर किया है। जिसकी आगामी पेशी दिनांक 30.03.2026 न्यायालय श्रीमान जी द्वारा नियत की गई है। यदि प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई एतरज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 30.03.2026 को स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर अदालत होकर अपना पक्ष रख सकता है। अन्यथा न्यायालय श्रीमान जी के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही विधिवत कर दी जावेगी।
आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर व सील मोहर से कार्यालय के द्वारा जारी किया गया।
आदेशानुसार
(मोहर अदालत) रीडर ग्रेड-प्रथम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवाडी, जिला खैरथल-तिजारा, राजस्थान

(देखिए नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को (नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नं. 364/2026

चूंकि श्री बृजमोहन वर्मा निवासी वार्ड न. होली दरवाजे के बाहर चौमूं जिला जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास विद्या भारती जयपुर जन शिक्षा न्यास कार्यालय सेवाधाम परिसर जवाहर नगर सेक्टर-4, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जाच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस को जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तिया यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।
आज दिनांक 09.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइन्दा तारीख पेशी 15.05.2026
(मोहर) सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम,प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-10442 दिनांक-23.02.2026

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर योजना में आवास संख्या 163/303 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गुलाब चन्द को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1466 दिनांक 29.09.1999 को जारी किया गया। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 25.05.2000 को प्राप्त कर लिया गया। श्री रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 15.01.2009 को हो जाने के कारण घोषणा पत्र के आधार एवं शपथ पत्र इनके पुत्र श्री विनोद कुमार उमरवाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र उमरवाल द्वारा उक्त आवास स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री विनोद कुमार उमरवाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र उमरवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-30200

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2026/D-150

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 273126

दिनांक 20/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृनि. स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	Madhu W/o Ashok Kumar	श्रीमती बूली बाई पत्नी स्व. श्री झामनदास एवं मधु पत्नी श्री अशोक कुमार	354	60.00 SQ. YARD	Cooperative	SACHIWALYA VIHAR SCHEME NO.27 Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	[illegible]

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection Module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली

प्रेम विज्ञप्ति

क्र.स.	नाम शिशु	उम्र	लिंग	शिशु प्राप्ति स्थल	प्रवेश का माध्यम	शिशु का फोटो
1	अयान (रखा गया नाम)	लगभग 5-6 दिन	F	राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास, करौली स्थित पालना गृह	बाल कल्याण समिति, करौली	

नोट:- उक्त शिशु का पुनर्वास/दत्तक ग्रहण किय जाना है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के अंदर कार्यालय अधीक्षक राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास करौली में आकर आपत्ति प्रस्तुत करावें।
दूरभाष नम्बर :- 07464-294625 (9982402482, 9636038008) ई-मेल आईडी adicps-karauli@gov.in

सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग करौली

संक्षिप्त

निःशुल्क चिकित्सा शिविर रविवार को

जयपुर। खण्डेलवाल डवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं स्वर्गीय रमेश चंद जी माचीवाल दौसा वाले की स्मृति में माचीवाल परिवार के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 15 मार्च 2026 रविवार को राजस्थान ब्राहम्ण महासभा एस-1 सेक्टर 4 विद्याधर नगर जयपुर में प्रात 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा। सांस्कृतिक सचिव कमल बडाया ने बताया कि मेडिकल केंप में ईको, टीएमटी, ब्लड शूगर, पीएफटी, बीएमडी, बीपी, लिपिड प्रोफाईल, ईसीजी की निशुल्क जांचे की जायेगी।

ब्याई माता का लख्खी मेला आज

लालसोट। क्षेत्र के डिगो गांव की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित ब्याई माता धाम पर बुधवार को आस्था का विशाल सैलाब उमड़ेगा। शीतलाष्टमी के अवसर पर श्रद्धालु घर-घर में बने ठंडे पकवानों का माता रानी को भोग लगाकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसी के साथ प्रसिद्ध ब्याई माता का लख्खी मेला भी भरेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। श्रद्धालु पूड़ी, पकौड़ी और अन्य ठंडे व्यंजन का प्रसाद चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। मेले में धार्मिक आस्था के साथ पारंपरिक आयोजनों की भी धूम रहेगी। कुश्ती दंगल में पहलवान दमखम दिखाएंगे, वहीं नाल उठाने की प्रतियोगिता में युवाओं की ताकत का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा घुड़ दौड़ भी मेले का प्रमुख आकर्षण रहेगी। मेले को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

रोजगार शिविर का आयोजन

कोटपूतली । राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र तथा कौशल नियोजन एवं उद्यिमता विभाग, कोटपूतली-बहरोड़ के संयुक्त तत्वावधान में 21 मार्च 2026, शनिवार को एक दिवसीय विशाल रोजगार शिविर (जॉब फेयर) का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर नारायणपुर स्थित नगरपालिका परिसर के रामलीला मंच पर प्रात: 10 बजे से सायं 4 बजे तक आयोजित होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक भंवर लाल ने बताया कि शिविर में क्षेत्रीय विधायक देवीसिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और चयनित युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।

सावित्री बाई फुले का निर्वाण दिवस मनाया

मनोहरपूर । आज भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले का निर्वाण दिवस पर नालंदा फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम किया गया। यादव महासभा नगर अध्यक्ष मनोहरपुर महेश जड़वाल ने बताया कि फुले दम्पत्ति ने शिक्षा के केंद्र खोलकर अपना सभी कुछ न्योछावर कर दिया। जड़वाल ने कहा कि महिला शिक्षा, वंचित वर्गों के उत्थान और समान अवसरों के लिए उनका क्रांतिकारी योगदान हमारे लिए सदैव प्रेरणास्त्रोत रहेगा। पूर्व सरपंच अर्जुन मोहनपुरिया ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा के साथ तार्किक होना जरूरी है।जब तक महिलाएं समाज सुधार की जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक बदलाव नहीं आ सकता।कार्यक्रम में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता हमीद खान,महेश जड़वाल राकेश सैनी बलराम जाट, रफीक भिस्ती, रामचंद्र सैनी, बनवारी यादव,विकास खटुमरिया राजेन्द्र फर्नीचर, राहुल सैनी व लीलाराम सोंकरिया इत्यादि उपस्थित रहेसभी ने पुष्प अर्पित कर उनसे प्रेरणा लेकर समाज को नई दिशा देने की प्रतिज्ञा ली।

साईकिलें पाकर बालिकाओं के खिले चेहरे

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम पंचायत पवाना अहीर के सेठ मूलचंद प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 09 की 18 बालिकाओं को साईकिलें वितरित की गई। साईकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। अब उन्हें विद्यालय आने जाने में आसानी रहेगी। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जाता है। प्राचार्य भागीरथ सिंह मीणा, प्राचार्य कृष्ण कुमार खजोतिया व प्रवक्ता डॉ. रामकरण यादव सहित स्टॉफ द्वारा बालक-बालिकाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुये अच्छी पढ़ाई कर उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित किया गया।

'राजस्थान दिवस के उपलक्ष में चलने वाले कार्यक्रमों को आमजन से जोड़ते हुए भव्य बनाएं'

- जिलेभर में 15 से 19 मार्च तक जनजातीय गौरव दिवस, युवा शक्ति दिवस, विकसित रन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्विज सहित विविध कार्यक्रमों का होगा आयोजन

खैरथल। खैरथल तिजारा जिले में 15 से 19 मार्च तक चलने वाले राजस्थान दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर आज मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में खैरथल सचिवालय पर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्थान दिवस समारोह के तहत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को तैयारियों के साथ समारोह को भव्य बनाने एवं राजकीय कार्यालय और भवनों पर रोशनी करने के निर्देश दिये।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट ने खैरथल तिजारा जिला सचिवालय पर तैयारियों को लेकर बैठक ली।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया समारोह का औपचारिक शुभारंभ 15 मार्च को राजस्थान को जाने क्विज के साथ होगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में निबंध, भाषण एवं चित्रकारी प्रतियोगिताएं आयोजित की जायेंगी। जिला स्तरीय ओ.डी.ओ.पी. मेले व प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। इसके साथ ही विकसित रन का आयोजन भी किया जाएगा।

कार्यक्रम के दूसरे दिन 16 मार्च को बेणेश्वर धाम, बांसवाड़ा में राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जायेगा, जहां जनसभा एवं प्रतिनिधिगणों के साथ संवाद, विकास कार्यों का शिलान्यास एवं जनजातीय कला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिला स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

तीसरे दिन 17 मार्च को राजस्थान युवा शक्ति दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जहां जयपुर में राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में रोजगार मेले, विकास कार्यों का शिलान्यास किया जायेगा। साथ ही, इस दिन जिलें में राजस्थान को जाने क्विज का आयोजन होगा। इसी दिन सायं 5 बजे उद्योग विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्योगपतियों के साथ संवाद एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए एम्पलॉयमेंट लेटर हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित होगा।

राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य एवं यादगार बनाने के निर्देश दिये जिससे कि आमजन विशेषकर युवाओं का परिचय प्रदेश की समृद्ध लोकसंगीत, नृत्य कला से हो सके।

बैठक के दौरान कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट, संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग वीरेंद्र त्यागी, नगर परिषद आयुक्त मुकेश शर्मा, पुलिस, राजीविका, कृषि, वन, शिक्षा सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

पीड़ित परिवार को मिला संबल

दौसा। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के तहत संचालित सहकारी दुर्घटना बीमा योजना पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने दुर्घटना में मृत एक काश्तकार सदस्य की पत्नी को 10 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि का लाभ प्रदान करते हुए चेक की प्रतिकृति सौंपी।

दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक जितेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि खेड़ली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के काश्तकार सदस्य सूरजपुरा तहसील के मीणा मोहल्ला निवासी स्वर्गीय प्रभुदयाल मीना की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके उपरांत उनकी धर्मपत्नी मोटा देवी को सहकारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई। जिला कलक्टर ने मोटा देवी को सहायता राशि की चेक प्रतिकृति देकर परिवार को संबल प्रदान किया।

भंडारण में सहकारी एम-पैक्स गोदामों को मिले प्राथमिकता : आमेरा

जयपुर। निमोद -डीडवाना बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी सोसाइटी निमोद के विस्तार पटल ग्राम बांसा-निमोद में दो हजार टन और पाँच सो टन भंडारण क्षमता के दो सहकारी गोदाम का विधिवत पूजा अर्चना के साथ भव्य समारोह आयोजित कर लोकार्पण किया गया। समिति अध्यक्ष खेमाराम बुगलिया ने सभी अतिथियों को साफा बाँधकर माला पहनाकर स्वागत किया ।

सहकार पथ प्रेरक सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने निमोद सहकारी समिति के गोदाम का लोकार्पण किया ।

गोदाम लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता विधायक प्रत्याशी महेंद्र सिंह जोधा व विशिष्ट अतिथि सहकार पथ प्रेरक सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा रहे । कार्यक्रम के अन्य विशेष अतिथियों आमंत्रितों में में सुनील छापोला क्षेत्रिय निदेशक एनसीडीसी, मोहित चौधरी डीडीएम नाबार्ड, डा.हरिओम सिंह संयुक्त निदेशक कृषि, विकास शर्मा अभियंता जल भू संरक्षण, शिवजी लाल चोपड़ा अतिरिक्त रजिस्ट्रार, पीथदान चारण सहायक रजिस्ट्रार, पृथ्वीराज सिहाग इफको, अर्जुन सिंह कृषि वैज्ञानिक, निरीक्षक, सुरेश अग्रवाल मुख्य प्रबंधक नागौर सीसीबी, अधिशासी अधिकारी बैंक, भुवनेश्वर प्रसाद, खेमाराम बुगालिया समिति अध्यक्ष, सुभाष आर्य समिति मुख्य सलाहकार , झाबर मल भार्गव व्यवस्थापक, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, पूर्व समिति अध्यक्ष, संचालक मंडल , समिति सदस्य किसान, महिला समूह, ग्रामीण जन और कर्मियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे ।

मुख्य अतिथि महेन्द्र सिंह जोधा व विशिष्ट अतिथि सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के दो हजार टन और राज्य बजट घोषणा के पाँच सो टन सहकारी गोदाम की लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर गोदाम भवन का रिबन खोलकर लोकार्पण उद्घाटन किया गया । उन्होंने बताया कि सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों की उपज ख़रीद करने और उपज को भंडारण के लिए गोदाम सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। निमोद के गोदाम नागौर ,डीडवाना ,कुचामन जिले के किसानों के लिए सौग़ात है। उन्होंने क्षेत्र में सहकारिता से किसानो के विकास और मजबूती के लिए सदैव मदद के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया।

यूजीसी एक्ट के विरोध में 16 मार्च को पावटा में रैली

- सवर्ण समाज यूजीसी एक्ट वापस लेने व सवर्ण आयोग गठन करने की मांग को लेकर सौंपेगा ज्ञापन

पावटा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून के विरोध में पावटा में 16 मार्च सोमवार को सवर्ण समाज द्वारा रैली और प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है व समाजजनों से रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आव्हान किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर भी प्रदर्शन को लेकर लगातार पोस्ट और संदेश साझा किए जा रहे हैं।

समाज के विभिन्न संगठनों और प्रतिनिधियों ने बैठक की।

सवर्ण समाज से एडवोकेट विष्णु पटेल, सुरेश शर्मा, बलदेव गोयल, सवाई सिंह शेखावत, लक्ष्मीकांत शर्मा, योगेश शर्मा, रामशरण बोहरा, नरेंद्र गौड , दीपक पटेल, विकास शर्मा, रतिपाल सिंह, नरेंद्र हुसडा, पंकज जिंदल, अमित पंसारी के अनुसार रैली 16 मार्च आदर्श रामलीला मैदान पावटा से सुबह 10 बजे से शुरू होगी। यहां से रैली मुख्य मार्गो व बाजारों से होते हुए उपखंड कार्यालय पावटा पहुंचेगी।

इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा व ज्ञापन में यूजीसी एक्ट वापस लेने व सवर्ण आयोग गठन करने की मांग की जायेगी।

आयोजकों का कहना है कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। सवर्ण समाज के लोगो का कहना है कि यूजीसी का नया कानून छात्रों के हित में नहीं है और इसे वापस लिया जाना चाहिए।

समाज जनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून पर रोक लगाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस कानून से सामान्य वर्ग के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और प्रतिस्पर्धा की स्थिति प्रभावित होगी। इसी मांग को लेकर रैली और ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है।

क्या अलवर नगर निगम ले रही है शमशान में जलने वाली चिता से कमीशन

- श्मशान पर अवैध टाल मालिक बता रहा है निगम का ठेकेदार
- पोल खुलने पर उपायुक्त ने कहा हमारा कोई ठेकेदार नहीं जांच करेंगे

अलवर । अलवर नगर निगम के अधिकारियों की लूट से अब श्मशान भी सुरक्षित नही रहे है यहां मुर्दे की चिता पर भी निगम के अधिकारियों को कमीशन तय किया जा रहा है यह कहना है प्रताप बंध स्थित श्मशान घाट पर स्थित लकडी विक्रेता का क्योकि वह अपने को नगर परिषद से अधिकृत ठेकेदार बता कर महंगे दाम पर लकड़ी बेच रहा है।

मंगलवार को लादिया मोहल्ला के रहने वाले घनश्याम जादौन के भाई का निधन हो गया था उनके अंतिम संस्कार के लिए लकडी खरीदने के लिए अशोका टाकीज स्थित लकडी की टाल पर जब लोग पहुंचे तो टाल वाले ने यह कह दिया कि भाई लकडी आप ले लो लेकिन श्मशान में नगर निगम के ठेकेदार की टाल है वह आपको वहा लकडी नही ले जाने देगा इसलिए आप वही से खरीद करो जब वहा से लकड़ी खरीदी गई तो लड़कियां पूरी तरह से गीली थी जिस कारण करीब दो घंटे तक चिता ने आग नही पकडी आखिर में जब परेषान होकर लोगों ने चार किलो देषी घी और दस किलो चीनी चिता में डाली लेकिन चिता नही जल पाई।

परेशान होकर कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद गोरी शंकर विजय ने इसकी शिकायत अलवर नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका को फोन कर बताई कि आपकी अधिकृत टाल पर इतनी गीली लकड़ी और बाजार से सात सौ रुपये अधिक दाम पर बेची जा रही है लोग परेशान होते है आप इस पर ध्यान देवे और चिता की वीडियों भी डाली इस पर उपायुक्त नरूका ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा कोई अधिकृत ठेकेदार नही है अगर ऐसा है तो हम उसकी टाल को खाली करवाते है।

नरूका से बात होने के बाद जब टाल मालिक से फोन पर बात की तो उसने अपने को अधिकृत ठेकेदार बताया वही वहा कार्यरत उसके कर्मचारी ने कहा कि साहब हम प्रत्येक चिता की लकड़ी खरीद पर निगम को पांच सौ रुपये का कमीशन देते है।

गर्मियों में पक्षियों के लिए लगाए जाएंगे 20 हजार परिंडे

- निराश्रित पशुओं की सुरक्षा के लिए चलेगा अभियान

दौसा। अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविन्द शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलेभर में पक्षियों के लिए अगले सप्ताह से बड़े स्तर पर परिंडे लगाने के निर्देश दिए गए।

जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविन्द शर्मा ने निर्देश दिए ।

बैठक में विगत बैठक के निर्णयों की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बिंदुवार एजेंडा पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न विभागों को पक्षियों के संरक्षण के लिए विभागवार परिंडे लगाने के लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जिले में करीब 20 हजार परिंडे लगाने तथा उनमें प्रतिदिन पानी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को पाबंद करने के निर्देश दिए।

उन्होंने गर्मियों में पशुओं के लिए भी पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क किनारे घूमने वाले निराश्रित गोवंश पर रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए, ताकि रात्रि के समय सड़क दुर्घटनाएं नहीं हो और पशुओं की हानि को रोका जा सके।

पशु एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं होने तथा दुर्घटनाग्रस्त व बीमार गोवंश को उपचार के लिए ले जाते समय पशु चिकित्सालय की पर्ची के आधार पर टोल से मुक्त नहीं करने पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि घायल पशुओं को तत्काल निकटतम पशु चिकित्सालय में उपचार उपलब्ध कराकर गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए। बैठक में नगर परिषद, नगरपालिकाओं, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परिवहन विभाग एवं पशुपालन विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान चलाने तथा निराश्रित गोवंश को नंदीशाला बीड, दौसा में आश्रय के लिए भिजवाने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद दौसा को आसपास के क्षेत्रों से घायल एवं बीमार गोवंश का उपचार कराकर उन्हें गौशाला एवं नंदीशाला में भेजने तथा पशुपालन विभाग को पात्र गौशालाओं के गोवंश को बाहर नहीं छोड़ने के लिए गौशाला प्रबंधकों को निर्देशित करने को कहा गया।

बैठक में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रहलाद मीणा, उप निदेशक राधेश्याम मीणा, डॉ. राकेश चौधरी, परिवहन विभाग के अधिकारी संदीप भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी तथा जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य अवधेश कुमार अवस्थी एवं गौसेवक सुशील शर्मा उपस्थित रहे।

ग्रामीण श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण

पावटा। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के निर्देशन में उपखंड अधिकारी डॉ. साधना शर्मा ने मंगलवार शाम ग्राम पंचायत भूरी भडाज एवं ग्राम पंचायत पंडितपुरा में संचालित ग्रामीण श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया।

शाम करीब 6 बजे किए गए निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी डॉ . साधना शर्मा ने रसोइयों में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने स्वयं भोजन को टेस्ट कर उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर की जांच की। निरीक्षण में रसोई व्यवस्थाओं, साफ-सफाई तथा भोजन वितरण व्यवस्था को भी देखा गया। निरीक्षण के बाद उपखंड अधिकारी डॉ.साधना शर्मा ने विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण अन्नपूर्णा रसोइयों में आमजन को मिलने वाला भोजन स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए तथा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सार-समाचार

सावित्रीबाई की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

फुलेरा। देश की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की 129वीं पुण्यतिथि पर फुलेरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। माली सैनी समाज संस्थान और सावित्रीबाई फुले संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बिचुन रोड स्थित सावित्रीबाई फुले सर्किल पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान की अध्यक्ष अंजू सैनी ने की। इस अवसर पर तेजकरण सैनी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने विपरीत परिस्थितियों में भी महिलाओं की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किया, जो आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। मुख्य वक्ता सुनीता सैनी ने कहा कि उनके आदर्शों को अपनाकर शिक्षा और समानता का संदेश समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। कार्यक्रम में पूजा भाटी, शेष नारायण सैनी, विनोद कुमार प्रजापति, मूलचंद गरवा, गौरीशंकर प्रजापत, पिंटू गढ़वाल, अजय सैनी, राकेश सैनी, अक्षय कुमार, संतोष, माधुरी सैनी, ललिता शर्मा, दुर्गा देवी, दीक्षा कुमावत, निलेश, मनीष कुमार, गीता सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

नशा मुक्ति विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन

निवाई। राजकीय महाविद्यालय में नशा मुक्ति विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्राचार्य प्रो. मीनाक्षी बघेल की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य वक्ता डीवाईएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने युवाओं पर नशे का दुष्प्रभाव विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक ऐसी सामाजिक बुराई है, जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नष्ट करती है, बल्कि इसके कारण अनमोल मानव जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। उन्होंने कहा कि नशे का आदी होने के बाद व्यक्ति अक्सर अपराध की दुनिया में कदम रख देता है, इसलिए युवाओं को स्वयं के साथ-साथ अपने परिवार को भी इस लत से दूर रखकर जीवन के वास्तविक मूल्य को समझना चाहिए। उन्होंने साइबर क्राइम पर भी विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों की विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं को उनके जीवन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं से अवगत कराते हुए उनसे बचने के प्रभावी उपाय भी बताए। कार्यक्रम के अंत में पुलिस प्रशासन के प्रति सहयोगात्मक भावना रखने वाले विद्यार्थियों के नाम पुलिस मित्र स्वयंसेवकों के रूप में दर्ज किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी रूपा चौधरी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग किया। इस दौरान नई किरण नशा मुक्ति केंद्र योजना के नोडल प्रभारी राजेशकुमार मीणा ने आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

गांव पराना से सिरस तक क्षतिग्रस्त हुआ सडक़ मार्ग

सिरस। गांव पराना से सिरस तक सडक़ मार्ग क्षितग्रस्त हो गया। जिससे वाहन चालकों को दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ है। पूर्व उपसरपंच कैलाश प्रजापत, पूर्व जीएसएस अध्यक्ष श्यामलाल योगी, राकेश योगी, शिवजीलाल जाट, बजरंगलाल प्रजापत व शिवचरण योगी सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि पराना से सिरस तक सडक़ मार्ग क्षितग्रस्त होने के साथ ही सडक़ उखडऩे से जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए। जिससे वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सडक़ की मरम्मत करवाने के लिए करीब 8 माह पहले भी ग्रामीणों ने पराना राजीव गांधी सेवा केंद्र पर धरने प्रदर्शन करके सडक़ मरम्मत करवाने की मांग की थी। प्रशासन मौके पर पहुंचकर समस्या का अवलोकन कर सडक़ को सुधरवाने का आश्वासन दिया था। 8 महीने बाद भी ग्रामीणों की सडक़ की हालत जैसी की जैसी बनी हुई है। वजीराबाद से सिरस तक भी सडक़ कई जगह से टूटी हुई है। सडक़ जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से आवागमन बाधित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पराना से सिरस तक नवीन डामरीकरण करवाने की मांग की है।

मुख्यमंत्री के सम्भावित दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने लिया जायजा

भरतपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सम्भावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, जिला कलक्टर कमर चौधरी, जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनन्द ने अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए सभा स्थल, हेलीपैड एवं अन्य व्यवस्थाओं के लिए स्थान चिन्हित किये। अधिकारियों ने पुलिस परेड ग्राउण्ड में सभा स्थल तथा एमएसजे कॉलेज मैदान में हेलीपैड के लिए स्थान देखकर संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को सभा स्थल पर छाया-पानी, योजनाओं के प्रदर्शन के लिए स्टॉल लगाने, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सभास्थल पर लाने ले जाने तथा बैठक व्यवस्था के संबन्ध में विस्तृत निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री के 18 मार्च को भरतपुर में आने का कार्यक्रम संभावित है, किसान-पशुपालन सम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के साथ विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेगें। निरीक्षण के दौरान आयुक्त बीडीए कनिष्क कटारिया, सीईओं जिला परिषद मृदुल सिंह, अतिरिक्त कलक्टर शहर राहुल सैनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र कुमार, आयुक्त नगर निगम श्रवण विश्नोई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

टीबी मुक्त कार्यशाला आयोजित

टोंक। टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय बीएससी नर्सिंग महाविद्यालय में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला क्षय निवारण केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में नर्सिंग अधिकारियों को टीबी उन्मूलन की बारीकियों और नवीनतम उपचार प्रोटोकॉल का गहन प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. हिमांशु मित्तल ने कार्यशाला में टीबी के विभिन्न प्रकारों और उनके उपचार पर तकनीकी जानकारी साझा की। उन्होने बताया कि सामान्य टीबी (डीएस टीबी) का उपचार पूरी तरह संभव है, बशर्ते दवा का कोर्स बिना किसी रुकावट के पूरा किया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए डॉ. मित्तल ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि होती है, तो उसके परिवार और संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में ही रोग को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि जिले में सीबीनाट और ट्रूनाट जैसी अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, जो सामान्य बलगम जांच की तुलना में कहीं अधिक सटीक और त्वरित परिणाम देती हैं। कार्यक्रम के सफल संचालन में डीपीसी मसर्रत मियां का विशेष सहयोग रहा। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप चौधरी ने जिला क्षय निवारण केंद्र की इस पहल की सराहना की।

बैठक आयोजित

दौसा। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सहकारी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने तथा सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नई पैक्स के गठन की कार्रवाई करने, एनसीडी पोर्टल पर एम-पैक्स से संबंधित डाटा अपलोड करने तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए उनके कंप्यूटरीकरण पर चर्चा की गई। इसके साथ ही डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण, उनके पंजीकरण एवं गठन की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए गए। जिला कलक्टर ने पैक्स को उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में विकसित करने, सभी ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अस्पतालों में सहकारिता की आरजीएचएस योजना के अंतर्गत मेडिकल दुकानें खोलने के लिए भूमि चिन्हित कर दुकानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जब हमने साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के लोग थे। हम ट्रॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत-हिंदुस्तान लाए थे।

- कीर्ति आजाद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने धमाकेदार पारी और टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। संजू ने तीन अहम मुकाबलों में भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। संजू को उनके प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं टीम इंडिया के तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने पर संजू के पिता सैमसन विश्वनाथ ने बेटे के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए बताया कि करियर के शुरुआती दौर में संजू को डिस्टर्ब किया गया था। संजू सैमसन के पिता ने कहा,"मैं अपने बेटे के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। मेरे बेटे को लोगों ने डिस्टर्ब किया। उन्हें काफी परेशान किया।

क्या आप जानते हैं ?... ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में भिड़ेंगे। दोनों टीमें 113 साल पहले भी लॉर्ड्स पर टेस्ट मैच में भिड़ चुकी हैं।

बीसीसीआई 131 करोड़ भारतीय खिलाड़ियों को देगा, प्लेयर के खाते मोटी रकम से भर जाएंगे

नई दिल्ली, 10 मार्च। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर टीम इंडिया के लिए 131 करोड़ रुपए की ईनामी राशि का एलान किया है। इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने पर बीसीसीआई ने टीम को 125 करोड़ रुपए देने का एलान किया था और इस बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ डाला है। बीसीसीआई द्वारा एलान की गई राशि को खिलाड़ी, कोच और अन्य सहायक कर्मचारियों में बांटी जाएगी। 131 करोड़ की राशि में से किसे कितने रुपए मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी सामने आई है। बता दें कि भारत ने रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था।सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम ने न्यूजीलैंड को फाइनल मुकाबले में 96 रनों से हराया और टी20 विश्व कप तीसरी बार अपने नाम किया। अब बीसीसीआई के द्वारा एलान की गई राशि को कैसे बांटा जाएगा ये कंफर्म हो गया है। बीसीसीआई ने इस बात की पूरी जानकारी नहीं दी है कि राशि का बंटवारा कैसे किया जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबित रुपयों को पद के अनुसार बांटा जाएगा। यानी कप्तान, हेड कोच, खिलाड़ियों और अन्य कोच को अलग-अलग राशि दी जा सकती है। इसकी पूरी जानकारी जल्द ही सामने आने की उम्मीद है। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मालामाल हो गई है। बीसीसीआई के एलान से पहले टीम इंडिया को आईसीसी द्वारा प्राइज मनी मिल चुकी है। भारतीय टीम को आईसीसी की तरफ से लगभग 23 लाख अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। भारतीय रुपयों में इसकी कीमत लगभग 21.5 करोड़ रुपए है। भारतीय टीम की जीत के बाद बधाई देते हुए बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, बोर्ड इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों और सेलेक्टर्स को बधाई देता है। हम भविष्य में उनकी निरंतर सफलता की कामना करते हैं।" बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, मैं टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने पर बधाई देता हूं। हम यही चाहते हैं कि वे आगे भी चाहते हैं कि वे सफल हों।"

जसप्रीत बुमराह ट्वंटी-20 कम, वनडे ज्यादा खेलेंगे

2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी पर रहेगा फोकस, वर्कलोड मैनेज करेगा बोर्ड

मुंबई, 10 मार्च। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अब टी-20 सीरीज कम खेलेंगे। वे 2027 वर्ल्ड कप तक ज्यादा वनडे मैच खेलेंगे। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए यह रणनीति बना रहे हैं। ताकि 2027 वर्ल्ड कप के लिए उनकी तैयारी बेहतर हो सके। न्यूज एजेंसी ने के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि अगले कुछ समय में द्विपक्षीय टी20 सीरीज में बुमराह को कम मौके दिए जा सकते हैं।

बुमराह ने 19 नवंबर 2023 के बाद वनडे नहीं खेला। बुमराह ने 19 नवंबर 2023 के बाद कोई वनडे मैच नहीं खेला है। पिछली बार वे वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे क्रिकेट खेलने उतरे थे। अक्टूबर-नवंबर 2027 तक टी20 इंटरनेशनल टीम के लिए कम प्राथमिकता वाला फॉर्मेट माना जा रहा है। इसी दौरान जापान के आइची-नागोया में होने वाले एशियाई खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव कर सकते हैं। अब का अगला टूर्नामेंट 2027 का वनडे वर्ल्डकप होगा। उसी साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेला जाएगा। 2028 में अगला टी-20 वर्ल्ड कप, ओलिंपिक गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल्ड हैं।

सिलेक्शन कमेटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और टीम मैनेजमेंट मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। में बुमराह मुंबई इंडियंस के पेस अटैक की अगुआई करने वाले हैं। 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से बुमराह ने 42 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इनमें 21 टेस्ट और 21 टी20 इंटरनेशनल शामिल हैं।

भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर

चाइनीज ताइपे ने 3-1 से हराया, कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चोटिल, अस्पताल में भर्ती कराया गया

सिडनी, 10 मार्च। भारत विमेंस फुटबॉल एशियन कप से बाहर हो गया है। मंगलवार को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के आखिरी ग्रुप मैच में भारत को चाइनीज ताइपे के खिलाफ 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही टीम का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया।

इस मैच में जीत भारत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम दो गोल के अंतर से जीत दर्ज करनी थी। मुकाबले के दौरान भारतीय कप्तान स्वीटी देवी और गोलकीपर पंथोई चोटिल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

सिडनी में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने लंबे समय तक गेंद पर नियंत्रण रखा और कई मौके भी बनाए, लेकिन अंतिम हिस्से में टीम गोल करने में नाकाम रही। इसी वजह से टीम को हार झेलनी पड़ी और टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। भारत इससे पहले ग्रुप स्टेज में वियतनाम और जापान से भी हार चुका था।

12वें मिनट में चाइनीज ताइपे की बढ़त - मैच के 12वें मिनट में चाइनीज ताइपे ने बढ़त बना ली। संजू के खराब बैक पास के बाद जे डब्ल्यू चेन ने गेंद वाई एच सू को पास की, जिन्होंने खाली गोलपोस्ट में गेंद डाल दी। भारत ने 39वें मिनट में वापसी की। मनीषा कल्याण ने करीब 30 गज दूर से जोरदार शॉट लगाकर गोल किया और स्कोर 1-1 कर दिया।

पेनल्टी से फिर आगे निकला चाइनीज ताइपे - पहले हाफ के अतिरिक्त समय में चाइनीज ताइपे को पेनल्टी मिली। वाई वाई सू का शॉट पोस्ट से टकराया और गोलकीपर पंथोई से लगकर गेंद गोल में चली गई। इससे ताइपे ने 2-1 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में भारत ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन 77वें मिनट में यू चिन चेन ने तीसरा गोल कर मैच लगभग तय कर दिया।

रिंकू सिंह ने पिता के लिए इमोशनल पोस्ट किया, लिखा-

आपने सिखाया था फर्ज सबसे आगे, उसे पूरा करने की कोशिश की

नई दिल्ली, 10 मार्च। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद अपने दिवंगत पिता खानचंद सिंह के लिए इमोशनल पोस्ट किया है। भारत ने रविवार को फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब जीता। यह मैच अहमदाबाद में खेला गया था। 27 फरवरी को रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया था। वह लंबे समय से स्टेज-4 लिवर कैंसर से जूझ रहे थे।

काश आप पास होते रिंकू ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले। मुझे नहीं पता आगे की जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी, पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आगे लिखा, आपने ही सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है, तो मैदान पर सिर्फ आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। आपका सपना पूरा हो गया है, काश आप पास होते। रिंकू वर्ल्ड कप के दौरान मिलने भी गए थे रिंकू के पिता खांचंद सिंह लंबे समय से लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। यह चौथे स्टेज का कैंसर था। पिछले महीने उनकी हालत बहुत खराब हो गई। रिंकू वर्ल्ड कप के दौरान पिता से मिलने घर भी गए थे। लेकिन 27 फरवरी 2026 को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में उनके पिता का निधन हो गया।

नन्हें खा क्रिकेट लीग भदौरिया की जीत में राहुल व भवित के नाबाद शतक

जयपुर, 10 मार्च। चंबल स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित नन्हें खा मेमोरियल क्रिकेट लीग में टॉस जीतकर राजस्थान यूथ ने बल्लेबाजी करते हुए जयंत ताम्बी 35, वरुण 34, रियान अली 39,नितिन सिंघल 24, कैफ गुडेज 41, गौरव पुनिया 17 रनों के सहयोग से 37 ओवर में 210 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भदौरिया एकेडमी की ओर से गेंदबाजी करते हुए राहुल गर्ग 3, राजीव दुखतावा 2, देवांश सिंह ने 1-1 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भदौरिया एकेडमी ने सलामी बल्लेबाज राहुल गर्ग 109, भवित कुमावत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद शतक लगाए और 10 विकेट से टीम को जीत दिलाई। आर. सी. ए. की सीनियर टूर्नामेंट होने के कारण मैच नहीं हो पाए थे, अब मैच चल रहे हैं।

टी-20 वर्ल्डकप फाइनल में अर्शदीप पर जुर्माना

न्यूजीलैंड के मिचेल की ओर गेंद फेंकी थी, मैच फीस का 15 प्रतिशत कटा, डिमेरिट पॉइंट भी मिला

नई दिल्ली, 10 मार्च। टी-20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन के कारण जुर्माना लगाया गया है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल की ओर गेंद फेंकने की घटना के बाद ने उन पर कार्रवाई की। मंगलवार को जारी बयान में अर्शदीप की मैच फीस का 15 काटने के साथ उनके खाते में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया। 8 फरवरी को फाइनल में अर्शदीप ने गुस्से में आकर मिचेल की तरफ गेंद फेंकी थी। जो उनके पैड्स पर लगी थी। यह कार्रवाई की आचार संहिता के लेवल-1 उल्लंघन के मामले में की गई। फाइनल मैच रविवार को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था। इसमें भारत ने 96 रन से कीवी टीम को हराकर लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरा टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनी थी।

मिचेल की कोहनी पर बॉल लगी

न्यूजीलैंड की पारी के 11वें ओवर में अर्शदीप ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड की और वापस फेंकी, जो बल्लेबाज डेरिल मिचेल को लग गई। इसे आचार संहिता के आर्टिकल 2.9 का उल्लंघन माना गया। इस नियम में मैच के दौरान किसी खिलाड़ी की ओर अनुचित या खतरनाक तरीके से गेंद या अन्य उपकरण फेंकने को गलत माना जाता है।

एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला

जुर्माने के साथ अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला मामला है। मैदान पर मौजूद अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स व्हार्फ, थर्ड अंपायर अलाउद्दीन पलेकर और फोर्थ अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने यह आरोप लगाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने जो सजा प्रस्तावित की, उसे अर्शदीप ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। भारत 3 टी-20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश भारतीय टीम 2024 के बाद 2026 में भी चैंपियन बनी और टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई।

इसके साथ ही इंडिया तीन टी-20 वर्ल्ड कप (2007, 2024 और 2026) जीतने वाली दुनिया की पहली टीम भी बन गया। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में जीत के साथ भारत ने पहली बार अपने घरेलू मैदान पर टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीती। इससे पहले टीम ने 2007 में साउथ अफ्रीका और 2024 में वेस्टइंडीज में खिताब जीता था। अब भारत के नाम तीन टी-20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो गई हैं, जबकि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दो-दो बार ही यह खिताब जीत सके हैं।

क्रिकेटर कुलदीप वंशिका संग मसूरी में 7 फेरे लेंगे

14 मार्च को शादी, 17 को लखनऊ में रिसेप्शन, योगी को दिया न्यौता

कानपुर, 10 मार्च। भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ शादी करने जा रहे हैं। दोनों 14 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी में सात फेरे लेंगे। तीन दिन बाद यानी 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी। इस बीच, सोमवार को कुलदीप के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ में योगी को शादी का न्योता दिया। कुलदीप और वंशिका ने 4 जून 2025 को लखनऊ में सगाई की थी, जिसमें क्रिकेटर रिंकू सिंह, प्रिया सरोज समेत कई करीबी लोग शामिल हुए थे। पहले दोनों शादी नवंबर 2025 में तय हुई थी, लेकिन टी-20 विश्व कप की तैयारियों की वजह से तारीख आगे बढ़ा दी गई। अब विश्व कप चैंपियन बनने के बाद कुलदीप नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। टी-20 वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा थे।

पांच ईरानी फुटबॉल खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने शरण दी

राष्ट्रीय गान विवाद के बाद लौटने से इंकार किया, एशियन कप खेलने गई थी खिलाड़ी

नई दिल्ली, 10 मार्च। एशियन कप से बाहर होने के बाद ईरान की महिला फुटबॉल टीम की पांच खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय वीजा देकर अपने देश में रहने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क ने बताया कि इन खिलाड़ियों को पुलिस ने सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है।

दरअसल, पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के खिलाफ मैच से पहले ईरान की टीम ने अपना राष्ट्रगान नहीं गाया था। इसके बाद ईरान में कुछ लोगों ने टीम की आलोचना की और उन्हें सख्त सजा देने की मांग भी की। इसी वजह से खिलाड़ियों ने शरण मांगी थी।। टीम में कुल 26 खिलाड़ी और स्टाफ मौजूद थे, लेकिन फिलहाल सिर्फ पांच खिलाड़ियों ने ही शरण मांगी थी। बाकी खिलाड़ी अभी अपने फैसले पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार ईरान में रहते हैं और उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई का डर है।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पुष्टि की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी पुष्टि की कि इन पांच खिलाड़ियों को मानवीय वीजा दे दिया गया है। इस वीजा के तहत वे ऑस्ट्रेलिया में रह सकती हैं, काम कर सकती हैं और पढ़ाई भी कर सकती हैं। इसी मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो अमेरिका भी इन खिलाड़ियों को शरण देने के लिए तैयार है।

खिलाड़ियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया ऑस्ट्रेलिया में ईरानी टीम को लेकर व्यापक अटकलें लगाई गईं और खबरें भी खूब छपीं जब खिलाड़ियों ने अपने पहले मैच से पहले ईरानी राष्ट्रगान नहीं गाया। मंगलवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया के संघीय पुलिस अधिकारियों ने गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया के एक होटल से पांच महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, क्योंकि उन्होंने शरण के लिए आवेदन किया था।

मंत्री टोनी बर्क ने जानकारी दी वहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के होम अफेयर्स मिनिस्टर टोनी बर्क से हुई और उनके मानवीय वीजा की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह जानकारी मंत्री ने कुछ घंटों बाद ब्रिस्बेन में पत्रकारों को ही। बर्क ने कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह निर्णय प्रत्येक महिला के लिए कितना कठिन रहा होगा, लेकिन निश्चित रूप से कल रात खुशी और राहत का माहौल था। उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय महिलाओं के मुस्कुराते और ताली बजाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए।

मैथ्यू हेडन गुजरात टाइटंस के नए पैंटिंग कोच बने

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर 2026 सीजन के लिए टीम से जुड़े

भोपाल, 10 मार्च। 2026 से पहले गुजरात टाइटंस ने अपनी कोचिंग टीम में बदलाव किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन को टीम का नया बैटिंग कोच नियुक्त किया। हेडन दो बार के वनडे वर्ल्ड कप विजेता हैं और अपने जमाने के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में गिने जाते रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। हेडन की नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब टीम अपनी बैटिंग यूनिट को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश कर रही है। विक्रम सोलंकी बोले- हेडन के आने से युवाओं को फायदा होगा फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट विक्रम सोलंकी ने कहा कि हेडन का अनुभव टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा।

हेडन की नियुक्ति पर बात करते हुए सोलंकी ने कहा,मैथ्यू हेडन का हमारी टीम से जुड़ना एक अहम पड़ाव है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो अनुभव रहा है और युवाओं को निखारने की जो उनकी काबिलियत है, उससे हमारी टीम को अपनी एक अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। आने वाले सीजन के लिए वह हमारी बैटिंग लाइनअप को मजबूत करेंगे। हेडन बोले- हम गुजरात टाइटंस में बैटिंग का नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे अपनी नई जिम्मेदारी पर मैथ्यू हेडन ने कहा,अच्छी बल्लेबाजी वह होती है जो सामने वाली टीम पर दबाव बनाए, लेकिन महान बल्लेबाजी वह है जो पूरे खेल पर अपना कब्जा कर ले। गुजरात टाइटंस में हम बल्लेबाजी का यही स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। हेडन को उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावरप्ले में डोमिनेट करने के लिए जाना जाता है, जो टी-20 फॉर्मेट की सबसे बड़ी जरूरत है।

श्री सीमेंट कप टूर्नामेंट का हुआ आगाज
आरपीसी ने जयगढ़ को हराकर जीता टूर्नामेंट का पहला मैच

जयपुर, 10 मार्च। राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर मंगलवार को श्री सीमेंट कप (आउट ऑफ हैट) टूर्नामेंट का आगाज हुआ। इस टूर्नामेंट की शुरूआत टीम आरपीसी और टीम जयगढ़ के बीच मैच के साथ हुई। इस मुकाबले में टीम आरपीसी 3.5-3 के स्कोर से टीम जयगढ़ को हराकर मैच की विजेता बनी। विजेता टीम आरपीसी से हिज हाइनेस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने 3 गोल किए। टीम से नरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह और जीशान अली मर्चेंट भी खेले। यहां टीम को आधे गोल का एडवांटेज भी प्राप्त हुआ। वहीं, टीम जयगढ़ से विक्रामादित्य सिंह बरकाना, प्रताप सिंह कानोता और एलन शॉन माइकल प्रत्येक ने 1-1 गोल किया। टीम से अश्विनी शर्मा भी खेले। टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 12 मार्च, गुरूवार को राजस्थान पोलो क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा। दूसरा मैच टीम जयपुर और नहारगढ़ के बीच होगा। इस कप का फाइनल 15 मार्च, रविवार को खेला जाएगा।

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक:-स्टोर/2025-26/20915995 दिनांक: 07.03.2026

संशोधित ऑक्शन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा निर्मित विश्वप्रिय शास्त्री चौपाटी की दुकान संख्या 01 से 09 किराये पर दिये जाने हेतु क्रमांक/स्टोर/2025-26/1742 दिनांक 04.02.2026 को सूचना जारी की गयी थी। दिनांक 27.02.2026 को बोर्ड मीटिंग होने के कारण उक्त ऑक्शन को संशोधित किया जा रहा है।

लोहागढ घना चौपाटी विश्वप्रिय शास्त्री पार्क भरतपुर व्यावसायिक दुकानें मय ओपन स्पेस अस्थायी रजिस्ट्रेशन/अमानत राशि/दस्तावेज, जमा करने की कार्यवाही 09.02.2026 से दिनांक 06.03.2026 सायं 06:00 बजे तक निर्धारित थी, जिसको होली अवकाश होने के कारण संशोधित कर दिनांक 13.03.2026 सायं 6.00 तक पढ़ा जावे एवं जिसकी ऑफलाईन नीलामी दिनांक 16.03.2026 दोपहर 03:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय सभागार में आयोजित की जावेगी।

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

1. WAQ2526SSOB00312

राज.संवाद/सी/25/22110 सचिव

कार्यालय नगर परिषद, तिजारा (खैरथल-तिजारा) राज.

Email ID :-tijara.jaipur@gmail.com Ph. No. 01469-262032 (O),

क्रमांकः- न.प.ति./2025-26/2788 दिनांकः- 06.03.2026

ई-निविदा सूचना- 17/2025-26

केन्द्र एवं राज्य सरकार में उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर पालिका/परिषद/निगम/स्वायत्त शासन विभाग के निविदाताओं से आयुक्त द्वारा सम्बन्धित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राजस्थान सरकार के पोर्टल Website:- https://sppp.rajasthan.gov.in एवं https://eproc.rajasthan.gov.in की बेवसाइट पर देखी एवं download कर प्राप्त की जा सकती है।

स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट का NIB Code DLB2526B2524 है। आयुक्त

राज.संवाद/सी/25/22097 नगर परिषद तिजारा

कार्यालय नगरपालिका सादड़ी (पाली) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.सा./2026/5441-5443 दिनांक 06.03.2026

-::कोरीजेण्डम ई-निविदा सूचना ::-

एतद् द्वारा समस्त पंजीकृत संवेदको को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सादड़ी द्वारा जारी ई-निविदा सूचना क्रमांक/न.पा.सा./2025-26/5151-5153 दिनांक 10.02.2026 को आमंत्रित की गई थी। उक्त ई-निविदा में किसी भी संवेदक द्वारा भाग नही लिये जाने से ई-निविदा में निम्नानुसार दिनांक बढाई जाती है। शर्तें यथावत रहेगी। सूचित रहे।

ऑनलाईन ई-निविदा भरने हेतु अन्तिम दिनांक व समय	16.03.2026 समय सांय 6.00 बजे तक
मूल दस्तावेज, डी.डी. जमा कराने की अंतिम तिथि	17.03.2026 समय दोपहर 1.00 बजे तक
ई-निविदा खोलने की दिनांक व समय	18.03.2026 समय दोपहर 4.00 बजे तक

राज.संवाद/सी/25/22060 अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सादड़ी

DIRECTOR WORKS (EO)

Rajasthan University Of Veterinary & Animal Science, Bikaner

क्रमांक : F( )/DW(EO)/RAJUVAS/2025-26/1038 - 1044 दिनांक :- 07/03/2026

निविदा सूचना संख्या 12 वर्ष 2025-2026

राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की ओर से विश्वविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी में, इस विश्वविद्यालय में एवं अन्य विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों तथा केन्द्र सरकार व केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों, जो कि राज्य सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो, पंजीकृत संवेदको से ई-टेन्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा प्राप्त की जावेगी। निविदा से सम्बधित विवरण वेब साईट www.dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp, www.rajuvas.org, www.sppp.rajasthan.gov.in व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। UBN No. : VAU2526SLOB00138

राज.संवाद/सी/25/22112 भू-सम्पदा अधिकारी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः- 1286 दिनांकः- 06.03.2026

ई-निविदा सूचना

UBN NO. DLB2526WSOB37121

नगर निगम जोधपुर के जोन नं 1, 5 एवं 8 एवं अन्य क्षेत्रों में सेवाएं एवं अनुरक्षण कार्य हेतु निविदाएँ अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई-निविदा प्रक्रिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in, https://lsg.rajasthan.gov.in/nnjodhpur एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

राज.संवाद/सी/25/22152 नगर निगम, जोधपुर

कार्यालय नगरपालिका उनियारा (टोंक) राज.

क्रमांक/न.पा.उ./ स्टोर/2025-26/4410 दिनांक : 06.03.2026

निविदा सूचना

नगरपालिका उनियारा (टोंक) द्वारा नगर निकाय उनियारा एवं स्वायत्त शासन विभाग के समुचित वर्ग के सूचीबद्ध ठेकेदारों/संवेदको एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनो में सक्षम क्षेणी के संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म एवं निविदा से सम्बन्धित विवरण व शर्तें वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

NIB NO- DLB2526B2539

राज.संवाद/सी/25/22082 अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका उनियारा (टोंक)

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दूरभाष सं.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www-udaipurmc.org

क्रमांक : निविजा/2025-26/ई -40 दिनांक :- 06.03.2026

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 40/2025-26

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यो हेतु कुल राशि रु0 25.00 लाख के कुल 01 कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है निविदा के कार्यो की प्रारम्भ तिथि 07.03.2026 एवं अंतिम तिथि 16.03.2026 तथा निविदा खुलने की तिथी 17.03.2026 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।

UBN No. UNP2526WSOB00167

राज.संवाद/सी/25/22148 अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, उदयपुर

मंत्री 5 साल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचें- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक दल की बैठक में सक्रिय विधायकों की सराहना की

जयपुर, 10 मार्च। मुख्यमंत्री ने 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सदन में सक्रिय और प्रभावी प्रदर्शन करने वाले विधायकों की सराहना करते हुए कहा कि जनहित के मुद्दों को इसी तरह मजबूती से उठाते रहें।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आव्हान किया।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र के अंतिम दिन भाजपा विधायक दल की बैठक ली। विधानसभा के 'हां पक्ष' लॉबी में आयोजित इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में विधायकों के कामकाज पर लगातार नज़र रखी जाती है और जनप्रतिनिधियों पर 'तीसरी आंख' भी रहती है, इसलिए सभी को अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विधायकों ने जो भी मांगें रखीं, सरकार ने उन्हें पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी जनप्रतिनिधियों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए कि पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचना जरूरी है। मंत्री और जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएं और कम से कम आठ से दस घंटे क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में आगामी के कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में बढ -चढ़ कर भाग लेने का आव्हान किया।

'गैस के दाम बढ़ा दिए पर आपूर्ति नहीं हो रही है'

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 10 मार्च। कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने मंगलवार को गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि वह गैस संकट को लेकर कुछ तथ्य छिपा रही है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर पड़ना ही है, इसलिए सरकार को इससे निपटने के लिए अग्रिम तैयारी करनी चाहिए थी।

- **कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा, गैस सप्लाई में कमी के लिए सरकार ने पूर्व तैयारी क्यों नहीं की।**

राजस्थान के नेता ने कहा कि सरकार ने गैस की कीमतों में वृद्धि तो कर दी, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की, जिसका सीधा असर आम लोगों के साथ-साथ, होटलों और रेस्तरां पर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि अगर आने वाले वर्षों में वैश्विक स्थिति ऐसी ही रहती है, तो पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। उन्होंने सरकार से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

संसद में सरकार के बयान पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि शांति के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और सरकार की पहली प्राथमिकता उनके संरक्षण के लिए होनी चाहिए।

प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली

बम निरोधक दस्तों व डॉग स्क्वॉड के साथ पुलिस ने सघन चैकिंग की

जयपुर, 10 मार्च। राजधानी जयपुर में मंगलवार को पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। भारत सरकार का पासपोर्ट सेवा केन्द्र (ऑर्बिट मॉल) और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर (झालाना) को ई-मेल के जरिए गैस बम से विस्फोट करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया था।

सूचना मिलते ही, राजस्थान पुलिस, एटीएस और बम डिफ्यूज टीम मौके पर पहुंच गईं और दोनों कार्यालयों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालयों में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों को बाहर निकाल दिया गया तथा एंट्री अस्थायी रूप से बंद कर दी गई।

जानकारी के अनुसार, धमकी भरा ईमेल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मिला, जिसमें दोपहर 1:10 बजे ब्लास्ट होने की बात लिखी गई थी। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाही करते हुए कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। करीब एक घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

- **एहतियात के तौर पर सभी पासपोर्ट कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई।**

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इसे फर्जी ई-मेल मानकर जांच कर रही हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

अधिकारियों के अनुसार, मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और ईमेल भेजने वाले स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है।

इसी तरह, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, सीकर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ , डुंगरपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ , श्रीगंगानगर, झालावाड़, अलवर, दौसा, भरतपुर जिलों में भी पासपोर्ट कार्यालयों को धमकी का ई-मेल मिला। सूचना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्तों, सिविल डिफेंस, डॉग स्क्वॉयड को बुलाया गया। हालांकि सर्च में कहीं भी संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है।

विपक्ष ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ईरान पर अमेरिका और इज़राइल के हमले तथा पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की संभावना है। इन घटनाओं के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की नीति पर सवाल उठा सकता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों द्वारा सदन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाये जाने की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शनिवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से जुड़े कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला उठा सकती है। इस बीच सरकार बजट सत्र के शेष हिस्से के दौरान बिजली संशोधन विधेयक पेश कर सकती है तथा सत्र के पूर्वाद्ध के कई लंबित विधायी कार्यों को भी ले सकती है। कार्यसूची के अनुसार, लोकसभा में चर्चा के लिए अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव ही सूचीबद्ध है।

ट्रंप ने पुतिन से लंबी वार्ता की

चर्चा है कि वार्ता ईरान जंग रूकवाने के बारे में थी

- **विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि ईरान वॉर रूकवाने के कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए हैं।**

वाशिंगटन/मॉस्को, 10 मार्च। अमेरिका-इज़राइल के ईरान के साथ जारी युद्ध और मध्य पूर्व में चरम पर पहुंचे तनाव को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू होने के शुरुआती संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सैन्य अभियान शुरू होने के बाद पहली बार सोमवार रात (इंडियन स्टैंडर्ड टाइम) रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलिफोन पर लंबी बातचीत की। दोनों ने करीब साठ मिनट तक चर्चा की। कहा जा रहा है कि वार्ता का अधिकांश हिस्सा ईरान पर केंद्रित रहा। ट्रंप ने अपने समकक्ष से यूक्रेन जंग पर भी कुछ समय तक चर्चा की।

द मॉस्को टाइम्स, अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस, द वॉल स्ट्रीट जनरल और द टाइम्स (लंदन) की रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों नेताओं की वार्ता पर क्रेमलिन ने बयान भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि सोमवार को यह वार्ता करीब एक घंटे तक चली।

पुतिन के हवाले से क्रेमलिन प्रवक्ता ने बयान में कहा कि ट्रंप ने अपने समकक्ष से ईरान युद्ध को जल्दी सुलझाने के लिए कई प्रस्ताव रखे। पुतिन ने कहा वह खाड़ी नेताओं के साथ-साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के संपर्क में हैं। क्रेमलिन ने कहा कि दोनों ने वेनेज़ुएला और ऊर्जा उद्योग के बारे में भी बात की।

एक रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने पुतिन से ईरान और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा की। एक्सियोस का आकलन है कि रूस ईरान का अहम साथी है। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि रूस इस युद्ध में ईरानियों की मदद कर रहा है। हालांकि ट्रंप ऐसा नहीं मानते पर वाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि रूस को ईरान के साथ कोई भी खुफिया सूचना नहीं बांटनी चाहिए।

पुतिन की विदेश नीति के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि दोनों के बीच बातचीत बेहद साफ और आपसी हितों पर केंद्रित रही। उन्होंने दावा किया कि पुतिन ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप को कई प्रस्ताव दिए।

इस घटनाक्रम के बीच ईरान के उप विदेशमंत्री काजम गरीबाबादी के हवाले से एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने युद्धविराम की शर्तों के लिए उनसे संपर्क किया है। गरीबाबादी ने ईरान के सरकारी ब्राडकॉस्टर प्रेस टीवी पर कहा कि फ्रांस, चीन और रूस ने शांति प्रस्ताव की शर्तों पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया है। गरीबाबादी की घोषणा के कई घंटे बाद ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, उनकी "पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।"

ट्रंप ने कहा, "मैंने पुतिन से कहा कि आप मेरी युक्रेन में युद्ध खत्म कराने पर मदद लीजिए। साथ ही आप ईरान के साथ युद्ध बंद कराने में मददगार बनें।" पुतिन के करीबी उशाकोव ने यह भी कहा कि दोनों ने तेल बाजार में कीमतों में तेजी पर भी चर्चा की।

राज्यपाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आईसीयू 2 में भर्ती किया गया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर भी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक, राज्यपाल को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही किडनी में थोड़ी समस्या को देखते हुए यहां जनरल मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी की टीम की देखरेख में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहीं, राज्यपाल के यूरिन और ब्लड की दोबारा सैंपलिंग कराकर उन्हें टैस्टिंग के लिए भिजवाया है। राज्यपाल के ट्रीटमेंट के लिए 7 से ज्यादा डॉक्टरों की टीम का एक मेडिकल बोर्ड बनाया है। इसमें जनरल मेडिसिन, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी तथा कार्डियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर्स है।

बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठिया मारा

चंडीगढ़ , 10 मार्च। बीएसफ ने सीमा पार से हो रही तस्करी की कार्रवाई को असफल बनाते हुए, तरनतारन के खेमकरण सेक्टर में हेरोइन तस्करी का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढे र कर दिया। इस संबंध में पाकिस्तान को सूचित किया गया है, लेकिन वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है।

घुसपैठ करते पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया

राजौरी, 10 मार्च। सेना के जवानों ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश करते एक आतंकवादी को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया।

- **अवैध रूप से नियंत्रण रेखा पार करते समय सुरक्षाबलों ने उन्हें निशाना बनाया।**

व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि खुफिया सूचनाओं पर कार्रवाई करते हुए, सुरक्षा बलों ने दोपहर करीब तीन बजे एलओसी के पास नौशेरा सेक्टर के झंगड़ के सामान्य इलाके में दो आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया।

गोलीबारी होने पर एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया, जिससे नियंत्रण रेखा के किसी भी उल्लंघन को प्रभावी ढ ंग से रोका जा सका। दूसरे आतंकवादी का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह इलाके में छिपा हुआ है।

'राहुल निडर हैं, बेझिझक सच बोलते हैं'

प्रियंका गांधी ने संसद में यह भी कहा कि राहुल गांधी ही एक मात्र नेता है जिन्होंने 12 साल में एक बार भी सरकार के सामने सिर नहीं झुकाया

- **प्रियंका ने यह टिप्पणियां तब की जब संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू ने कहा राहुल की जगह प्रियंका बेहतर नेता प्रतिपक्ष होतीं।**

नई दिल्ली, 10 मार्च। लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सवाल उठाए और प्रियंका गांधी को राहुल से बेहतर बताया। इस पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती रहीं। इसके बाद रिजिजू ने उनके मुस्कुराने का जिक्र कर पंडित नेहरू का कथन उद्धृत किया। इस पर प्रियंका ने राहुल को निडर नेता बताया।

रिजिजू ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता क्यों बनाया गया, जबकि वे गंभीर नहीं हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा बेहतर विपक्ष की नेता होतीं। रिजिजू के इस बयान पर प्रियंका मुस्कुराती हुई अपनी सीट से खड़ी हो गईं।

प्रियंका ने कहा, "मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि आज उन्होंने पंडित नेहरू का कथन अपने पक्ष में इस्तेमाल किया, जिनकी वे दिन-रात आलोचना करते हैं। आज रिजिजू ने पंडित नेहरू के उस कथन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही थी।"

'हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं'

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने अमेरिका की कहर बरसाने की धमकी पर जवाब दिया

- **उन्होंने ईरान 6 हजार साल पुरानी सभ्यता है कई हमलावरों ने इसे खत्म करने की कोशिश की पर वे सफल नहीं हो सके।**

तेहरान/वॉशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के 11 वें दिन तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर अब तक के सबसे बड़े और सबसे तीव्र हमले किए जा सकते हैं। इसके जवाब में ईरान के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि देश किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने कहा कि कोई भी ताकत ईरान को मिटा नहीं सकती। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान कम से कम छह हजार साल पुरानी सभ्यता का वारिस है और इतिहास में कई आक्रमणकारियों ने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उनके मुताबिक जो लोग ईरान को खत्म करने का सपना देखते हैं, वे इतिहास को नहीं समझते।

वहीं, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी जनता किसी भी धमकी से नहीं डरती। उन्होंने कहा कि पहले भी कई शक्तिशाली ताकतों ने ईरान को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं।

लारीजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परोक्ष संदेश देते हुए कहा कि जो लोग ईरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, उन्हें अपने अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके अनुसार इतिहास गवाह है कि ईरान पर हमला करने वाले कई आक्रमणकारी समय के साथ खत्म हो गए, लेकिन ईरान कायम रहा।

पदीय कर्तव्य ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिसर में घुसे और दीवार और गेट को तोड़ दिया। यह कार्रवाही तत्कालीन अधिकारी के निर्देश पर हुई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन बाद में एफआर पेश कर दी। इसके खिलाफ दायर प्रोटेस्ट पिटिशन पर अदालत ने 10 फरवरी, 2010 को याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रसंज्ञान ले लिया। इसके खिलाफ दायर रिवीजन पर भी कोर्ट ने यह आदेश बहाल रखा। इसे चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया कि यह कार्रवाही सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर की गई थी और जेडीए में प्रवर्तन अधिकारी होने के कारण उन्हें इसका अधिकार था। ऐसे में उन्हें सीआरपीसी की धारा 197 के तहत संरक्षण प्राप्त है।

'होर्मुज़ स्ट्रेट रोका तो ईरान पर कहर बरसेगा'

अमेरिका ने होर्मुज़ स्ट्रेट रोकने के लिए ईरान को कड़ी चेतावनी दी

वॉशिंगटन, 10 मार्च। अमेरिका ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आपूर्ति बाधित करने की कोशिश की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि अगर ईरान इस अहम समुद्री मार्ग से तेल के प्रवाह को रोकने का प्रयास करता है, तो अमेरिका उसे कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा।

हेगसेथ ने कहा कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी स्पष्ट कर दिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में तेल आपूर्ति रोकने की किसी भी कोशिश का कड़ा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में ईरान पर मौत, आग और कहर बरसेगा। यह बयान उस समय आया है जब अमेरिकी सैन्य अभियान "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी" को लेकर नई जानकारी साझा की गई। इस दौरान जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने बताया कि अमेरिकी सेना क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा और संभावित सैन्य विकल्पों का आकलन कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब तक ईरान के मिसाइल, नौसैनिक और सैन्य ढ ांचे से जुड़े 5,000 से अधिक लक्ष्यों पर हमले किए जा चुके हैं।

- **ज्ञातव्य है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण है और यह मार्ग समुद्र में जहाजों के परिवहन के लिए बहुत जरूरी है।**

अपने फायदे के लिए विभिन्न देशों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोल्ड वॉर के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका सत्ता परिवर्तन अभियानों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल हुआ। वर्ष 1953 में, सीआईए ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ की सरकार को उखाड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था।

इस ऑपरेशन ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में बहाल किया। शाह का शासन कुछ समय के लिए स्थिरता लाया और वॉशिंगटन के साथ करीबी संबंध बनाए। तानाशाही शासन और विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ आक्रोश ने अंतत: 1979 में इस्लामिक क्रांति का रूप लिया, जिसने राजतंत्र को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया और ईरान को अमेरिका के प्रमुख विरोधियों में से एक बना दिया।

वर्ष 1954 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाटेमाला में एक तख्तापलट को समर्थन दिया, जिसने लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेन्स को उखाड़ फेंका। वॉशिंगटन उसके द्वारा किए गए भूमि सुधारों और लेफ्टिस्ट रुझानों को अमेरिका के लिये खतरा मानता था। इस तख्तापलट ने सैन्य शासन की शुरुआत की और दशकों लम्बे नागरिक संघर्ष और दमन को जन्म दिया, जिसके कारण ग्वाटेमाला राजनीतिक रूप से कई वर्षों तक अस्थिर रहा।

वर्ष 1961 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा में फिडेल कास्त्रो की सरकार को उखाड़ने का प्रयास किया, जिसे असफल बे ऑफ पिग्स आक्रमण के जरिए अंजाम दिया गया था, ऑपरेशन सीआईए द्वारा प्रशिक्षित क्यूबा के निर्वासितों ने किया था। यह ऑपरेशन न केवल विफल हो गया, बल्कि कास्त्रो की स्थिति मजबूत हुई, साथ ही क्यूबा सोवियत संघ के साथ और अधिक मजबूती से जुड़ गया, जिससे शीत युद्ध के तनावों में वृद्धि हुई।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1965 में डोमिनिकन गणराज्य में भी सैन्य हस्तक्षेप किया, ताकि वह सिविल वॉर को रोक सके वॉशिंगटन को लगता था कि यह वॉर वामपंथियों के नियंत्रण में जा रहा था। अमेरिकी सैनिकों ने एक और अधिक रूढ़िवादी सरकार की स्थापना में मदद की। हालांकि इस हस्तक्षेप ने कुछ हद तक व्यवस्था बहाल की, तथा देश में तानाशाही राजनीतिक संरचनाओं को भी लंबा किया।

वर्ष 1973 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिली की सेना के तत्वों का समर्थन किया, जिन्होंने समाजवादी राष्ट्रपति सल्वाडोर अलेंडे की सरकार को उखाड़ फेंका। इस तख्तापलट के बाद जनरल अगस्तो पिनोचेट को सत्ता में लाया गया। पिनोचेट के शासन के तहत चिली ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक पुनर्गठन का अनुभव किया, लेकिन इसके साथ ही व्यापक मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हुआ। देश अंतत: 1990 में लोकतंत्र में वापस लौट आया।

वर्ष 1980 के दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने दो और देशों में सीधे सैन्य हस्तक्षेप किए। वर्ष 1983 में, अमेरिकी बलों ने ग्रेनेडा पर आक्रमण किया, जहां एक मार्क्सवादी सरकार के भीतर आंतरिक उथल-पुथल के बाद हुए इस हस्तक्षेप से शासक जुंटा को हटा दिया गया और चुनावों और अपेक्षाकृत स्थिर लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

वर्ष 1989 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा पर आक्रमण किया, ताकि सैन्य शासक मैनुएल नोरेगा को हटाया जा सके, जो अमेरिका में ड्रग तस्करी के आरोपों में अभियुक्त थे। नोरेगा को गिरफ्तार किया गया और पनामा ने बाद में एक स्थिर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया।

कोल्ड वॉर के बाद के युग में, शासन परिवर्तन युद्ध और भी विवादास्पद हो गए। 11 सितंबर के हमलों के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तालिबान शासन को उखाड़ फेंका, जो अल-कायदा को शरण दे रहा था।

हालांकि काबुल में एक नई सरकार स्थापित की गई, लेकिन देश दो दशकों तक संघर्ष में डूबा रहा। वर्ष 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद, तालिबान सत्ता में वापस आ गया, जिससे हस्तक्षेप की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर सवाल उठे।

वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण का उद्देश्य सद्दाम हुसैन को हटाना और कथित रूप से विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना था। सद्दाम का शासन खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद कई सालों तक विद्रोह, संप्रदायिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा, जिसमें चरमपंथी समूह का उभार हुआ। इराक ने अंतत: एक निर्वाचित सरकार स्थापित की, लेकिन देश अभी भी राजनीतिक और सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रहा है।

एक और विवादास्पद हस्तक्षेप 2011 में लीबिया में हुआ, जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित नाटो के नेतृत्व में एक अभियान ने अरब स्प्रिंग के दौरान मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंका। हालांकि इस हस्तक्षेप ने लंबे समय तक शासन करने वाले नेता को हटाने में सफलता प्राप्त की, लीबिया इसके बाद प्रतिद्वंद्वी मिलिशिया और प्रतिस्पर्धी सरकारों के बीच गुटीय संघर्ष में डूब गया, जिससे देश भारी अस्थिरता का शिकार हो गया।

इन घटनाओं को एक साथ देखा जाए, तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक लगातार बनी हुई दुविधा को दर्शाता है। सैन्य हस्तक्षेप अक्सर शासन को जल्दी हटा सकता है, लेकिन इसके बाद स्थायी राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना कहीं अधिक जटिल है। कई मामलों में ईरान, ग्वाटेमाला, अफगानिस्तान, इराक और लीबिया से लेकर-शासन परिवर्तन के दीर्घकालिक परिणामों ने अस्थिरता पैदा की है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक भू-राजनीति को आकार देती रही है।

क्या अमेरिका ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट में कहा गया है कि, अभियान को जारी रखने के लिए वाइट हाउस इस सप्ताह अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग कर सकता है, जो दसियों अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, इसके साथ ही, यह भी उम्मीद की जा रही है कि इज़रायल और अमेरिका हथियारों के इस्तेमाल में बदलाव करते हुए, लेज़र-गाइडेड बमों का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन देशों के पास ऐसे हथियारों का बड़ा भंडार है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने कहा कि विभाग के पास राष्ट्रपति द्वारा चुने गए समय और स्थान पर किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए जरुरी, हर चीज मौजूद है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने हाल ही में तेहरान को हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से तेल की आपूर्ति को बाधित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर ईरान ऐसा कुछ करता है, जिससे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल का प्रवाह रुकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका बीस गुना ज्यादा कठोरता से जवाब देगा।

उन पर मौत, आग और गुस्से की बारिश होगी। लेकिन मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो।"

बंद हो सकते हैं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में संचालन संबंधी एक और झटका (ऑपरेशनल शॉक) आर्थिक रूप से कमजोर व्यवसायों को दिवालिया बना सकता है।

उद्योग के नेता सरकार से अपील कर रहे हैं कि स्थिति और बिगड़ने से पहले जल्दी हस्तक्षेप किया जाए। एक तत्काल कदम यह हो सकता है कि आतिथ्य क्षेत्र के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की "न्यूनतम सुनिश्चित आपूर्ति" पक्की की जाए, ताकि रेस्तरां अपना काम जारी रख सकें। कम जरूरी कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से स्टॉक को कुछ समय के लिए हटाना, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और वितरकों के बीच बेहतर तालमेल, और प्रभावित शहरों तक तेज़ आपूर्ति व्यवस्था करना, दबाव कम करने में मदद कर सकता है। लंबे समय में यह संकट इस बात को भी उजागर करता है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में व्यवधान आने पर आतिथ्य क्षेत्र कितना असुरक्षित है। नीति-निर्माताओं को बड़े शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क का विस्तार तेज़ करना पड़ सकता है और व्यावसायिक रसोइयों को ईंधन के अलग-अलग स्त्रोत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, ताकि वे पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर न रहें। अभी के लिए समस्या बहुत बड़ी और तात्कालिक है। यदि व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति जल्द स्थिर नहीं हुई, तो कई रेस्तरां की रसोइयां बंद करनी पड़ सकती हैं। पश्चिम एशिया में शुरू हुआ संघर्ष अब भारत के शहरों में भी असर दिखाने लगा है, बिलकुल वहीं, जहां देश खाना बनाता है और खाता है।

जिष्णु देव वर्मा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नार्वेकर, विधान परिषद की उपसभापति डॉ.नीलम गोऱ्हे, पूर्व मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ ा, मुंबई नगर निगम के आयुक्त भूषण गगराणी, पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती, मुख्य राज्य शिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे सहित, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908